जबलपुर नगरीय निकाय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं का विश्लेषण

डॉ. जयश्री दीक्षित, रितु मिश्रा

जबलपुर नगर निगम जिसकी वर्तमान जनसंख्या 14 लाख है, जोकि 119.31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरे इस शहर में 5 बड़े नाले – ओमती नाला, मोती नाला, उर्दना नाला, शाह नाला, खंदारी नाला विद्यमान है जिसमें सम्पूर्ण शहर के वर्षा, जल एवं गंदे पानी की निकासी प्रमुख रूप से होती है, तथा पेयजल आपूर्ति के लिए माँ नर्मदा का स्वच्छ जल उपलब्ध है, साथ ही खंदारी जलाशय, परियट जलाशय से भी शहर में जलापूर्ति होती है। शहर की बसाहट अधोसंरचना के अभाव में बेतरतीब ढंग से है जिसमें अत्याधिक घनी आबादी पहाड़ी क्षेत्र के नागरिकों की पहचान है एवं तीज त्यौहारों को विशेष रूप से सभी सांप्रदायिक लोग मिल–जुल कर मनाते हैं, जिसके कारण ही इसे संस्कारिक शहर संस्कारधानी कहा जाता है। माँ नर्मदा की विशेष कृपा होने के कारण भेड़ाघाट धुआँधार जलप्रपात के रूप में इस शहर में अपना स्थान विश्व के नक्शे में अंकित किया है तथा कान्हा अभ्यारण्य के कारण पर्यटन के क्षेत्र में भी शहर की विशेष भूमिका है।

जबलपुर नगरपालिका क्षेत्र को स्वच्छ, सुन्दर रखने के साथ ही यहाँ निवास करने वाले नागरिकों को स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्रदान करने का दायित्व निगम के स्वास्थ्य विभाग के ऊपर है। इस हेतु नगर निगम के जो आवश्यक कर्त्तव्य हैं उनमें नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए पर्याप्त संख्या में व सुविधायुक्त चिकित्सालयों का संचालन करना, नगर पालिका क्षेत्र में उत्तम सफाई व्यवस्था, मल–जल एवं वर्षाजल की निकासी की व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट के परिवहन व निपटान की व्यवस्था, आवारा पशुओं पर नियंत्रण करना, सार्वजनिक शौचालयों–मूत्रालयों की व्यवस्था करना, शव वाहन व दहन की व्यवस्था करना, मच्छरों–कीटों–मकोड़ों पर नियंत्रण करना, प्रदूषण फैलाने वाले सभी कारणों पर नियंत्रण रखना, मृत पशुओं के निराकरण की व्यवस्था करना, कीटनाशक दवाईयों का छिड़काव करना, कचरा फैलाने वालों पर कठोर कार्यवाही करना, पेयजल की पर्याप्त और नियमित व्यवस्था करना, गंदी बस्तियों का व्यवस्थापन करना एवं जल–मल निकासी के लिए भूमिगत नालियों की व्यवस्था करना इत्यादि। ये सभी कार्य जबलपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं। इस विभाग की गतिविधियों का संक्षेप में विवरण इस प्रकार हैः–

चिकित्सालयों–औषधालयों का संचालन : नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने तथा उन्हें आवश्यक औषधियाँ समय पर उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम द्वारा अनेक चिकित्सालय एवं औषधालय संचालित किए जा रहे हैं। यद्यपि समय के साथ विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने और नई नियुक्तियाँ नहीं होने के कारण इन चिकित्सालयों के संचालन में अव्यवस्था हो रही है, तथापि समस्या का त्वरित निदान करने के उद्देश्य से संविदा नियुक्तियाँ की जा रही हैं एवं यथाशीघ्र नियमित नियुक्तियों की योजना है। आय–व्ययक 2013–14 के अनुसार नगर में संचालित चिकित्सालयों में पर्याप्त व्यवस्थाओं के साथ–साथ चिकित्सकों की पदस्थापना कर दी गई है तथा उनका सुचारू रूप से संचालन होने लगा है।

जबलपुर नगरपालिका निगम के क्षेत्रांतर्गत शासकीय और निजी 100 से अधिक चिकित्सालय व नर्सिंग होम्स के अतिरिक्त अनेक डायग्नोस्टिक सेंटर्स, एक्स–रे तथा पैथालिजी सेंटर्स है।

कीटनाशक दवाइयों का उपयोग

जनस्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग दूसरा बड़ा एवं महत्वपूर्ण कार्य कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करता है। नगर निगम क्षेत्र में मलेरिया एवं मच्छरों से उत्पन्न होने वाली तथा अन्य संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु नगर निगम जबलपुर द्वारा फॉगिंग मशीनों, पॉवर स्प्रेयर मशीनों एवं हेण्ड स्प्रेयर मशीनों के द्वारा मच्छरों के विनिष्टीकरण हेतु लगातार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जाता है।

चूँकि वर्तमान में नगर निगम सीमा क्षेत्र में वार्डों की संख्या 79 हो गई है तथा सीमा क्षेत्र में भी वृद्धि हो गई है अतः मलेरिया नियंत्रण कार्य हेतु कीटनाशकों का छिड़काव सघन रूप से होता रहे।

सामुदायिक शौचालयों–मूत्रालयों की व्यवस्था एवं संधारण

नागरिकों की सुविधा के लिए अनेक स्थलों पर 200 से अधिक सामुदायिक शौचालय तथा लगभग 300 स्थलों पर मूत्रालयों का निर्माण कराया गया है। बढ़ती

जनसंख्या के कारण ये सुविधाएँ पर्याप्त नहीं हैं इसलिए निगम द्वारा आगामी वर्ष में 33 शौचालयों तथा 10 मूत्रालयों का निर्माण किया जाएगा। इनकी सफाई एवं संधारण व्यवस्था निगम द्वारा संविदा पर कराई जाती है। निगम इन सुविधाओं में प्रतिवर्ष और अधिक वृद्धि करने हेतु प्रयासरत है।

चलित शौचालयों की व्यवस्था

नगर निगम में विभिन्न सार्वजनिक आयोजनों में मोबाइल टायलेट्स की आवश्यकता पड़ती है। अतः प्रस्तावित है क इस वित्तीय वर्ष में दो मोबाइल टॉयलेट क्रय किए जाएँगे। इसी प्रकार मेलों व सार्वजनिक कार्यक्रमों में अस्थाई शौचालय बनाए जाते। इनमें टॉयलेट शीट पाइप आदि लगते हैं व कार्यक्रम के पश्चात् वे बेकार हो जाते हैं। अतः प्रस्तावित है कि लोहे के फ्रेम पर निर्मित 20 अस्थाई शौचालय इस वर्ष बनाए जाएँगे जो सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपयोग में आएँगे।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य(Solid Waste Management)

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अंतर्गत शहर की आग सफाई ठोस अपशिष्ट हटाना, एकत्र करना एवं परिवहन आदि का कार्य किया जाता है। शहर से प्रतिदिन लगभग 500 टन कचरा उत्सर्जित होता है जिसे पूर्व में रानीताल के पास ट्रेचिंग ग्राउण्ड में डाला जाता था। प्रोजेक्ट उदय के अंतर्गत कठौंदा में लैण्डफिल साईट का निर्माण पूर्ण हो गया है जिसमें 26 जनवरी 2011 से कचरा भेजना प्रारम्भ किया गया।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण भाग कचरे का डोर–टू–डोर कलेक्शन है। वर्तमान में यह कार्य लगभग सभी वार्डों में चालू कराया गया है जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इन वाहनों के क्रय हेतु भी प्रावधान रखा गया है।

सफाई व्यवस्था

नगर निगम में सफाई कर्मचारियों तथा संसाधनों की कमही होने के कारण शहर में सफाई व्यवस्था ठेका प्रणाली पर तथा नगर निगम के कर्मचारियों एवं संसाधनों के द्वारा कराई जा रही है। कर्मचारियों को समय–समय पर होने वाली सेवानिवृत्ति से सफाई संरक्षकों के पद खाली होते गए इस कारण कर्मचारियों की संख्या कम होती गई। वर्तमान में वार्डों की संख्या 79 हो गई है। सफाई कर्मचारियों की कमी के साथ–साथ संसाधनों/उपकरणों की भी कमी है। अतः आगामी बजट में इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाना आवश्यक है।

विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी की पदस्थापना

नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत अतिक्रमण हटाना, खाद्य पदार्थों की जाँच करना, अनुज्ञप्तिकी शर्तों का पालन कराना नगर निगम का दायित्व है। इन प्रावधानों के उल्लंघन होने पर निगम द्वारा सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालयीन प्रक्रियाओं के चलते ऐसे प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब होता है। इसी तरह शहर में बढ़ते अतिक्रमणों पर भी दाण्डिक कार्यवाहियों में विलम्ब होता है। यदि शासन नगर निगम में विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी की पदस्थापना कर दे तो यह कार्य प्रभावी ढंग से एवं त्वरित गति से होना शुरू हो जाएगा।

अतः प्रस्तावित है कि शासन से इस आशय का अनुरोध किया जावे कि नगर निगम में विशेष दण्डाधिकारी की नियुक्ति की जावे, उनके वेतन भत्तों आदि का व्यय नगर निगम वहन करेगा।

आवारा पशुओं पर नियंत्रण

जबलपुर नगर में आवारा कुत्तों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसके कारण आम जनता को न केवल कठिनाई हो रही है बल्कि रात्रिकालीन समय में सड़कों और गलियों में चलना खतरनाक हो रहा है। वर्तमान में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 प्रभावशील है जिसके अनुरूप किसी भी आवारा कुत्ते/सुअर का वध नहीं किया जा सकता जब तक यह सिद्ध न हो कि वह पागल व उत्मत है। वर्तमान में जनता को भय पागल कुत्तों से नहीं है वरन् सामान्य आवारा कुत्तों से है जो बड़ी संख्या में होने के कारण झुण्ड बनाकर रहते हैं तथा रात्रि में नागरिकों का जीवन दूभर किए रहते हैं। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 38(1) के अनुसार कुत्तों को बधिया व असंक्रमित किया जा सकता है। इसी नियम के परिपालन में वर्तमान में नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों के बधियाकरण एवं टीकाकरण का कार्य कराया जा रहा है।

नागरिकों को एंटी रैबीज वेक्सीन निःशुल्क प्रदाय किए जाने नगर निगम में एंटी रैबीज वेक्सीन प्रतिमाह विक्टोरिया अस्पताल के माध्यम से दिए जाने का प्रावधान था जिसके अंतर्गत अभी तक कुल 400 वेक्सीन प्रदाय किए गए हैं।

मशीनरी क्रय

स्वास्थ्य विभाग में सफाई कार्य हेतु जिन मशीनों एवं उपकरणों की सतत् आवश्यकता होती है उनके एक बार क्रय हो जाने के बाद फिर कई वर्ष तक उनकी बढ़ती आवश्यकता का आकलन नहीं किया जाता न ही उनकी सतत् आपूर्ति हेतु कोई विशेष प्रावधान रखा जाता है। लम्बे समय तक आवश्यक उपकरणों एवं मशीनरी का क्रय नहीं होने तथा पुरानी मशीन खराब हो जाने से सफाई व्यवस्था के कार्य में अनेक कठिनाईयाँ आती हैं। इस हेतु आवश्यकतानुसार मशीनों/उपकरणों एवं व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है जो निम्नलिखित हैं :– सीवर क्लीनिंग मशीनें, सार्वजनिक शौचालय एवं पेशाबघरों की धुलाई सफाई हेतु वाहन, कचरा एकत्रीकरण हेतु हाथठेले, कचरे के डोर–टू–डोर कलेक्शन हेतु साईकिल रिक्शा, मृत पशु बिना सींग वाले उठाने वाहन, लावारिस शवों को उठाने वाहन, मलेरिया नियंत्रण कार्य हेतु पावर स्प्रेयर मशीन, मोबाइल टॉयलेट 10 सीटर, मोबाईल यूरिनल, मोबाईल क्लोज कन्टेनर (4.5 क्यू.मी. एवं 1.1 क्यू.मी. क्षमता वाले), शव वाहन, नर्मदा तटों की सफाई व्यवस्था एवं मृत पशुओं के निराकरण हेतु व्यवस्था आदि। इनमें से अधिकांश उपकरण व व्यवस्थाऐं नगर निगम में आवश्यकता से कम ही हैं। अतः और उपकरण क्रय करने की एवं अधिक व्यवस्थाऐं लागू किए जाने की आवश्यक है।

स्वतंत्रता पश्चात् शहर की जनसंख्या का विस्तारीकरण का मूल कारण बाहर से आने वाले लोगों से हुआ है। लोगों द्वारा जहाँ जगह देखी, वहीं मकान बना लिया गया है, कुछ विशेष जातियाँ आज भी इस शहर में समूह के रूप में निवासरत हैं। पूर्व से ही शहर की अधोसंरचना का विकास न होने के कारण शहर के पर्यावरणीय सौंदर्यीकरण का विकास, स्वच्छता का नियमन प्रभावी ढंग से नहीं हो पाया। पूर्व में जो सफाई कर्मचारी पदस्थ हुए उनसे आज भी शहर की सफाई हो रही है। किंतु शहर इतना अत्याधिक फैल चुका है तथा आबादी एवं कई कॉलोनियाँ विकसित हो गई हैं कि इन कर्मचारियों की संख्या नगण्य प्रतीत होती है। फिर भी अन्य शहरों की तुलना में सफाई की दृष्टि से यह शहर अव्वल है। यह कर्मचारियों की कार्यक्षमता, सफाई के प्रति जागरूकता तथा कार्य के प्रति उत्साह के कारण नगर निगम नागरिकों को सुव्यवस्थित तो नहीं परंतु संतोषजनक स्वास्थ्य सेवाएँ दे रहा है।

उपसंहार

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जबलपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य तो हो रहा है किंतु इसे त्वरित एवं अत्यंत आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अतः स्वास्थ्य जागरूकता हेतु अच्छे कार्यक्रम व योजनाएँ बनाने एवं लागू करने चाहिए। इस हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों, परामर्शदाताओं, समाजशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों एवं समाजसेवियों की सहायता लेनी चाहिए। शिविर में किसी अच्छे समाजसेवी, लोकप्रिय और प्रसिद्ध व्यक्ति के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता सम्बन्धी सूचनाएँ प्रसारित करना चाहिए। आधुनिक जनसम्पर्क माध्यमों का उपयोग करके स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी सूचनाओं/कार्यक्रमों/योजनाओं, शिविरों इत्यादि की सूचना जनसामान्य तक पहुँचानी चाहिए। आधुनिक उन्नत जनसम्पर्क साधनों के द्वारा मितव्ययितापूर्वक अल्प समय और श्रम पर सूचनाएँ सरलता से भेजी जा सकती हैं। नगरीय जनता को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना तथा उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा का दायित्व स्थानीय प्रशासन अर्थात् नगरीय निकायों का है। नगरीय निकाय का सुदृढ़ संगठन एवं प्रबंध होना चाहिए। अत्याधुनिक संचार साधनों का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य जागरूकता लाने वाली सूचनाओं एवं विषयों को सामान्य जनता तक पहुँचाना चाहिए।

संदर्भ

1. स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन, 2011.
2. नगरीय निकायों के लिए सिटीजन चार्टर (पुनरीक्षित) म.प्र. नगरीय प्रशा. एवं विकास विभाग, भोपाल, अगस्त 2011
3. बाबूलाल श्रीवास्तव, नगर पालिका निगम अधिनियम–1956, सुविधा लॉ हाउस, भोपाल (म.प्र.), 2006
4. सरोज कुमार वर्मा, 'मूल मुद्दे की पहचान', आलेख, योजना–मासिक, प्रकाशन विभाग, सूचना–प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जुलाई 2009
5. आयुक्त नगर निगम, जबलपुर, स्वास्थ्य विभाग, 2008
6. स्वास्थ्य विभाग का आव–व्ययक, 2013–14 हेतु प्रस्ताव एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नगरपालिका निगम, जबलपुर (म.प्र.)
7- Project Report on PMS by Ascent Leadership & Management Consultant (P.)Ltd. for MPUSP Project.

Status of Tourism in Madhya Pradesh

Mrs. Gunjan Shrivastav

ABSTRACT

Tourism is not merely leisure or entertainment or physi cal invigoration or mental rejuvenation. It also serves as a potent instrument for eliminating poverty, for ending unemployment, for promoting dialogue among civilizations and for providing channels in which, streams of different culture could meet and mingle. This paper attempts to cover various trends of tourist arrival in Madhya Pradesh, revenue generation and employment possibility, as well as subject area of Madhya Pradesh tourism in all its possible dimensions in particular, the numerous variables which keep on impacting upon it. The possibilities of new dimensions in the fields of thematic tourism are explored in this paper and there is an effort to formulate some new strategies for tourism development in Madhya Pradesh. Evaluation of the role of tourism in the state economy has also been the effort here. Therefore, this paper can prove to be helpful in determining the extent and role of tourism in the economy.

Focus Area and Tourist Arrival

Tourism activity in Madhya Pradesh is mainly concentrated in protected areas. But due to the lack of infrastructure, trained manpower and absence of separate contingent staff for visitors use and interpretations; the level of enrichment through a variety of experience is not adequate. Tourism in Madhya Pradesh is characterized by the following trends:

- The continued dominance of cultural tourism as far as foreign tourists is concerned.
- A shift towards nature resorts and wildlife areas for domestic tourists.
- Growing interest in tribal art and culture and the emergence of adventure tourism as a major tourist interest.
- The state has been divided into five tourism circuits, viz Bhopal, Jabalpur, Panna-Khajuraho, Pachmarhi-Pench and Indore.

In 2006, the number of tourist arrivals in Madhya Pradesh was one crore, while the current figure exceeds six crore visitors. This has necessitated creation of improved facilities and better connectivity

The year 2013 saw arrival of 2, 80,000 international tourists in the state, along with 15 per cent to 20 percent increase in domestic tourist arrivals. The state government has signed a MoU with Emirates and Air Arabia for international air connectivity to Bhopal and Indore.

The yearly calendar of the state of Madhya Pradesh is featured with innumerable fairs and festivals. These events portray the vibrant culture and enthusiasm of the people of the state. The state celebrates varied kinds of festivals like religious festivals originating from mythology, festivals to mark a particular season, festivals held in memory of a local God or a native hero. Apart from showcasing the culture and heritage of the state, some of these festivals even take the art and culture of the tribes up to the national market. To know the entire state, one needs to have a glimpse of these festivals. Fairs are a major part of almost each of these festivals. During festive seasons, most of the populations of Madhya Pradesh, dressed in colorful native attire along with ornaments, are found to be moving towards the fair ground. Though each and every festival has its own unique features that are different from one community to another, still some of the common activities include, merry making, cock fighting, meena bazaar, swings, eating and drinking, singing and dancing.

Rural parts of Madhya Pradesh are still resided by the tribals.They still follow the traditions and rituals that were followed by them at thebegning. Rural destinations of Madhya Pradesh are surely the beats in this heart of India.

The focus of rural tourism is to provide quality holiday experience to domestic and international visitors to

rural sites of India in which home stays/farm stays are provided with certain hosting criteria.

Tourism Policy

In November 1982 first Tourism Policy of Government of India was announced. This had marketing as its focus than have a prescription plan for development. In 1992, a National Action Plan for tourism was prepared and in 1996 the drafting of National Strategy for Promotion of Tourism was done. In 1997, a draft new tourism policy according to 21 the on going economic policies of the Government along with the trends in tourism development was published for public debate and deliberations. The draft policy is currently under revision. A New Tourism Policy, which builds the strength of the national Tourism Policy of 1982, but which envisages new initiatives towards making tourism the catalyst in employment generation, environmental regeneration, development of remote areas and development of women and other disadvantaged groups in the country. Beside these, promotion of social integration is, vital to our economy. It would lead to larger foreign exchange earnings and create conditions for more Foreign Direct Investment.

The mission is to promote sustainable tourism as a means of economic growth and social integration and to promote the image of India abroad as a country with a glorious past, a vibrant present and a bright future. The objectives of tourism development are to foster understanding among people, to create employment opportunities and bring about socio-economic benefits to the community, particularly in the interior and remote areas and to strive towards balanced and sustainable development and preserve, enrich and promote India's cultural heritage. One of the major objectives is the preservation and protection of natural resources and environment to achieve sustainable development.

The New Tourism Policy also aims at making the stay of foreign tourists in India, a memorable and pleasant one with reliable services at predictable costs, so that they would be encouraged to undertake frequent visits to India, as friends. India is not all geared up to reach its true potential in tourism. The endeavour is to go for a comprehensive tourism policy with focus on ecology economics and local participation and benefit sharing.

For this the questions that need to be resolved are as follows:

- How can responsible active participation of the local people in
- How will the Planning and implementing tourism promotion schemes be encouraged?
- How can better municipal governance especially in and around tourism centres be promoted?
- How can vandalism be checked and promotion of responsible tourism be done, especially environmental and local benefits are concerned?

Objectives of Tourism Policy

The objectives of the tourism policy are as follows :

- To create employment opportunities and to bring about socio-economic benefits to the community.
- Facilitate and expand sustainable domestic and foreign tourism in the country.
- Minimise negative effects such as cultural pollution and degradation of natural environment.
- Increase the tourists satisfaction and making their tourism activity pleasant and memorable.
- Create a desirable tourist products supported by infrastructure.
- Involve and create synergy among all agencies, public, private and government in tourism development.
- Maintain a balance between the negative and positive impacts of tourism through planning restrictions and education of the people for conservation and development.

Factors affecting Growth of Tourism in M.P.

The important factors, which have limited the growth of tourism in Madhya Pradesh, are mentioned below:

a) Inadequate airline capacity, particularly during the peak tourist season, bad conditions of our airports, delays in getting the bookings, flight cancellations and

delays render airtravel in India night marish for foreign tourists.

b) Due to appalling conditions of traveling by trains, in India tourist prefer to avoid unless unavoidable.

c) Lack of hygienic and comfortable accommodation for the tourist,in general, but reasonable good accommodation for low spending middle class tourists in particular, render tourism unattractive. Absence of motel hampers the smoothness of long distance travels.

d) There is absence of an up to date information systems with quick retrieval facilities causes inconvenience to tourists.

e) Another major factor inhibiting the growth of tourism is the seasonality of the industry with the busy season being limited to six months from October to March and heavy rush in November and December.

f) Lack of an integrated tourism promotion programme during the five year plan periods has hindered the growth of tourism.

g) Indifference of many states and union territories to tourism, which has not yet been accorded industry status by them, is another factor limiting its growth.

h) Next factor is the failure of the mandarins of tourism to quickly adopt to the changing environment, for example the temporary closure of Jammu and Kashmir to tourists and socio-political and religious agitations in other northern states of the country rendering them unattractive to tourists, by developing and promoting alternative tourists destinations in South India.

i) A lukewarm attitude towards the domestic tourism due to the emphasis placed by the authorities on foreign tourism has been another limiting factor. We should not forget that domestic tourists have its own importance and its development provides a sound basis for the growth of international tourism.

Suggestions for Improvements

Tourism development must be guided by a sound and careful planned policy not built on balance sheets and profit and loss statements alone, but on the ideals and principles of human welfare and happiness. Sound development policy can have the happy results of a growing tourist business and the preservation of the natural and cultural resources that attracts visitors in the first place. Main advantages of tourism are that it provides employment opportunities, both skilled and unskilled, because it is a labour intensive industry, that generates a supply of foreign exchange, increases income, creates increased GDP, requires the development of an infrastructure that will also help stimulate local commerce and improvement, increases governmental revenues, helps to diversify the economy, creates a favourable worldwide image for the destination, facilitates the process of modernization, by education of youth and society and changing values, provides tourist recreational facilities that may be used by a local population, gives foreigners an opportunity to be favourable impressed by a little known country or region.

Finally following steps are suggested to revamp the tourism administration for making tourism a grand success:

1. Experts in the fields of hotel management and tourism must be associated with all the decision-making bodies of the structure.
2. The State Tourism Departments must have an independent research, Development and analysis wing to research tourist demand and tourism structure in their states so as to develop the prospects of tourism in the state.
3. The State Governments must also develop an institute of Hotel Management and Tourism guidance in respectives state to have better trained and equipped units like tourist bungalows, hotels, midways night resorts etc.
4. All the tourist information bureaus must be adequately staffed and equipped to satisfactorily perform their functions.
5. The state governments must encourage its employees to undertake journeys providing concessions on the Central Government pattern.

6. Tourism should be declared an industry by the State Government without any delay to attract the private entrepreneurs to invest in construction of hotels and other resorts.
7. The standard of room services transport services etc. should be improved for customers' satisfaction.

8. The pre-service and in-service training programmes should be started for better results.
9. Better liaison should exist between State Tourism Department and ITDC.

Conclusion : Thus we come to the conclusion that a well knit management system should be established to encourage tourism in the state. Madhya Pradesh is gifted with beautiful spots which are natural and some are manmade, but it still lacks a healthy flow of foreign tourists. The tourism industry in the state carries a huge potential of attracting tourists provided proper care should be taken of its cultural and historical legacy. Hence the department should thoroughly analyze the Strengths and weaknesses of the its Tourism Industry and should also consider the opportunities coming its way and the threats it will have to face in order to promote and develop tourism in Madhya Pradesh.

References :

- Dube Dr. Rajiv, Tourism in the Economy of Madhya Pradesh,Daya Publishing House, New Delhi, 1987
- Kothari Anurag, A Book of Tourisms and Aviation, Wisdom Press, Kolkata, 2011
- Mahajan Malti, Madhya Pradesh: Cultural and Historical Geography from Place name in Inscriptions, Sharada publication, Agra, 2000
- Sarkar A.K., Action Plan and Priorities in Tourism Development, Kanishka Publications, New Delhi, 2010
- Sen Probir, Madhya Pradesh: Unhurried Unspoilt Undiscovered, Wisdom Tree Publications, New Delhi, 2010

राष्ट्रीय जैव विविधता

धनेन्द्र कुमार, एम.ए., एम.फिल., पी–एच.डी अध्ययनरत् (राजनीति विज्ञान) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर म.प्र.

भारत के संदर्भ में – भारत एक वृहत् विविधताओं वाला राष्ट्र है। विश्व में केवल 12 ऐसे राष्ट्र हैं जो वृहत् जैव विविधता राष्ट्र के रूप में जाने जाते है। भारत भी इन जैव विविधता रखने वाले 12 राष्ट्रों में सम्मिलित है। ऐसा माना जाता है कि विश्व के सर्वाधिक पादप सम्पन्न राष्ट्रों में भारत का 10 वाँ स्थान है, तथा जैव विविधता एवं कृषि विविधता की उत्पत्ति की दृष्टि से भारत का 6 वाँ स्थान है।

भारत का विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2 प्रतिशत भू–भाग है ताकि इस राष्ट्र में विश्व की कुल ज्ञात जैव प्रजातियों का 6 प्रतिशत भाग निवास करता है। इसके अलावा भारत के पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट क्षेत्र जैव विविधता सम्पन्न क्षेत्र या जैव विविधता के तप्त स्थलो की उपस्थिति में उल्लेखनीय है।

वर्तमान में भारत में जेनेटिक भिन्नता रखने वाले 1.25 लाख से अधिक आर्थिक वैज्ञानिक रूप से वर्णित प्रजातियॉ तथा 4.0 लाख से अधिक अवर्णित प्रकृतियाँ है जो देश के कुल 328.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्षेत्रफल पर फैली हुई है।

भारत में जैव प्रजातियों की आर्थिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण है कि इस देश में जलवायु तथा उच्चावच की दृष्टि से पर्याप्त भिन्नताएँ।

जैव विविधता के ह्रास के कारण–

जैव विविधता के ह्रास के निम्नलिखित कारण प्रस्तुत हैं–

1. **प्राकृतिक कारण** – जब जलवायु में होने वाले परिवर्तनों को कोई जीव सहन नहीं कर पाता अर्थात् प्राकृतिक दशाओं के अनुरूप स्वयं को ढ़ाल नहीं पाता तो उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। अतः इस प्रकार की प्रजाजियाँ पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाती हैं। साथ हीं जो प्रजातियाँ इन जलवायु परिवर्तनों के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेती हैं, वे प्रजाजियाँ और अधिक विकसित रूप में अस्तित्व में आती चली जाती हैं।

2. **निवास क्षेत्रों का विनाश** – वर्तमान क्षेत्र में विकास के नवीन आयामों की खोज में जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण वनोन्मूलन है। आर्द्र प्रदेशों तथा अन्य जैविक रूप से सम्पन्न पारिस्थितिकी तंत्रो के विनाश से प्रतिवर्ष सैकड़ों प्रजातियों का पृथ्वी से पूर्णतया सफाया हो जाता है।

प्रजातियों में निवास क्षेत्र के विनाश से जहाँ एक ओर प्रजातियों की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आती है, वहीं दूसरी ओर निवास क्षेत्र छोट–छोटे विलग भागों में विभक्त हो जाता है। वन्य जीवों के अस्तित्व की रक्षा के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थाना वनों का होता है। वनों के विभिन्न उपयोग हेतु अनियंत्रित कटाई से जीवों के निवास क्षेत्र नष्ट होते जा रहे हैं।

3. **जंगली जीवों का अवैध शिकार** – भू–पटल पर जंगली जीव वस्तुओं का मानव द्वारा वृहत् स्तर पर अवैध शिकार करने से इनका तेजी से विनाश हो रहा है। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्धों/नियमों आदि के बावजूद भी जीवों का अवैध शिकार किया जा रहा है। जीवों से प्राप्त बहुमूल्य खाल, दाँत, हड्ड़ियाँ आदि से आर्थिक लाभ पाने के उद्देश्य।

मानव वन्य जीवन संघर्ष–

मानव प्राचीन काल से ही वनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं के लिये करता आया है। मनुष्य अपनी सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही वन्य जीवन का अविवेकपूर्ण ढ़ग से विदोहन करता आया है किन्तु 20वीं शताब्दी में बढ़ते औद्योगीकरण नगरीकरण तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण मानव द्वारा वन्य जीवन के विदोहन की दर में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई है। भू–पटल पर वनों तथा घास के क्षेत्रो के सिकुड़ते क्षेत्रफल से जंगली जीव–जन्तुओं के प्राकृतिक आवासीय क्षेत्रो को नष्ट करने तथा मानव द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से इनका वृहत् स्तर पर शिकार करने से जंगली जीव–जन्तुओं को तेजी बिनाश हो रहा है। फरयुक्त खालों के लिये शेर, हिरण

तथा चीता को उनकी बहुमूल्य खालों के लिये तथा हाथियों को उनके कीमती दाँतो के लिये मानव द्वारा वृहत् स्तर पर इन जीवो को मारा जा रहा है, साथ ही अनेक अन्य जंगली जीवों तथा पक्षियों के मास प्राप्ति के लिये शिकारियों द्वारा शिकार किया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि कई प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी है और कई विलुप्ति की कगार पर है।

जैव–विविधता का महत्व

जैव–विविधता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योकि यह मानव संस्कृति के विकास में बहुत सहायक होती है। दूसरी ओर मानव ने अनवंशिक प्रजातीय व परिस्थितिकी स्तरों पर प्राकृतिक विविधता बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव–विविधता की तीन मुख्य बकाए हैं जिन्हे पारिस्थितिकी आर्थिक तथा वैज्ञानिक भूमिका के में जाना जाता है।

जैव–विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका

परितंत्र में अनेक प्रजातियां होती है, जो विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। प्रत्येक जीवन आपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ वस्तुओं का प्रयोग करता है, और साथ ही अन्य जीवों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ पदार्थ लौटाता है।

जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती हैं और पारितंत्र में जल व पोषण तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायता देती है। इसके अतिरिक्त प्रजातिया वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती है। और जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्रजातियों द्वारा किए गए कार्य पारितंत्र को कार्यरत रखने तथा मानव जीवन के विकास के लिए उपयोगी हैं।

पारितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होगी। स्पष्ट है कि प्रजातियों की क्षति से पारितंत्र की क्षमता भी कम हो जाती है। अधिक जैव–विविधता वाले पारितंत्र में पर्यावरणीय परिवर्तनों को सहन करने की क्षमता अधिक होती है। अतः अधिक विविधता वाले पारितंत्र की स्थायी रहने की संभावनाएं भी अधिक होती है।

जैव विविधता

जैव विविधता अथवा जीवीय विविधता का अभिप्राय जीवों को विविधता अथवा प्रचुरता से है। किसी प्रदेश की जैव विविधता वहां पर रहने वाले सूक्ष्मजीवों पादपों तथा पशुओं के योग द्वारा आंकी जाती है। विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार ''जैव विविधता विश्व के जीवो तथा उनके जनन का विविधता एवं उनके द्वारा निर्मित संयोजन से है। यह प्राकृतिक जैव सम्पत्ति है जो मानव जीवन तथा उसके कल्याण को प्रभावित करती है''

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार '' सभी पशुओं पादपों एवं सूक्ष्मजीवो तथा पारिस्थितिकी जटिलताओं की विभिन्नता एवं परिवर्तशीलता को जैव विविधता कहते हैं। '' जैव विविधता की संकल्पना को तीन विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है और प्रत्येक स्तर का अपना विशेष महत्व है। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

भारत में जैव विविधता

32.87 लाख वर्ग किमी. से भी अधिक क्षेत्र वाला भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है जिसमें अधिकांश भागों में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अतः यह जैव विविधता की दृष्टि से बड़ा ही समृद्ध देश है। इसके लगभग 6,77,088 वर्ग किमी. श्रेत्र पर वन उगे हुए हैं। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 20.59 प्रतिशत है। इसमें से 38,726 वर्ग किमी. (57.19) सघन वन, 289872 वर्ग किमी. (42.81%) खुले वन, 38475 वर्ग किमी. (8. 761%) छितरे वन हैं। पश्चिमी तटीय भाग में तथा असम में सदाबहार वर्षा वन, पश्चिमी हिमालय में कोणधारी वन महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा राजस्थान में शुष्क मरूस्थलीय वनस्पति पाई जाती है।

भारत को तीन मुख्य भू–आकृतिक खंड़ों में बाटा जाता है। इसके उत्तर में विश्व का उच्चतम हिमालय पर्वत तथा इसके पूर्वी एवं पश्चिमी विस्तार तथा दक्षिण में

विश्व का प्राचीनतम प्रायद्वीपीय पठार है। इन दोनो के मध्य में गंगा–सिंध का मैदान है। भारत में प्राचीनतम जीवाश्म (fossil) 450 मिलियम वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। 300 मिलियन वर्ष पूर्व भारत का अधिकांश भाग वनाच्छादित था। इस समय भारत विश्व के 12 महाजैव विविधता केन्द्रों में से एक है।

भारत में जैव विविधता उच्च स्तर की है जहां पर विश्व की लगभग 8 प्रतिशत प्रजातिया पाई जाती हैं। पादप समृमिद्ध की दृष्टि से भारत विश्व का दसवां बड़ा देश है। इसकी परिस्थिति में वन आद्र भूमियां (Wetlands), घास के मैदान, मरूस्थल, समुद्री भाग, आदि हैं, और प्रत्येक में हजारों प्रजातियां है। अभी तक लगभग 2,00,000 प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है, और बहुत सी अन्य प्रजातियों की पहचान करना अभी बाकी है। भारत में जैव विविधत का संक्षिप्त विवरण।

संदर्भ सूची :

1. श्रीवास्तव डॉ. लोकेश : पर्यावरणीय अध्ययनः म.प्र. हिन्दी ग्रंथ आदमी ओवस 2012–13
2. गर्ग डॉ. एच.एस. गर्ग डॉ. अजली : पर्यावरण अध्ययन : विद्याया भवन 620 खजरी बाजार इंदौर 452002 इंदौर
3. शर्मा डॉ. प्रो. राजीव, सिद्दकी डॉ. अनिश : पर्यावरीण अध्ययन, देवी अहित्या प्रकाशन : 26 सुभाष चौक इंदौर (म. प्र.)
4. खुल्लर डी.आर. भूगोल मेग्राव हिल एजूकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमीटेड (न्यू दिल्ली)
5. इन्टरनेट के द्वारा प्राप्त किया गया है।
6. मासिक पत्रिका कुरूक्षेत्र, 2016
7. मासिक योजना पत्रिका, 2015

''छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में महिला जागृति कार्यक्रम में कैथोलिक चर्च का योगदान''

डॉ. सी. अनुपा तिर्की, सहायक प्राध्यापक (राजनीतिक शास्त्र) शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा (छत्तीसगढ़)

1. गृहिणी शिक्षा योजना (गृहिणी स्कूल) :–

गृहणी स्कूल ग्रामीण अशिक्षित युवतियों के लिए स्वास्थ्य, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक ज्ञान का आभास देने के लिए खोला गया है। यह लगातार दस माह तक चलता है। इसमें इन अशिक्षित युवतियों को लिखने, पढ़ने की शिक्षा तथा मानव जीवन के प्रत्येक पहलु का संक्षिप्त ज्ञान दिया जाता है। दूसरे शब्दों में – गृहणी स्कूल में पारिवारिक और सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा दी जाती है। इन स्कूलों के प्रत्येक केन्द्र में एक सत्र में 15 से 60 अशिक्षित युवतियाँ शिक्षा प्राप्त कर सकती है।

विशप ओस्कार सेभरिन औपचारिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वे पहले राँची महाधर्मप्रान्त में थे। बाद में रायगढ़–अम्बिकापुर धर्म प्रांत आए। उनका ध्यान ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा की ओर आकृष्ट हुआ। ग्रामीण महिलाएं अकसर ठगी, दुर्व्यवहार और हिसाब रखने में असमर्थ होना। पुरूष जाति के सामने वे असहाय थी। विशप ने इस समस्या को देखा कि यद्यपि स्कूलों के द्वारा सरकारी नौकरी के लिए बहुत स्त्री–पुरूष योग्यता प्राप्त कर लेते थे, यद्यपि आदिवासी ग्रामीण समाज, ऐसी स्त्रियों पर अधिकतर निर्भर करता है जो अशिक्षित है, परंतु अपने पतियों के साथ घर एवं खेतों की देखरेख करती है। अतएव उनकी मदद करनी चाहिए कि वे अपने कर्तव्यों को और अधिक अच्छी तरह से निभा सकें तथा बेहतर समाज का निर्माण कर सके। इस कार्य में पुरूषों की आपेक्षा स्त्रियों की भूमिका और बड़ी है। विशप सेभरिन की यह अर्न्तदृष्टि (विजन) (vision) थी। इसी से उनको ग्रामीण महिलाओं के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिली पल्ली के कार्यों में भी ऐसी महिलाएं अपना योगदान देती थी।

होली क्रोस धर्मसमाज की सिस्टर जोहान्ना को विशप सेभरिन के इन विचारों से प्रेरणा मिली। इसके साथ उनकी अपनी ही दृढ़ धारणाएं रही। सन् 1960 को घोलेंग में उसने प्रथम गृहिणी स्कूल की सीापना की। यह निरक्षर या अर्ध–साक्षर अविवाहिता महिलाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा योजना के तहत हुई। आरंभिक अवस्था में श्रीमति लूसी एक्का का नाम भी नहीं भूलना चाहिए। वह सिस्टर जोहन्ना की अति सफल सहयोगी रही।

गृहिणी स्कूल प्रारम्भ करने के उद्देश्य :–

1. साक्षरता एवं निरक्षता के मध्य की खाई भरना।
2. अपने आप को आदर करना तथा इसके साथ–ही–साथ दूसरों का भी आदर करना।
3. एक आदर्श पत्नी, बहु और माँ बनाना।
4. ग्रामीण बालिकाओं में जो गुण–योग्यता और गांव–घर में जो चीजें उपलब्ध है उसके बारे में जानकारी देकर परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना।
5. महिला शोषण, अत्याचार और बलात्कार से बचना।
6. अनौपचारिक शिक्षा–पद्धति के द्वारा निरक्षर या कम शिक्षित ग्रामीण लड़कियों को कुशल गृहिणियाँ, माताएँ समुदाय का नेतृत्व करने वाली और शिक्षित व्यक्ति बनाना, इस योजना का उद्देश्य है। इस प्रशिक्षण से ग्रामीण लड़कियों को आत्मविश्वास प्राप्त होगा। वे समाज की उत्तरदायी सदस्य होंगी और देश की सुयोग्य नागरिक बनेगी।
7. जो लड़कियां स्कूल नहीं जा सकी या कई कारणों से उनको स्कूल छोड़ देना पड़ा वे गृहिणी स्कूलों में शिक्षा पा सकेंगी ताकि वे मनुष्योचित जीवन जी सकें और अपने परिवार को अच्छा जीवन की ओर चलें।

विधियाँ और प्रशिक्षण के तरीके :–

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित सैद्धान्तिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। यह प्रशिक्षण–काल 8 से 10 माह का होता है। ये स्कूल पल्लियों में ही स्थित रहते है। प्रशिक्षण–क्षेत्र है– गृह विज्ञान, मातृ कला, रसोई बनाना, या पाक शास्त्र, बागवानी, मुर्गी पालन, स्वास्थ्य–रक्षा, विवाह, प्राकृतिक परिवार नियोजन, सिंलाई, बुनाई, वयस्क शिक्षा, पशु–पालन, मधुमक्खी पालन और उद्यान कृषि प्रत्येक केन्द्र में दो स्थाई स्टॉफ रहते है, अर्थात् दो स्थायी रूप से रहने वाले प्रशिक्षक। इनके अतिरिक्त, बाहर से विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ, भाषण और सेमीनार के लिये निमंत्रित किये जाते है। इन केन्द्रों में स्थाई रूप से नियुक्त किये जाने वाले स्टॉफ सदस्य, योग्यता प्राप्त व्यक्ति होते है जो टी.टी.सी. गृहिणी–प्रशिक्षण–केन्द्र हजारीबाग, जैसी संस्थाओं में प्रशिक्षित रहते है और इनके पास आवश्यक प्रमाण पत्र होते है। अंत में ये प्रशिक्षित लड़कियाँ गृहिणी केन्द्रों में स्टॉफ सउस्य बन सकते है।

जशपुर जिले में गृहिणी स्कूल का प्रारंभ :–

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के अंर्तगत घोलेंग नामक शैक्षणिक केन्द्र में सन् 1960 ई. में अशिक्षित युवतियों के लिए गृहिणी स्कूल का प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उत्प्रेरक होली क्रॉस धर्म समाज की सिस्टर जोहन्ना थी। जिसे एक आदिवासी सिस्टर लूसी एक्का का पूर्ण सहयोग मिला था। आरंभिक दिनों में गृहिणी स्कूल उन युवतियों के लिए था जो 10 से 15 वर्ष की उम्र में स्कूल नहीं जा सकी थी। इन्हें लिखने–पढ़ने का साधारण ज्ञान देना था। इस कार्यक्रम में उन्हें असफल होने का अहसास हुआ। इसलिए उन्होंने गृहिणी स्कूल की सफलता के लिए सर्वप्रथम मैट्रिक पास युवतियों तथा धर्म बहनों को इन स्कूलों में शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण दिया। शिक्षिकाओं के प्रशिक्षित हो जाने के बाद सन् 1962 ई. में जशपुर तथा सरगुजा जिले में 10 गृहिणी स्कूल खोले गये। प्रत्येक केन्द्र में एक सिस्टर संचालिका और सहायक शिक्षिका रहती थी। इन स्कूलों में युवतियों को गृह स्वामिनी, माता तथा समाज के प्रति निष्ठा की शिक्षा दी जाने लगी। इन गृहिणी केन्द्रों में स्कूल छात्रावास की भांति व्यवस्था की गयी। जहाँ एक क्लास रूम, एक शयन कक्ष, एक गोदाम, एक रसोई कमरा, और एक छोटा सब्जी बगान रहता है। क्योंकि प्रत्येक परिवार में इन सब चीजों की आवश्यकता होती है।

मकान की बनावट देहात के घरों की भांति बिलकुल साधारण थी लेकिन जीवन की अन्य आवश्यकताओं का इसमें प्रावधान किया गया था। जैसे–कमरे में प्रकाश, स्नानगृह, शौचालय आदि।

गृहणी स्कूल के कुशल संचालन के लिए जशपुर जिले के कुनकुरी पल्ली को इसका मुख्यालय बनाया गया है। यही कुनकुरी पल्ली में इसके संचालकगण रहते है तथा विभिन्न गृहिणी केन्द्रों का निरीक्षण करते है।

पाठयक्रम :–

गृहिणी स्कूल फरवरी से दिसम्बर तक कुल 10 माह का पाठयक्रम है। जिसमें निम्न लिखित विषय पढ़ाये जाते है –

1. माँ–बच्चे का पारिस्परिक संबंध
2. साधारण पारिवारिक चिकित्सा एवं इलाज
3. प्राथमिक चिकित्सा
4. आहार और पाक विधि
5. पोषाक और पहनावे पर शिक्षा
6. सिलाई, कढ़ाई, तथा सिलाई मशीन का ज्ञान
7. परिवार संचालन की शिक्षा
8. सामाजिक जीवन संबंधी शिक्षा
9. स्वास्थ्य शिक्षा
10. प्रौढ़ शिक्षा
11. कृषि एवं बागवानी
12. हस्त कला
13. मातृ कला
14. गीत–नृत्य एवं सांस्कृतिक क्रिया कलाप।

इसके अतिरिक्त उन्हें सार्वजनिक ग्रामीण जीवन की पारिस्थितियों के अनुकूल शिक्षा दी जाती है। जो दैनिक जीवन में काम आते है– जैसे जंगल से जलाऊ लकड़ी लाना, बकरी पालन, मुर्गी पालन, खरगोश पालन, कपड़ा सिलाई करना, बाजारों और दुकानों में खरीद बिक्री करना, छोटे–छोटे बगानों में सब्जी उगाना, घर–आँगन साफ करना, चटाई बुनना, कपड़ा प्रेस करना आदि के द्वारा परिवार की आय में वृद्धि करने की शिक्षा दी जाती है।

इसके साथ–ही–साथ इन्हें सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन के प्रत्येक पहलू पर नाटक और रोल प्ले के द्वारा शिक्षा दी जाती है। उनके मनोरंजन के लिए संगीत पर भी जोर दिया जाता है।

सीखने की सुविधाएं केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं है। अवकाश के समय वार्तालाप, पर्यटन, त्यौहार, नृत्य, खेल और सामुदायिक जीवन व्ययतीत करने की सुलभता उन्हें चरित्र निर्माण में मार्ग दर्शन और व्यक्तित्व विकास के अवसर प्रदान करते है। जब कभी घरों में अधिक काम होता है यथा कटनी और रोपा के समय बालिकाओं को मदद के लिए उनके गांव भेजा जाता है। आस–पास के गांवों के अवलोकन की व्यवस्था भी की जाती है। जहाँ वे अरोग्य शास्त्र और स्वच्छता के नियमों का व्यवहारिक रूप से उपयोग कर सके। गांव की सैर करने के पश्चात् वाद–विवाद किया जाता है जिसमें उनके विचारों को प्रोत्साहन मिले। इस तरह वे दूसरों के विचार और अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना भी सीखती है। विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार व्यवहार करें? इस उद्देश्य से बालिकाओं को जीवन के विभिन्न पहलुओं को अभिनय द्वारा दर्शा कर सिखाया जाता है। जिससे वे भले बुरे में अंतर जान सके। बगान में स्वयं द्वारा उत्पन्न की गई सब्जियों को बाजार में बेचकर उन पैसों से रसोई के लिए मसाले आदि खरीदती है और इस तरह उन्हें खरीद बिक्री का ज्ञान प्राप्त होता है।

गृहिणी शिक्षा के लाभ को देखकर अशिक्षित युवतियों में बहुत ही उत्साह आया और थोड़े ही समय में बहुत से गृहिणी केन्द्रों की मांग हुई। इन मांगों के अनुसार जशपुर धर्म प्रांत में लगभग 13 गृहिणी स्कूल खोला गया जो निम्नानुसार है :–

1. अम्बाकोना
2. गिना बहार
3. घाघरा
4. घोलेग
5. जेकबहला
6. कॉन्साबेल
7. लुड़ेग
8. मुसगुटरी
9. पत्थलगांव
10. पोरतेंगा
11. सराई टोली
12. ताम्बामुण्डा
13. तपकरा

सन् 1960 ई. से 1985 ई. तक गृहिणी स्कूल सफलता पूर्वक चला सन् 1985 में पत्थल गाँव में सिल्वर जुबली मनाया गया। जिन उद्देश्यों को लेकर गृहिणी स्कूल की शुरूआत हुई थी उसका परिणाम आज गाँवों में देखने को मिलता है। 10 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लड़कियां न केवल व्यक्तिगत विकास की बल्कि परिवार के साथ–साथ गाँव एवं समाज में परिवर्तन लायी है। एक गृहिणी प्रशिक्षित माँ शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपने बच्चों को स्कूल भेजती है जिसके परिणाम स्वरूप जशपुर जिले में शिक्षा के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी हुई है। इस गृहिणी स्कूलों के परिणाम स्वरूप जशपुर जिले में अनपढ़ लड़कियों की संख्या में कमी हुई और इसी कारण गृहिणी स्कूल की संख्या को कम करना पड़ा।

फिलहाल निम्नांकित गृहिणी स्कूलों में अनपढ़ लड़कियों के लिए प्रशिक्षण चल रहा है:–

1. अम्बाकोना
2. तपकरा
3. पत्थलगांव
4. घोलेंग
5. बिरसिंघा (जिला रायगढ़)

गृहिणी स्कूल का प्रभाव :–

सन् 1960 से 1999 ई. तक गृहिणी प्रशिक्षाणार्थियों की कुल संख्या 17717 है। जिसमें अधिकांश गृहिणी प्रशिक्षित कन्याओं की शादी हो चुकी है जो कि अब बेहतर गृहस्वामिनी एवं कुशल माता साबित हो रही है तथा वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही है।

इस कार्यक्रम से अशिक्षित युवतियों में शिक्षा का प्रसार हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप परिवार ग्राम एवं समाज में परिवर्तन आया है। घर परिवार के साथ ही साथ कृषि में प्रगति हुई। गृहिणी प्रशिक्षित लड़कियाँ अपने परिवार की देख–रेख करने तथा घर के सामनों को व्यवस्थित रखने का ज्ञान प्राप्त किया। उनके भोजन और खान–पान में सुधार हुआ। पौष्टिक आहार को प्राथमिकता दिया जाने लगा। व्यक्तिगत पोषाक और पहनावे के वस्त्रों में परिवर्तन

आया। बाल बच्चों के स्वास्थ्य और सफाई में उन्नति हुई। गृहिणी प्रशिक्षित लड़कियां घर ही में सिलाई करने लगी जिससे आर्थिक बचत हुई। खरीद–बिक्री का ज्ञान उन्हें प्राप्त हुई। इन्हीं कारणों से समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ा। इस प्रकार गृहिणी शिक्षा योजना से पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक जीवन में प्रगति एवं उन्नति हुई।

अच्छी तरह से प्रशिक्षित होकर निकलने पर लड़कियों में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। उनका रूख बदल जाता है। चाल–व्यवहार, रीति, शिष्टाचार, दूसरों के साथ संबंध, बोलने–करने का ढंग, इत्यादि अच्छे हो जाते है। बहुत सी लड़कियाँ समाज में अच्छी नेत्री बनती है। कुशल गृहणियाँ और अच्छी माताएँ बनती है। शादी के लिए उनकी बहुत मांग होती है। कई निरक्षर लड़कियाँ दस माह के प्रशिक्षण के बाद शिक्षित हो जाती हैं।

2. मोबाइल गृहिणी प्रशिक्षण :–

जशपुर जिले में महिलाओं और जो बालिकाएं बीच में पढ़ाई छोड़ देती है, उनके विकास के लिए सन् 1992 ई. में मोबाइल गृहिणी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रारंभ में यह कार्यक्रम अनुभव प्राप्त करने के लिए केवल पांच गांवों में इस योजना को शुरू किया गया था। महिलाओं की रूचि एवं उत्साह देखकर और अधिक गांवों में इस योजना को शुरू करने की अनुमति मांगी गई। मिसेरियोर द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से अभी कुल 12 गांवों में यह शिक्षा योजना चल रही है। इन प्रत्येक गाँव में एक प्रशिक्षित शिक्षिका शिक्षा देने के लिए नियुक्त होती है।

मोबाइल गृहिणी शिक्षा योजना का पाठ्यक्रम कुल 6 माह का होता है। एक प्रशिक्षित शिक्षिका 6 माह तक एक गाँव में रहकर महिलाओं की सुविधानुसार सामान्यः दोपहर 12 से 3 बजे तक प्रशिक्षण देती है। इन प्रशिक्षणार्थियों से शिक्षण फीस नहीं ली जाती है। शिक्षिका के रहने और खाने–पीने की व्यवस्था गाँव वाले स्वयं ही करते है।

मोबाइलगृहिणी प्रशिक्षण से प्रभावित होकर आस–पास की अन्य गाँवों की महिलाएं इस कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए संबंधित शिक्षिका से संपर्क सीपित कर उन्हें अपने गांव में आने के लिए निमंत्रण देती हैं। इसके पश्चात् अपने ही गांव में पुरूषों एवं महिलाओं के बीच में बैठक करके इस मोबाइल प्रशिक्षण का अपने गांव में केन्द्र खोलने का निर्णय लेते है। इस प्रशिक्षण योजना को उस गांव तक पहुँचने के लिए स्थानीय पल्ली पुरोहित एवं प्रचारक का भी सहयोग मिलता है।

उद्देश्य :–मोबाइल गृहिणी प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित है –

1. ग्रामीण महिलाओं में छिपे अच्छे गुणों और शक्तियों को विकसित करके, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक गुणों के विकास में सहायता देना।
2. महिलाओं को शोषण, अत्याचार और बलात्कार से बचाना।
3. साक्षर बनाना।
4. पारिवारिक जीवन में अच्छी पत्नी, आदर्श बहु एवं कुशल माँ बनाना तथा गाँव में नेतृत्व के लिए तैयार करना।
5. आर्थिक रूप से सबल होने के बाद रहन सहन में परिवर्तन लाना।
6. विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देना तथा इन योजनाओं से लाभ उठाने के लिए सिखाना।

प्रशिक्षण हेतु विषयवस्तु :–इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्न विषयों की जानकारी एवं प्रशिक्षण दी जाती है :–

1. अक्षर ज्ञान।
2. स्वास्थ्य शिक्षा।
3. गृह प्रबंध और आहार विज्ञान।
4. देशी जड़ी–बूटी द्वारा इलाज।
5. एक्यूप्रेशर।
6. भोज्य पदार्थों का संरक्षण।
7. मशरूम उत्पादन।
8. पर्यावरण की सुरक्षा।
9. बचत योजना।
10. किंचन गार्डन।
11. मातृ कला।
12. सिलाई–बुनाई तथा सिलाई मशीन का ज्ञान।

13. सामाजिक और पारिवारिक जीवन तथा ग्रामीण स्तर पर आय वृद्धि साधन की शिक्षा।
14. सांस्कृतिक कार्यक्रम।

मोबाइल शिक्षा देने की व्यवस्था क्लास रूम तक ही सीमित नहीं है। बल्कि महिलाओं के द्वारा निर्धारित विभिन्न स्थानों में यथा–घरों, खेतों, कुआँ के पास या अनयंत्र कहीं भी मोबाइल शिक्षा, शिक्षिकाओं के द्वारा दी जाती है।

इस प्रशिक्षण में महिलाओं की रूचि के अनुसार शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग के लोगों के लिए अलग–अलग क्लास की व्यवस्था की जाती है। महिलाएँ सिलाई–बुनाई, पकवान, आचार, हस्तकला आदि सीखना चाहती है तो वे स्वयं सामग्रियों की व्यवस्था करती है।

प्रत्येक मोबाइल गृहिणी केन्द्र के लिए एक सिलाई मशीन, महिला जागृति केन्द्र कुनकुरी से प्राप्त होती हैं। छः महीने प्रशिक्षण के पश्चात् प्रत्येक मोबाइल गृहिणी केन्द्र में महिला दिवस मनाने का आयोजन किया जाता है। इस समारोह को सफल बनाने में गाँव के बुजुर्ग, युवक एवं युवतियों का सहयोग रहता है। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विकास कार्य निर्देशक एवं सीनीय पल्ली पुरोहित विशेष रूप से आमंत्रित किये जाते है।

महिलाओं द्वारा बनायें गये सिलाई, बुनाई, आचार विभिन्न प्रकार के पकवान, मलेरिया एवं साधारण बुखार के लिए देशी जड़ी–बूटी द्वारा बनाये गये गोली, दर्द निवारक तेल, शिरॉफ, विभिन्न प्रकार के टॉनिक जैसे–मुनगा साग, ऑवला, जामुन रस, गुलहड़ फूल, गुलाब फूल, चिधरी फूल, मेंढ़क साग(ब्रम्ही आंवला), सींठा घास, केला, कठहल आदि का टॉनिक बनाकर प्रर्दशनी में सजाया जाता है। विषय के आधार पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है जिसमें क्षेत्रीय नाच–गान, कव्वली, कॉमिक्स किया जाता है। इसका संचालन महिलाएं स्वयं करती है। इन प्रशिक्षित महिलाओं की खुशी एवं उत्साह बढ़ाने के लिए खेल–कूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। इस प्रतियोगिता में पारितोषिक वितरण किया जाता है।

सन् 1992 ई. 2001 ई. तक 158 गाँवों में 6375 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से 3485 महिलाएं अपने परिवार एवं गाँव के विकास कार्यों में आगे आयी है और मोबाइल गृहिणी के उद्देश्यों को पूर्ण कर रही है। इन महिलाओं के द्वारा कई गाँवों में बचत योजना शुरू की गई है। गाँव में शराब सेवन पर पाबंदी लगाई गयी है। स्वयं सहायता दलों के द्वारा लगभग 10 गाँवों में दैनिक आवश्यकता की छोटी दुकानें खोली गयी है। इस प्रकार मोबाइल गृहिणी के अतंर्गत प्रशिक्षित महिलाओं के द्वारा अनेक कार्य{मों का संपादन हो रहा है।

मोबाइलगृहिणी के अंतर्गत 'बचत योजना' –

सन् 1993 ई. में जशपुर जिले के गिनाबहार केरसई, बांसेन और जोकबहला की कुछ महिलाओं को तीन दिन का हजारी बाग(झारखण्ड) में बचत कार्यक्रम और मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के पश्चात् सन् 1993 ई. में ही 10 गाँवों में 'बचत कार्यक्रम' शुरू किया गया।

बचत योजना के उद्देश्य :–

1. अपनी आय में वृद्धि करना।
2. बचत करने की आदत डालना।
3. आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना।
4. एकता और संगठन को मजबूत बनाना।
5. सेठ साहूकारों के कर्जो से छुटकारा पाना।
6. परिवार एवं गांवों का विकास करना।
7. महिलाओं के शक्ति को बढ़ावा देना।

'बचत योजना' शुरू करने के पश्चात् इन गाँवों में स्वयं सहायता दल द्वारा सामुदायिक कार्य प्रारंभ किया गया। जिसे गाँव में लोग संगत कार्य कहते है। जिसमें गाँव के सभी लोग मिलकर एक निश्चित तिथि को किसी एक परिवार का कोई भी कार्य करते है। इस सामुदायिक(संगत) कार्य द्वारा गाँव के लोगों के सभी प्रकार के कार्य सरल हो जाते है।सन् 1993 ई. से 2001 ई. तक कुल 19 पैरिस के 158 गाँवों में 171 दलों में बचत कार्यक्रम चल रहा है। जिसमें महिलाओं की कुल संख्या 3375 है और इस कार्यक्रम के तहत आज तक लगभग 5 लाख रूपये जमा किये जा चुके है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. नॉन फॉरमल एजूकेशन फॉर उमेन 1980 – पृ. 16
2. रायगढ़ धर्म प्रान्तीय स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 1851–2001
3. पूर्वोक्त – पृ. 43–44
4. अनुभव रायगढ़ अम्बिकापुर हेल्थ एसोसिएशन – पृ. 14
5. दी कैथोलिक डायरेक्टरी ऑफ इंडिया 1990 – पृ. 686
6. दी कैथोलिक डायरेक्टरी ऑफ इंडिया 2005–06 – पृ. 1123
7. कार्यालयीन दस्तावेज– कार्यालय प्रभारी विशप हाऊस कुनकुरी (छ.ग.)
8. साक्षात्कार संचालिका गृहिणी शिक्षा योजना दिनांक 11.10.06
9. छोटा नागपुर सर्वे II लीवन्स शताब्दी स्मारिका 1985 – पृ. 40–41
10. पूर्वोक्त – पृ. 93–94
11. टोप्पों फा. पौल – खीस्त हमारी ज्योति और मुक्ति –पृ. 130

जनजातीय अर्थ–व्यवस्था और औद्योगिक प्रभाव

ज्ञानेन्द्रधर बड़गैया, शोधार्थी, एम.ए. समाजशास्त्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर म.प्र

जनजातीय अर्थव्यवस्था–भारत की जनजातीय अर्थव्यवस्था का व्यापक अध्ययन सर्वप्रथम दो अर्थशास्त्रियों यथा डी. एस. नाग तथा आर. पी. सक्सेना ने क्रमशः 1958 एवं 1964 में किया। यहाँ नाग ने मध्यप्रदेश के मंडला, बिलासपुर, दुर्ग और बालाघाट के बैगा जनजातीय क्षेत्रों का दौरा कर बैगा–अर्थव्यवस्था का अध्ययन प्रस्तुत किया, वहीं सक्सेना ने नाग द्वारा प्रतिपादित अध्ययन सूत्रों के माध्यम से मध्यप्रदेश के ही पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र का अध्ययन कर वहाँ के पाँच जनजातीय समूहों की अर्थव्यवस्था की जानकारी दी। इन दानों अध्ययनों के पूर्व विभिन्न नृविज्ञानियों यथा विद्यार्थी (1963),राय (1976)ने अपने नृजातिवर्णन विनिबंधों के माध्यम से जनजातीय अर्थव्यवस्था का वर्णन प्रस्तुत किया। विद्यार्थी ने ''मालेर''' अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हुए इसे पहाड़ी कृषि के वृत्ताकार चक्र पर घूमता हुआ कहा तथा राय ने आधी से अधिक अर्थव्यवस्था को जंगल एवं पहाड़ों पर निर्भर पाया। उपरोक्त उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि भारत की जनजातीय अर्थव्यवस्था का वृहद भाग प्रकृति पर निर्भर है। नृ–विज्ञानियों ने अपने जनजातीय समाजों के अध्ययन के माध्यम से तीन प्रकार की अर्थ–व्यवस्थाओं की चर्चा की है –

प्रथम– जो वन पशुओं के शिकार तथा कंद–मूल–फलों के संचय पर निर्भर है।

द्वितीय– जो पशुपालन पर निर्भर हैं।

तृतीय– कृषि या पशुपालन मिश्रित कृषि पर आधारित है। ये तीनों प्रकार मानवीय संस्कृति के विकास के विभिन्न चरणों में अपनाये गये साधनों का प्रतिनिधित्व करतें हैं।

जनजातीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण–

विभिन्न विद्वानों ने जनजातीय अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया है।

भारत की जनजातियों में अर्थव्यवस्था सर्वत्र् मिश्रित् प्रकार की पायी जाती है। डी. एन. मजूमदार(1966) ने इसे प्रथमतः तीन श्रेणियों में विभाजित किया–

(1) आखेटन एवं संग्रह की अवस्था

(2) स्थानान्तरित एवंझूम कृषि

(3)व्यवस्थित या स्थायी कृषि

कुछ समयोपरांत मजूमदार ने टी. एन. मदान के साथ मिलकर इस वर्गीकरण का पुर्नमूल्यांकन करते हुए 1970 में नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने इसे छः श्रेणियों में विभक्त किया।

(1)खाद्य–संकलन (2) कृषि (3)स्थानान्तरित कुल्हाड़ा कृषि (4) दस्तकारी (5) पशुचारण (6) औद्योगिक श्रमिक

श्यामाचरण दुबे ने 1969 में भारतीय जनजातीय अर्थव्यवस्था को दो मुख्य वर्गों में बाँटा है–

(1) महत्वपूर्ण –(क)खाद्य–संकलन

(ख)अव्यवस्थित प्राथमिक कृषि (ग) व्यवस्थित प्राथमिक कृषि

(2)अर्ध्द महत्वपूर्ण (घ) पशुपालन

(ड़) निर्दिष्ट काश्तकारों एवं उद्योग से जीवन यापन करने वाली जनजातियाँ

(च) अपराध वृत्ति से जीवन यापन करने वाली कुछ जनजातियाँ।

तारक चन्द्र दास ने 1967 में पाँच प्रकार के वर्गीकरण प्रस्तुत किये–

(1) यायावर, खाद्य–संकलन तथा पशुचारक

(2) पर्वतीय ढलानों पर स्थानान्तरित कृषि कारक

(3) पठार एवं तराई क्षेत्रों के हल – कृषि कारक

(4) हिन्दू समाज व्यवस्था को अंशतः आत्मसात करने वाली जनजातियाँ

(5) आत्मसातकृत जनजाति जिन्होंने हिन्दू समाज में स्थान पा लिया है।

योगेश अटल ने 1965 में जनजातीय अर्थव्यवस्था को चार वर्गों में विभक्त किया–

(1) खाद्य–संकलन (2) स्थानान्तरित कृषि, सह खाद्य संकलन(3) व्यापार (4) यायावर और पशुचारक

जे. एच. हट्टन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए भारत की जनजातीय अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बाँटा है–

(1) वन खाद्य–संकलन (2)पशुचारक (3) कृषि, आखेटन, मत्स्यमारक एवं उद्योगजीवी

इन सबको ध्यान में रखते हुए ललिता प्रसाद विधार्थी ने 1978 में इन्हें निम्नलिखित आठ प्रमुख वर्गों में बांटा है जिसे भारत की जनजातीय अर्थव्यवस्था कों पूर्णता में समेटने का सफल प्रयास माना जायेगा।

(1) वन्य–आखेटक

(2) पहाड़ी कृषि,

(3) मैदानी कृषि,

(4) सरल कारीगर

(5) पशुचारक

(6) लोक–कलाकार

(7) कृषि कार्य एवं अन्य श्रमिक

(8) कुशल श्रमिक, सफेदपोश नौकरी एवं व्यापारी

जनजातीय अर्थ–व्यवस्था पर औद्योगिक प्रभावः–

भारत में औद्योगीकरण का प्रभाव सम्पूर्ण जनजीवन पर पड़ना प्रारम्भ हो चुका था, तो जनजातियाँ इससे कैसे अछूती रह जाती। बहुतायत में जनजातीय संस्कृति भी आर्थिक परिवर्तन के आधार परिवर्तित हो रही है। औद्योगीकरण के प्रभाव के कारण ही जनजातियों की दो नई श्रेणियाँ मजदूर वर्ग तथा सफेदपोश नौकरी वाली बनी है। यह इस बात का द्योतक है कि जनजातिय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक प्रभाव महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी सिद्ध हो रहा है।

अधिकाधिक शहरी प्रभाव में आने के कारण शिक्षा का अच्छा प्रसार हुआ है। जिससे शहरों के औद्योगिक क्षेत्र रोजगार में संलग्न होने लगे। जनजातीय क्षेत्रों में अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना तथा विभिन्न खनिज खदानों का होना जनजातियों को मजदूरी या अन्य कुशलकर्मी के रूप में रोजगार प्रदान करता है। इसके कारण ये अपनी परम्परागत कृषि छोड़कर सामयिक रूप से विभिन्न उद्योगों वाले स्थानों, मिलों, कारखानों, चाय बगानों आदि में कार्यरत् हैं। दूर शहरों में जाकर इन्होंने गृह निर्माण कार्य, कारखानों, बाँध–पुल निर्माण कार्यों में मजदूरी करना प्रारम्भ कर दिया है। ये कार्य करने वालों में छोटा नागपुर में स्त्रियों की भी पर्याप्त संख्या शामिल है। 1961 की जनगणना के अनुसार 3.42 प्रतिशत जनजाति मजदूर खदानों आदि से संबंधित थे।

जनजातीय अर्थव्यवस्था पर औद्योगिक प्रभाव से पारम्परिक अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों में काफी परिवर्तन हो गया है। उस व्यवस्था ने वर्तमान संदर्भ में अपनी मान्यता खो दी है। इसके स्थान पर उन लोगों ने नये कार्य यथा रिक्शाचालक, कारखाना मजदूरी, मशीन चालन का कार्य अपना लिया। आज छोटा नागपुर के उरांव, मुण्डा जनजाति के काफी लोग उद्योगों में कार्यरत् हो चुके हैं जबकि उद्योगों की स्थापना के पूर्व वे पूर्णतः कृषि कार्य पर आधारित थे। उत्तर–पूर्वी भारत के चाय बागानों में भी काफी मजदूर छोटा नागपुर क्षेत्र के जनजाति समुदाय के है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी विभिन्न रूपों में कार्य करने वाली यहाँ की जनजातियों की बहुतायत है। संथाल जनजाति के लोग खदानों में कोयला खनन में लगे हैं। मध्यप्रदेश के मैगनीज उद्योग में 50 प्रतिशत जनजातीय मजदूर कार्य कर रहें हैं। इसमें दो मत नहीं कि उद्योगों की

स्थापना के बाद जनजातियों को नियोजन का अच्छा साधन मिल गया है। इस औद्योगीकरण के कारण जनजातीय गाँव में पारम्परिक अर्थ–व्यवस्था ध्वस्त होने लगी है तथा अधिकाधिक लोग इन व्यवसायों की ओर आकर्षित हो रहें हैं। इस व्यवसाय परिवर्तन से इन परिवारों की आय में काफी वृद्धि हुई हैं। जनजातियों की अधिकाधिक संख्या आज उद्योग सम्पन्न राज्यों यथा–बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात आदि के औद्योगिक संस्थानों की ओर विस्थापित होती रहती है।

उपसंहार– भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिये महिला शिक्षा का महत्व अत्यधिक है। समाज के सम्पूर्ण मानव स्त्रोंतो के दोहन एवं विकास, मानवीय घरों के समुचित विकास, बच्चों के चरित्र निमार्ण, जनसंख्या वृद्धि की रोक आदि के लिए भारतीय महिलाओं की समुचित शिक्षा व्यवस्था अत्यधिक आवश्यक है। परिवारों की उन्नति एवं शैशवास्था के वर्षों में बच्चों के चरित्र निमार्ण के लिए महिलाओं की शिक्षा का महत्व पुरूषों की शिक्षा से भी अधिक हैं।

आज दुनियाँ भर में बालिकाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी है और उनकी दशा सुधारने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। लड़कियों के अस्तित्व और संपूर्ण विकास के प्रति बढ़ती चिंता के परिणाम को देखते हुए सार्क देशों के शासनाध्यक्षों और राष्ट्राध्यक्षों ने सन् 1990 के दशक को सार्क बालिका दशक के रूप में मनाया।

भारत सरकार ने सार्क बालिका दशक 1990–2000 में अलग से एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की, जिसमें बालिकाओं के लिए लिंग आधारित लक्ष्य निर्धारित किये गये, जो निम्नलिखित है–

1. बालिकाओं को उनकी पारंपरिक भूमिका और पूर्वाग्रह से बंधी बेड़ियों से मुक्त करके उन्हें राष्ट्रीय विकासमें समान दर्जे के साथ मुख्याधारा से जोड़ कर दनका सर्वागींण विकास करना।

2. कठिन परिस्थितियों, आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग जैसे विशेष वर्गों की संवेदनशील बालिकाओं को विशेष संरक्षण।

बालिका समुदाय, समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका आत्मबल , परिवार और समाज में योगदान बढ़े, जिसके लिये अनिवार्य शिक्षा, हमारे सहयोग और प्रोत्साहन की आवश्यकता है, इसी में हम सभी का कल्याण है।

नये समाज की रचना के लिए बाधक है –पुराने रीति–रिवाज, अधंविश्वास, कुप्रथाएं। समाज में व्याप्त छुआछूत, ऊँच–नीच के भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, जातिगत संकीर्णता। इन कुरीकतयों को मिटाना चाहते हैं तो समाज की कमजोर और पिछड़ी जातियों की बालिकाओं को शिक्षित करना होगा।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं को प्राथमिक स्तर तक शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए, किंतु इतने प्रयासों के बावजूद अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा संबंधी समस्या निरंतर बनी हुई है। इसको ज्ञात करना अति आवश्यक हो जाता है। प्राथमिक स्तर तक सभी को शिक्षित करने के लक्ष्य को पूरा करने में हम तभी सफल हो सकते हैं। जब अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या को दूर किया जाये।

जनजातीय समाज :

आज भी ऐसे अनेक मानव समूह हैं, जो दुर्गम क्षेत्रों में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। हजारों वर्षों से शेष विश्व की सभ्यता से दूर अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की पहचान बनाये हुए हैं। ये मानव–समूह बीहड़ वनों, मरूस्थलों, ऊँचे पर्वतों और पठारों के ऊँचे अंचलों में निवास करते हैं। इन मानव समूहों को ''आदिवासी '' , ''वनवासी'', ''जनजाति'' आदि नाम से सम्बोधन किया जाता है।

विभिन्न विद्वानों द्वारा जनजाति शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया है। **डी. एन. मजूमदार** के अनुसार जनजाति परिवारों का एक समूह होती है जिसके सदस्य एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, एक ही क्षेत्र में निवास करते हैं, विवाह तथा पेशों से संबंधित समान निषेधों का पालन करते हैं, तथा उनके बीच सुविकसित पारस्परिक विनिमय तथा आपसी लेन–देन की व्यवस्था पाई

जाती हैं इसी तरह **आर. एन.मुखर्जी** के अनुसार उस मानव समूह को जनजाति कहा जाता है जिसके सदस्य आम अभिरूचि, प्रदेश, भाषा, सामाजिक नियम तथा आर्थिक पेशों से बंधे होते हैं। देश की जनजातियों का संवैधानिक नाम अनुसूचित जनजाति (शेड्यूल्ड ट्राइब) है। **वेरियर एल्विन**, जिन्होंने भारतीय जनजातियों पर विस्तार से तथा आधिकारिक तौर पर लिखा है, जनजातियों के लिये ''ओरिजनल ओनर्स'' शब्द उपयुक्त मानते हैं। **गिलिन एवं गिलिन** के मतानुसार स्थानीय जाति–समूहों का एक ऐसा समुदाय जनजाति कहलाता है, जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति है।

जनजातीय स्थिति :विश्व में, अफ्रीका के बाद भारत जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। देश की कुल जनसंख्या का 9.08 प्रतिशत भाग हमारे जनजातीय बन्धुओं द्वारा निर्मित है तथा देश की सर्वाधिक जनजातियाँ मध्यप्रदेश में निवास करती हैं। यहाँ कुल 46 जनजातियाँ पायी जाती है। जिनमें से विशेष पिछड़ी जनजातियाँ भी है। गौंड जनजाति संख्या की दृष्टि से मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इस कारण मध्ययुग में गोंडवाना को प्रसिद्धि मिली है।

जनजातियाँ न केवल संस्कृति , समाज और आर्थिक दशाओं की दृष्टि से सामान्य वर्ग के लोगों से भिन्न है, बल्कि उनके जनसंख्यात्मक गुण भी अलग हैं। आदिवासियों में स्त्री–पुरूष अनुपात ऊँचा है। प्रजनन दर अधिक होने से वृद्धि दर भी तेज है। विवाह सार्वभौमिक है तथा विधवा के पुनर्विवाह पर प्रतिबंध नहीं है। फलतः परिवार का बड़ा होना स्वाभाविक है। इनमें अल्प आयु में विवाह का प्रचलन आज भी स्पष्टतः देखा जा सकता है।

जनजातीय शिक्षा : शासन द्वारा अदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सर्वाधिक जोर शिक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार पर दिया गया है। निरन्तर यह प्रयास किया जाता रहा है कि आदिवासी बच्चें गरीबी अथवा अन्य कारणों से शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहें।

शिक्षा के प्रचार हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जिनमें से छात्रवृत्ति वितरण प्रमुख है। प्रतिभाशाली आदिवासी विद्यार्थियों को प्रावीण्य छात्रवृत्ति, कन्या शिक्षा को बढ़वा देने के उद्देश्य से कम साक्षरता वाले विकासखण्डों में अनुसूचित जनजातियों की छात्राओं को नगद प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है। साथ ही मुफ्त पुस्तक वितरण एवं गणवेश वितरण की योजना भी कार्यान्वित है। माता–पिता के भार को कम करने तथा बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के दृष्टिकोण से मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम भी चलाया गया है। इसके साथ–साथ छात्राओं को शासन द्वारा साईकिल भी प्रदान की जा रही है जिससे विद्यालय की दूरी शाला त्यागने का कारण न बन सके। इसके अतिरिक्त आदर्श विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की गई। छात्रावासों, आश्रम शालाओं एवं क्रीड़ा परिसरों की संख्या में भी आशातीत वृद्धि की गई। छात्रावासों, आश्रम शालाओं एवं क्रीड़ा परिसरों की संख्या में भी आशातीत वृद्धि हुई है। कम पढ़े–लिखे आदिवासी युवकों तथा युवतियों हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित किये जा रहे हैं। साथ ही साथ आदिवासी युवकों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिये भी शासन द्वारा समय–समय पर व्यवसायगत प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है।

शासन द्वारा आदिवासी शिक्षा के प्रसार हेतु किये गये प्रयासों से आदिवासी समाज में शिक्षा का संचार अवश्य हुआ है किन्तु आज भी आदिवासी समाज शैक्षिक दृष्टि से बहुत पीछे है जो उनके विकास के मार्ग में बाधा का बहुत बड़ा कारण है। इसका आभास इसी से होता है कि राज्य की कुल आदिवासी जनसंख्या में से सन् 1991 तक मात्र 16.88 प्रतिशत ही साक्षर हो सकी। शेष 83.12 प्रतिशत अब भी निरक्षर हैं। यह साक्षरता वर्ष 1971 में अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता11.30 प्रतिशत थी, जो 1981 में 16.35 प्रतिशत हो गई तथा 1991 में साक्षरता बढ़कर 29.6 प्रतिशत हो गई है। 1971 में पुरूष साक्षरता 17.63 प्रतिशत तथा 1981 में पुरूष साक्षरता 24.52 प्रतिशत थी। जबकि जनजातियों के मध्य 1971 में महिला साक्षरता मात्र 4.85 प्रतिशत तथा 1981 में महिला साक्षरता प्रतिशत 8.04 प्रतिशत हो गई थी। वर्ष 1991 में पुरूष साक्षरता जनजातियों की बीच 40.65 प्रतिशत थी, जबकि महिलाओं के बीच साक्षरता 18.19 प्रतिशत थी। हालांकि विगत वर्षों में जनजातियों की साक्षरता में वृद्धि हुई है, लेकिन यह

सामन्य स्तर से बहुत कम है। महिलाओं में साक्षरता की स्थिति तो और दयनीय है।

स्वतंत्रता के साठ वर्षों के बाद भी मध्यप्रदेश में आदिवासी साक्षरता अत्यधिक सोचनाय स्थिति में है। आज भी बहुसंख्यक आदिवासियों को लिखना और पढ़ना नहीं आता है। प्राथमिक स्तर के सामान्य शिक्षा से भी वे वंचित है। आदिवासी अंचलों में हिन्दी माध्यम के कारण लोगों में पढ़ने के प्रगति रूचि जागृत नहीं हो पायी।

सामाजिक पृष्ठभूमि :समानता के संदर्भ में मानव अधिकारों की विवेचना विशेषतः लिंग भेद के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिंग भेद से स्थायी विषमताएँ, असंतोष और मानवता की हानि जैसी परिस्थितियाँ सामने आई है। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने सामाजिक अवसरों को सभी के लिए व्यापक स्तर पर खेलने की आवश्यकता को विकास का मूल मुद्दा बताया है। लिंग आधरित भेदभाव विकसित, अविकसित, सभ्य–असभ्य समाजों में व्यापक या सूक्ष्म रूप में अवश्य मौजूद है और जब तक समान अवसरों को स्त्रियों के लिए व्यापक स्तर पर उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक कोई सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक उपलब्धि, राजनैतिक सत्ता, समाज में शान्तिपूर्ण, सुरक्षित एवं पोषणीय विकास की नींव नहीं डाली जा सकती।

सभी क्षेत्रों में प्रगति एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिए लिंग की समानता और महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के सिद्धान्तों को विश्व भर में एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में स्वीकार किया गया। महिलाओं के विकास और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में 18 दिसम्बर 1979 को महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार का भेदभाव समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव पारित किया। जो 3 सितम्बर 1981 से प्रभावी हुआ। ग्रामीण महिलाओं की विशेष समस्याओं और उनके पारिवारिक जीवन के अस्तित्व को बनाये रखने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को भी रेखांकित किया गया। किन्तु अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर अनेक समझौतों के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति दूसरे दर्जे की है। विश्व स्तर पर प्रौढ़ निरक्षरों में दो–तिहाई महिलाएँ हैं। विश्व के निर्धनों में 70 प्रतिशत महिलाएँ हैं। मातृ दर और शिशु मृत्यु दर अत्यंतउ च्च है। साक्षरता में सभी स्तरों पर लिंग संबंधी अंतराल बहुत गहार है। बालिकाओं में स्कूली शिक्षा के मध्य में ही शाला छोड़ने की दर अधिक ऊँची है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएँ निरंतर बढ़ती जा रही है।

आदिवासी बालिकाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं शिक्षा : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन जबलपुर से 65 किलो मीटर दूर स्थित निवास तहसील के अतंर्गत निवास विकासखण्ड के 105 गांवों का अध्ययन है। आदिवासी बहुल क्षेत्र निवास में तीन विकासखण्ड सम्मिलित है – निवास, बीजाडाण्डी एवं नारायणगंज। इन विकास खण्डों में क्रमशः 105, 128 एवं 78 गांव है। सरकारी योजना के तहत सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य पर शासन की ओर से 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के समस्त बच्चों को स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना, ब्रिज कोर्स पाठ्यक्रमों में सम्मिलिति करने हेतु प्रत्येक गांव में शासन की ओर से जनपद पंचायत के माध्यम से जनपद शिक्षा केन्द्र प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक, हायर सेकेण्डरी विद्यायलों की स्थापना की गई है तथा शाान की ओर से प्रत्येक आदिवासी परिवार के बालक एवं बालिकाओं इन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभिन्न सुविधाएं प्रदान करनें का लक्ष्य निर्धारित कर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर बल देते हुए वर्ष 2010 तक सभी को शिक्षा मुहैया कर समस्त प्रकार के भेदभाव मिटाकर समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।

प्रस्तुत अध्ययन में सुविधाजनक निदर्शन प्रणाली से उत्तरदाताओं का चुनावउ किया गया धन, समय व साधन की उपलब्धता के आधार पर निवास संकुल क्षेत्र के आठ गांवों में 20 विद्यालयों का चुनाव किया गया तथा विद्यालयों में प्रत्येक स्तरों में उपयुक्त बालिकाओं को चुनकर, चुनी हुई 268 बालिकाओं के अभिभावकों से सम्पर्क किया गया। सर्वप्रथम समग्र की सभी विशेषताओं की प्राथमिकजानकारी प्राप्त कर प्रत्येक वर्ग में से इकाइयों से संबंधित अभिभावकों से घर पर जाकर प्राथमिक अध्ययन हेतु विषय से संबंधित एक प्रश्नावली अनुसूची का निर्माण कर निर्वाचित विद्यार्थियों के परिवार में जाकर जिम्मेदार सदस्य से जानकारियाँ प्राप्त की गयी। कुल 5628 से चयनित 268 बालिकाओं को अध्ययन हेतु सम्मिलित किया गया।

वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन

डॉ. ध्रुव कुमार दीक्षित, प्राध्यापक समाजशास्त्र केसरवानी महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

'वैश्वीकरण' का अर्थ है विश्व की अर्थव्यवस्था का देश की अर्थव्यवस्था में एकीकरण होना अर्थात् अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना। 1984 में स्वर्गीय राजीव गांधी के सत्ता में आने के बाद आधुनिकीकरण के साथ–साथ नीतियों में भी पश्चिमीकरण की छाया आने लगी। 1991 में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई जिसमें प्रमुखतत्व निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण है। जब सरकार, उद्योगों एवं व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर निजी उद्योगों एवं व्यापार को अपना विकास करने का पूरा–पूरा अवसर प्रदान करती है तो उसे निजीकरण कहा जाता है। उदारीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शासकीय नियंत्रणों को शिथिल करके अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का विस्तार करते हुये अर्थव्यवस्था को बाजरोन्गुणी बनाया जाता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत निर्बाध व्यापार प्रवाह, निर्बाध पूँजी प्रवाह, निर्बाध टेक्नोलॉजी प्रवाह और निर्बाध श्रम प्रवाह आता है।

'वैश्वीकरण' का वास्तविक अर्थ है–व्यक्ति को व्रहत्तर समाष्टि से जोड़ना। वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा या संप्रत्यय है जिसमें उदारीकरण के नाम पर पूँजी का मुक्त आवागमन प्रारंभ हुआ। समाजशास्त्री एंथोनी गिडेन्स के अनुसार, आज सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्ध ऐसे हैं। बहु–राष्ट्रीय कंपनियों का विश्व के सभी देशों में प्रवेश और उपभोक्तावाद ही वैश्वीकरण का मुख्य पोषक व संरक्षक है। भारतीय अवधारणा ''वसुधैव कुटुम्बकम'' से बिल्कुल विपरीत अवधारणा ही वैश्वीकरण की है। वैश्वीकरण संपूर्ण विश्व को एक परिवार में परिवर्तित नहीं करता है बल्कि उसे एक बाजार में बदलता है जिसमें हर वस्तु की कीमत वहीं निर्धारित करता जिसमें उस बाजार को नियंत्रित करने की ताकत होती है। वैश्वीकरण से भारतीय समाज में वयापक परिवर्तन हुये है। पहरवार, समाज, राज्य से होता हुआ युवाओं; महिलाओं और बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है।

वैश्वीकरण का प्रभाव–(1) परिवार में बदलाव।

(2) उत्पादन का ढाँचा प्राथमिक क्षेत्र से विर्निमाण व सेवा क्षेत्र में श्रम का पलायन होने से कुटीर उद्योगों की समाप्ती।

(3) पेशेवर शैक्षणिक क्रांति का उद्भव प्रारंभ हुआ।

(4) संचार क्रांति जिससे पारिवारिक पर्जनायें समाप्त हो गयी।

(5) बेरोजगारी में वृद्धि होना।

वैश्वीकरण ने सर्वाधिक प्रभावित किया भारतीय परिवारों को। संयुक्त परिवार औद्योगीकरण के कारण जहाँ एकल परिवारों में परिवर्तित हुये वहीं वैश्वीकरण के कारण ये एकल परिवार भी टूट कर, भग्न परिवारों में बदल रहे है। बढ़ती तलाक की दर के कारण एकल परिवार बिखर रहे है। परिवार का दायित्व बाजार के हाथ में आ गया है।

पूरे विश्व के लिये भारतीय बाजारों के खुलने और उदारीकरण होने से भारत में विदेशी सस्ता सामान आने से भारतीय उद्योग आज धीरे–धीरे बंद होते जा रहे है। चीन ने लागत से भी कम कीमत पर सामान भारतीय बाजार में पहुँचा दिया जिसके चलते हमारे कुटीर उद्योग बंद होते जा रहे है। वहीं वैश्वीकरण ने भारत में कम्प्यूटर साफ्टवेयर–हार्डवेयर की शुरूआत की जिसमें आज भारतीय बच्चे एक नई किस्म की मानसिक गुलामी का शिकार हो रहे है। कम्प्यूटर साफ्टवेयर का ज्ञान बाबुओं का एकवर्ग तैयार कर रहा है। बच्चे कम्प्यूटर शिक्षा लेकर विभिन्न कंपनियों में कार्य कर रहे हैं, जहाँ उन्हे पैसा तो खूब मिल रहा है लेकिन उन कंपनियों में उनकी जवानी खत्म हो रही है।

वैश्वीकरण से आज भारत में एक नये तरह की पेशेवर शैक्षणिक क्रांति पैदा हुई है। आज कॉलेजों में दो तरह के विद्यार्थी है,एक बेहद पढ़ाकू किस्म के, जिन्हें दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं होता है। दूसरे मौज मस्ती वाले छात्र जो अपना पारिवारिक व्यापार संभालते हुये पढ़ रहे हैं, जिनका एक मात्र उद्देश्य डिग्री लेना है। उनके लिये जिंदगी सिर्फ मौज–मस्ती है उन्हें सामाजिक सारोकारों से कोई मतलब नहीं है।

संचार क्रांति ने आज परिवार, विवाह, नारीत्व, मातृत्व की भूमिका को बदल डाली है। डेंटिग, एवारशन, सिंगल पेंरेट, लिव इन रिलेशन, पोर्न फिल्मों का बढ़ता संजाल भारतीय समाज को भ्रष्ट कर रहे है। अश्लील विज्ञापन हमारे व्यापार की आवश्यकता बनते जा रहे है। ब्लू फिल्म, अश्लील मैसेज आज भारत के 80 करोड़ मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में अपना स्थान बना चुके है। जिन्होंने भारतीय पारिवारिक वर्जनाओं को समाप्त कर दियाहै। गरीबी की बढ़ती खाई के कारण कोख बिक रही है। बाजार आज औरत पर हो निर्भर है।

वैश्वीकरण ने सिर्फ हमारे समाज को ही नहीं बल्कि हमारी संरचना को भी बदल डाला है। देश में उपभोग, संस्कृति बढ़ रही है और इस उपभोग संस्कृति नेसमाज मेंएक बनावटी आवश्यकता को जन्म दिया है। वैश्वीकरण के कारण आज Act cocol think global के कारण समान में प्रतियोगिता बढ़ रही है। आज शिक्षा प्रतियोगिता में बदल गई है। समाज में नवधनाढ़यों में वृद्धि हुई है।मोल कल्चर बढ़ रहा है। ब्रांडेड का जोर चल रहा है। ऑन लाइन व्यापार सेवा के कारण छोटे–छोटे नगरोंमें भी बड़ी–बड़ी कंपनियों के उत्पादों ने अपनी पहँच बनाती है।ई–चौपाल, ई–प्रशासन, तेली मेडिसिन, किसान कॉल सेंटर, एक सकारात्मक पहल है। आज समाज में सामूहिक आनंद का स्थान एकाकी सुख ने ले लिया है अर्थात् मनुष्य की सारी सोच ''ने'' और मेरा परिवार तक ही सीमित होकर रह गई है। समस्त जीवन यंत्रवत् व नीरस होता जा रहा है, भावनायें समाप्त होती जा रही है जो सामाजिक विघटन, डिप्रेशन को जन्म देता है।

'मोबाईल' फोन को पाश्चात्य देशों ने भारत में सूचना क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया लेकिन आज यह छोटा सा खिलौना परिवार को समाप्त कर देता है।हम अपने तक सीमित रहने के लिये पीले बच्चों को मोबाईल फोन में उलझाते है फिर शनैः शैनेः बच्चा उसमें उलझ कर रह जाता है। मोबाईल फोन के कारण आज प्रारंभ हुई ''सेल्फी'' की प्रवृत्ति के कारण नये–नये हादसों में युवा फंसते जा रहे है।

वैश्वीकरण के इस युग में हिन्दी की भूमिका : भारतीय व्यापार के सन्दर्भ में

अर्जुन शुक्ला (गोल्ड मेडेलिस्ट), शोधार्थी, जन्तु विज्ञान विभाग, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

शोध सारांश : अंतरराष्ट्रीय एकीकरण में भाषा की भूमिका और व्यापकता विश्व में उसके स्थान को सुनिश्चित करती है, भाषा की इस आधुनिक दौड़ में दुनिया की तमाम भाषाओं की भांति हिंदी के स्वरूप, क्षेत्र एवं प्रकृति में बदलाव आया है, प्रसार में वृद्धि हुई है। हिंदी न सिर्फ भारतीय मंडल अपितु समूचे भूमंडल की एक प्रमुख भाषा के रूप में उभरी है। यह हकीकत है कि 90 के दशक में विश्व बाजार व्यवस्था के तहत बहुप्रचारित उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की प्रकृति से भारत अछूता नहीं रह सकता था। देरदृसबेर उसे भी वैश्विक मंडी में खड़ा होना ही था। जाहिर है इस वैश्वीकरण ने जहाँ एक तरफ मुक्त बाजार की दलीलें पेश की, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में एक नई उपभोक्ता संस्कृति को जन्म दिया, जिससे जनजीवन से जुड़ी वस्तुएं ही नहीं, भाषा, विचार, संस्कृति, कला सबदृकुछ को एक 'कमोडिटी' के तौर पर देखने की प्रवृत्ति विकसित हुई।

वैश्विक बाजार संस्कृति के लिए हिंदी सबसे अनुकूल भाषा के रूप में अपनाई जा रही है। इससे हिंदी का विकासदृ विस्तार तो हो ही रहा है, संपूर्ण राष्ट्र में भाषिक संपन्नता की परिचय भी मिल रहा है, और हिंदी की स्वीकृति का भी। आज तकरीबन सत्तर प्रतिशत से अधिक वस्तुएं हिंदी के माध्यम से जनमानस तक पहुँच रही हैं। विक्रेता और क्रेता के बीच हिंदी सेतु का कार्य कर रही है, चाहे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पाद हों, चाहे देशी कंपनियों के।

मुख्य बिंदु : भाषा, वैश्वीकरण, भारत, कम्पनियां, उत्पाद.

प्रस्तावना :रात्रि के निविड़ अंधकार में अनंत आकाश में टिमटिमाते अनगिनत तारों को देखकर आदिम मानव के मस्तिष्क मे भी इन अनजान लोकों के प्रति उत्कंठा जाग्रत हुई होगी और वह उनके रहस्यों को जान लेना चाहता रहा होगा। दूर गगन में उड़ते पक्षियों को देखकर मनुष्य ने भी उड़ने की आकांक्षा पाली और अन्यान्य ग्रह लोकों की सैर करनी चाही। इसी भावना के वशीभूत कालांतर में वैमानिकी अस्तित्व में आई।

वैश्वीकरण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए वेट्टे क्लेर रोस्सर ने कहा था कि यह प्रक्रिया अचानक बीसवीं सदी में नहीं उत्पन्न हुई। दो हजार वर्ष पूर्व भारत ने उस समय विश्व के व्यापार क्षेत्र में अपना सिक्का जमाया था जब वह अपने जायकेदार मसालों, खुशबूदार इत्रों एवं रंग–बिरंगे कपडों के लिए जाना जाता था। भारत का व्यापार इतना व्यापक था कि एक बार रोम की सांसद ने एक विधेयक के माध्यम से अपने लोगों के लिए भारतीय कपडेका प्रयोग निषिद्ध करार दिया ताकि वहां के सोने के सिक्कों को भारत ले जाने से रोका जा सके। तभी से भारत की उक्ति 'वसुधैव कुटुम्बकम्' प्रचलित रही और इसीलिए आज भी भारत के लिए 'वैश्वीकरण' का मुद्दा कोई नया नहीं है।

भाषा के रूप में निश्चय ही इस नवउपनिवेशवादी व्यवस्था ने राष्ट्रों की प्रतिनिधि भाषाओं को चुना। बहुभाषिक समाज व्यवस्था वाले भारत में हिंदी चूँकि संपर्क और व्यवहार की प्रधान भाषा थी इसलिए हिंदी को वैश्विक बाजार ने अपनाया। यहाँ वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप हिंदी के विकासदृविस्तार पर जाने से पूर्व वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बारे में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, प्रसिद्ध समाज विज्ञानी प्रो. आनंद कुमार की राय का उल्लेख आवश्यक है। उनके अनुसार वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सात तत्व शामिल हैं, ये हैं– एक तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, दूसरा–माध्यम वर्ग, तीसरा–बाजार, चौथा–संचार माध्यम, पाँचवाँ–बहुउद्देशीय कंपनियां, छठा–आप्रवासन और सातवाँ–सम्पन्नता। ये सात चीजें मिलकर वैश्वीकरण को आधार देती हैं और इनमें से दो चीजें हैं जो कि देशी भाषाओं के अनुकूल हैं। एक है बाजार और दूसरा संचार माध्यम। निश्चय ही वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी के विकास–विस्तार को इन्हीं दोनों आयामों–बाजार और संचार माध्यम से देखना होगा। कहने की गरज नहीं, वैश्वीकरण की मूल अवधारणा अर्थकेन्द्रित है। अर्थोन्मुखी होने के

कारण ही वैश्वीकरण का समूचा प्रासाद, चाहे भाषा को लेकर हो या विचार को, संस्कृति को लेकर हो या तकनीक को, उपभोक्तावादी है।

हिंदी को लेकर यद्यपि इस तरह की आशंकाएँ व्यक्त की जाती रही हैं कि विश्व बाजार और भूमंडलीकरण के कारण हिंदी का मूल संसार शायद और सिमटेगा, परन्तु आँकड़ों और अब तक हुए बदलावों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि हिंदी बाजार से बेदखल होगी। निश्चित ही इस दौर में बाजार पूरी तरह हिंदी की गिरफ्त में है। और उल्लेखनीय पहलू यह है कि हिंदी का दबदबा बाजार में वर्चस्व के नाते नहीं बल्कि लोकोपयोगिता के कारण है। वैश्वीकरण में आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से हिंदी की भूमिका बढ़ी है। जैसेदृजैसे सीमाएं टूट रही हैं, प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं, दुनिया सिमट रही है, कारोबारी निकटता आ रही है, वैसेदृवैसे एक नई संस्कृति विकसित हो रही है। यह नई बाजार संस्कृति अब तक स्वायत्त रहे समाजों और संस्कृतियों के रहन–सहन, आचार–विचार, भाषा–वेशभूषा और मूल्यबोध सभी का अपने तरीके से अनुकूलन कर रही है। संचार माध्यम इस संस्कृति के वाहन बने हैं और हिंदी माध्यम के आंकड़े बताते हैं कि 100 करोड़ से अधिक की आबादी वाले इस राष्ट्र में 20 करोड़ से अधिक लोगों की मातृभाषा हिंदी है। 30 करोड़ से अधिक लोग इस भाषा का प्रयोग दूसरी भाषा के रूप में करते हैं, और लगभग 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका किसी न किसी रूप में हिंदी भाषा के साथ सरोकार जुड़ा हुआ है। कहने का आशय यह है कि देश की आबादी के लगभग तीन चौथाई से अधिक लोगों में हिंदी संपर्क का माध्यम है।

वैश्वीकरण और हिन्दी की भूमिका : बेशक, हिंदी की शक्ति के नाते ही अमेरीकी सरकार हो या 'कम्प्यूटर किंग' बिल गेट्स, हिंदी के उपयोग में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दुनिया को यह भलीभांति पता है कि लगभग 40 करोड़ की आबादी वाले भारतीय मध्यवर्गीय बाजार तक पहुँच बनानी है तो हिंदी को अपनाना होगा। यह वैश्वीकरण का ही दबाव है कि यू.एन.ओ. में हिंदी की चर्चा हो रही है, विश्व की प्रमुख भाषाओं में शुमार करने की ठोस दलीलें दी जा रही हैं। कहना न होगा, मारीशस में विश्व हिंदी सम्मेलन होना राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, परन्तु न्यूयॉर्क में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन निश्चय ही एक ऐतिहासिक परिवर्तन की आहट है, हिंदी की स्वीकृति का सकारात्मक पहलू है। विश्व समुदाय को पता लग चुका है कि भारत की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था का आधार क्या है और इस विकास की प्रक्रिया में शामिल होने का द्वार क्या है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है, गत दिनों मीडिया में हुए दो प्रयोग।

छोटे पर्दे और बड़े पर्दे दोनों पर हुए निम्न दो प्रयोगों से हिंदी की स्थिति का जायजा लगाया जा सकता है। रूपर्ट मडोंक जब छोटे पर्दे पर स्टार टी.वी. को लेकर आये तो जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि अंग्रेजी के माध्यम से कितना भी बढ़िया 'प्रोग्राम' और प्रसारण हो, मात्र शहरी वर्ग तक ही पहुँचा जा सकता है, वह भी 'इलीट क्लास' तक। जबकि हिंदी में कार्यक्रम प्रसारित किया जाये तो एक विशाल दर्शक वर्ग तक पहुँचा जा सकता है। परिणामस्वरूप स्टार टी.वी. ने हिंदी में कार्यक्रम बनाने–दिखाने शुरू किए और नतीजा समाने है।

इसी प्रकार एक दिलचस्प उदाहरण बड़े पर्दे का है। यूँ तो बड़े पर्दे पर अनेकानेक फिल्में 'डब' होती रहती हैं, परन्तु जब से 'हालीवुड' की फिल्मों को 'बालीवुड' की भाषा में लाने की कोशिश शुरू हुई, तब से एक नई चीज फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है। हमें याद है जब 'जुरासिक पार्क' को हिंदी में 'डब' किया गया तो देश के दूरदराज के गाँवदृकस्बों तक उसे खूब पसन्द किया गया। उल्लेखनीय यह है कि इसके पहले किसी भी विदेशी फिल्म ने इतना मुनाफा नहीं कमाया था। ये तथ्य इस बात के संकेत है कि हिंदी में कितनी जबरदस्त क्षमता है।

इतना ही नहीं, यह हिंदी का ही कमाल है कि राष्ट्रीय ही नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों को भी आज हम गाँवों में पा सकते हैं। बेशक संचार क्रान्ति और विज्ञापन संस्कृति का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वैश्वीकरण के कारण जो बाजार आज बन रहा है उसके विकासदृविस्तार में संचार क्रान्ति और विज्ञापन उद्योग की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पिछले दो दशकों में साबुन और टूथपेस्ट जैसी दैनंदिन उपयोग की वस्तुओं से आगे चलकर अब मोटरसाईकिल, कार, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े आदि के विज्ञापन हिंदी प्रसारित किये जा रहे हैं। छोटेदृछोटे कस्बों तक सौन्दर्य प्रसाधन के 'ब्यूटी पार्लर' खुल चुके हैं। सैलून जैसे अब गुजरे जमाने का शब्द लगने लगा

है। बड़ेदृबड़े होर्डिंग्स पर लिखे लोकदृलुभावन विज्ञापन आज शहरों की चौहद्दियों से बाहर छोटेदृछोटे कस्बों और गाँवों तक देखे जा सकते हैं। टी.वी. और मोबाइल से शायद ही अब देश का कोई कोना अछूता हो। उल्लेखनीय है कि इन संचार माध्यमों की भाषा हिंदी है, क्षेत्रीय भाषाएँ हैं।

भाषा को दो भागों में बाँटा जा सकता है। एक तो वह भाषा जो स्थान–स्थान पर कुछ देशज शब्दों और लहजे के साथ कही जाती हैं और दूसरी साहित्य की भाषा जो सारे देश में मानक की तरह लिखी व पढीजाती है। वैसे तो, अब साहित्य में भी बोलियों का प्रयोग स्वागतीय बन गया है ताकि कथन में मौलिकता बनी रहे और देशज शब्दावली जीवित रहे।

वैश्वीकरण के बाद भाषाओं को भी दो भागों में बाँटा जा सकता है। विश्वस्तर पर छः भाषाओं को सरकारी काम–काज के लिए अंतरराष्ट्रीय भाषाओ का दर्जा दिया गया है। ये भाषाएं हैं – अंग्रेजी, फ्रेच, स्पेनिश, चीनी, रूसी और अरबी। और दूसरी –वो भाषाएं जो व्यापार में संपर्क भाषाओं ख्लोबल लेंग्वेजस, के रूप में प्रयोग में आतीं है।

आठवें विश्व हिन्दी सम्मेलन में जोर से माँग उठाई गई कि हिन्दी को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सातवीं अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी जाय। वैसे, यह एक राजनीतिक मुद्दा है, जिसके लिए न केवल राजनीतिक इच्छा– शक्ति की आवश्यकता है बल्कि अपार धन व्यय की व्यवस्था भी करनी पडेगी। शायद इसीलिए हमारी सरकार का ध्यान इस ओर अभी नहीं गया है। परन्तु हिन्दी की उपयोगिता को विश्व का व्यापारिक समुदाय समझ चुका है और इसे अन्तरराष्ट्रीय वैश्विक भाषा ख्लोबल लेंग्वेज, का दर्जा मिला है।

हिन्दी को वैश्विक दर्जा दिलाने में कई कारक हैं जो व्यवसाय और व्यापार को बढावा देने में सहायक होंगे। भारत एक बडाबाजार है जहाँ के सभी लोग हिन्दी में सम्प्रेषण कर सकते है। इसीलिए हिन्दी का महत्व व्यापारी के लिए बढ़ जाता है। निश्चय ही मीडिया और फिल्मों में हिन्दी के प्रचार–प्रसार मे एक मुख्य भूमिका निभाई है। हिंदी का विरोध कर रहे कुछ क्षेत्रों में भी हिन्दी फिल्मों की मांग बढ़ रही है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी टेलिविजन पर सबसे अधिक हिन्दी चैनल ही प्रचलित एवं प्रसिद्ध हैं और यह इस भाषा की लोकप्रियता व व्यापकता का प्रमाण है।

पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हिन्दी का स्थान प्रथम है। भूमंडलीकरण, निजीकरण व बाजारवाद ने नब्बे के दशक में हिन्दी पत्रकारिता में क्रांति लाई। रंगीन एवं सुदर साज–सज्जा ने श्वेत–श्याम पत्रकारिता को अलविदा कहा। अब दैनिक पत्र भी नयनाभिराम चित्रों के साथ प्रकाशित होते हैं। इसके साथ ही यह भी हर्ष का विषय है कि इन पत्रों के संस्करण कई स्थानों से एक साथ निकल रहे हैं। यह जानकर सुखद आश्चर्य भी होता है कि भारत में सब से अधिक बिकनेवाले समाचार पत्र हिन्दी के ही हैं जबकि अंग्रेजी के सबसे अधिक बिकनेवाले पत्र का स्थान दसवें नम्बर पर आता है। 'दैनिक भास्कर' समाचार पत्र की रोज 1 करोड 60 लाख प्रतियां छपती हैं जबकि सर्वाधिक बिकनेवाले अंग्रेजी पत्र 'टाइम्स आफ इण्डिया' की 65 लाख प्रतियां छपती हैं और वह दसवें स्थान पर है। इसी से हिन्दी के प्रभाव, प्रचार,प्रसार और फैलाव का पता आंका जा सकता है।

वैश्वीकरण की एक और देन होगी अनुवाद के कार्य का विस्तार। जैसे– जैसे विश्व सिकुड़ता जाएगा, वैसे–वैसे देश–विदेश के विचार, तक्नीक, साहित्य आदि का आदान–प्रदान अनुवाद के माध्यम से ही सम्भव होगा। आज अनुवाद की उपयोगिता का सबसे अधिक लाभ फिल्मों को मिल रहा है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि हिन्दी अनुवाद के माध्यम से अंग्रेजी फिल्म 'द ममी रिटर्न्स' को सन 2001 में 23 करोड़ रुपयों का लाभ हुआ जबकी 2002 में 'स्पैडरमैन' को 27 करोड़ का और 2004 में 'स्पैडरमैन–2' को 34 करोड का लाभ मिला। ये आंकडे एक उदाहरण है जिनसे अनुवाद की उपयोगिता प्रमाणित होती है।

कम्प्यूटर युग के प्रारंभ में यह बात अक्सर कही जाती थी कि हिन्दी पिछड़ रही है क्योंकि कम्प्यूटर पर केवल अंग्रेजी में ही कार्य किया जा सकता है। अब स्थिति बदल गई है। अंतरजाल के माधयम से अब हिन्दी के कई वेबसाइट, चिट्ठाकार और अनेकानेक सामग्री उपलब्ध है। यूनिकोड के माध्यम से कंप्युटर पर अब किसी भी भाषा में कार्य करना

सरल हो गया है। गूगल के मुख्य अधिकारी एरिक श्मिद का मानना है कि भविष्य में स्पेनिश नहीं बल्कि अंग्रेजी और चीनी के साथ हिंदी ही अंतरजाल की प्रमुख भाषा होगी।

कंप्युटर युग में विश्व और सिकुड़ गया है। अब घर बैठे देश–विदेश के किसी भी कोने से संपर्क किया जा सकता है, वाणिज्य सम्बंध स्थापित किये जा सकते है। ऐसे में सर्वाधिक बोली जानेवाली भाषा को प्राथमिकता मिलेगी ही क्योंकि बाजार में जाना है तो वहीं की भाषा के माध्यम से ही अपनी पैठ बना सकते हैं। ईस्ट इन्डिया कम्पनी के अंग्रेज भी आये तो हिन्दी सीख कर ही आये थे।

भारत की जनसंख्या को देखते हुए और यहाँ के बाजार को देखते हुए, विश्व के सभी व्यापारी समझ गए हैं कि हिन्दी के माध्यम से ही इस बाजार में स्थान बनाया जा सकता है। इसीलिए यह देखा जाता है कि अधिकतर विज्ञापन हिन्दी में होते हैं, भले ही देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग किया गया हो। रोमन लिपि का यह प्रयोग भी धीरे–धीरे नागरी को इसलिए स्थान दे रहा है कि विश्व का व्यापारी समझ चुका है कि व्यापार बढाना है तो उन्हीं की भाषा और लिपि के प्रयोग से ही अधिक जनसंख्या तक पहुँचा जा सकता है। वैज्ञानिक तौर पर भी नागरी अधिक सक्षम है और अब कंप्यूटर पर भी सरलता से प्रयोग में आ रही है।

वैश्वीकरण का जो प्रभाव भाषा पर पड़ता है, वह एकतरफा नहीं होता। विश्व की सभी भाषाओं पर एक–दूसरे का प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव पिछले दो हजार वर्षों के भाषा–परिवर्तन में देखा जा सकता है। विगत में यह प्रभाव उतना उग्र नहीं दिखाई देता था और यह मान लिया जाता था कि कोई भी शब्द उसकी ही भाषा का मूल शब्द है। ऐसे कई हिन्दी शब्द अंग्रेजी में भी पाए जाते हैंय जैसे, चप्पु–शेम्पु, दांत–डेंटल, पैदल–पेडल, सर्प–सर्पेंट आदि। लेकिन आज हमें पता चल जाता है कि किस शब्द को किस भाषा से लिया गया है।

निष्कष : जो लोग पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण से आतंकित हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि वैश्वीकरण के इस युग में भारतीय संस्कृति विश्व पर हावी हो रही है। आज के मानसिक तनाव को देखते हुए विश्व की बडीकंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए योग एवं ध्यान के प्रशिक्षण के उपाय कर रहीं हैं। हमारे गुरू आज देश–विदेश में फैले हुए हैं और भारतीय संस्कृति का प्रचार–प्रसार कर रहे हैं जिनसे विदेशी समुदाय लाभान्वित हो रहे है। विदेशी कंपनियां व्यवसायिक लाभ के लिए हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करके अपने उत्पादन को बढावा दे रहे हैं। भारत की सदियों पुरानी उक्ति 'वसुधैव कुटुम्बकम' एक बार पुनः चरितार्थ हो रही है और वैश्वीकरण व बाजारवाद के इस युग में हिन्दी अपना सम्मानित स्थान पाने की ओर अग्रसर है।

सन्दर्भ :

•स्टाइपो, फ्रांसेस्को. विश्व संघवादी घोषणा पत्र राजनीतिक वैश्वीकरण के लिए मार्गदर्शिका ISBN 978-0-9794679-2-9.

•हर्स्ट ई.चार्ल्स सामाजिक असमानताः प्रकार, कारण और परिणाम, छठा संस्करण.P-41.

•"पैंबाजूका समाचार"-Pambazuka.org2007-01-26अभिगमन तिथिरू 2012-12-23.

•नाओम शोमस्की जीनेट मई 07-2002क्रोएशियन फेरल ट्रिब्यून अप्रैल27-2002

•स्टिगलिट्ज, यूसुफ और चार्लटन निष्पक्ष व्यापार सभी के लिएरू व्यापार कैसे विकास को बढ़ावा दे सकता है. 2005 पी. 54 एन-23.

मिथिलेश्वर के साहित्य में तत्कालीन समय और समाज

डॉ. ललित कुमार सिंह, सुधा चौरसिया

समय परिवर्तनशील है, समय में परिवर्तन के साथ–साथ समाज भी परिवर्तित होता है आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि साहित्य समाज का दर्पण है। समाज में परिवर्तन या तो सामाजिक दबाव से होते हैं या साहित्यिक दबाव से अनेक प्रकार की समस्याओं से आज हमारा समाज ग्रस्त है जैसे–सामाजिक समस्या, राजनैतिक समस्या, आर्थिक समस्या, नैतिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या। जाहिर है कि जो लेखक, कवि या साहित्यकार जब लेखनकार्य करता है तो वह अपने वातावरण, परिवेश, आस–पास की घटित घटनाओं से कहीं न कहीं वह प्रभावित होता है और यह प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से उसके लेखन में दिखाई देता है और यदि पाठक गहराई से उसके साहित्य का अध्ययन करें तो वह उस पृष्ठभूमि से अवगत होता है। क्योंकि लेखनकार्य उसके मस्तिष्क की उपज से अधिक अपने परिवेश से प्रेरित होता है।

मिथिलेश्वर बिहार के एक छोटे से गाँव से है जहाँ अशिक्षा बेरोजगारी, अंधविश्वास, तंत्र–मंत्र, भूतप्रेत का प्रचार, विधवाओं एवं बूढ़ी औरतों का शोषण, औरतों को बच्चा न होने पर डायन घोषित कर प्रताड़ित करना, नारी उत्पीड़न, राजनीतिक दलवन्दी, जातिगत भेदभाव इत्यादि समस्याओं से ग्रस्त था। अतः मिथिलेश्वर बचपन से इस परिवेश को देखते सुनते आ रहे थे और कहीं न कहीं वे इन समस्याओं से अपने गाँव, समाज परिवेश को बचाना चाहते थे। अतः उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज को उन समस्याओं से अवगत कराना एवं उन समस्याओं पर चिंतन करने के लिये विवश किया है।

मिथिलेश्वर समाज में हो रहे मूल्यों के ह्रास को रोकना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसी सीढ़ी है, जिसके माध्यम से समाज को अच्छे पथ की ओर अग्रसारित किया जा सकता है, जब लोगों में जागरुकता आ जायेगी, लोग अधिक मात्रा में शिक्षित हो जायेंगे, लोगों की समझदारी विकसित हो जायेगी, तब इन रूढ़ियों पर से लोगों का विश्वास अपने आप हट जायेगा। जिस तरह वर्ग–भावना से लोग ग्रसित हैं, उसी तरह रूढ़ियों से भी चिपके हैं। शिक्षा के व्यापक प्रसार के बाद ये भावनाएँ स्वतः खत्म हो जाएगी।

आज लोग पाश्चात्य संस्कृति की नकल करके अपने को मॉडल कहते हैं परन्तु मिथिलेश्वर का मानना है मॉडल बनना है तो सबसे पहले अपने मस्तिष्क को और अपने आपको बदलना होगा। अपने पारिवारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक मूल्यों को अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करते हुये ही हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं और तभी एक अच्छे परिवार समाज, गाँव, देश और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।

आज भूमंडलीकरण का दौर चल रहा है और लोगों के व्यवहार में भी परिवर्तन हो रहा है, जिससे हमारे संयुक्त परिवार टूट रहा है, समाज का विघटन हो रहा है। 21वीं सदी का दौर है, स्त्री सशक्तीकरण, दलित चेतना, विभिन्न आन्दोलनों की बात हो रही है। आज स्त्रियों की स्थिति में पहले की अपेक्षा परिवर्तन आया है किंतु संतोषजनक नहीं।

आज ज्यादातर परिवारों में माता–पिता का तिरस्कार हो रहा है जो एक नई समस्या के रूप में उभरा है वह है, वृद्धावस्था, माता–पिता का एकांगीपन।

किसी शायर ने माँ के महत्व को बताते हुये लिखा है कि–''जो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है दुनिया की मोहब्बत फिजूल, माँ की हर दुआ कबूल है ऐ! इंसान माँ को नाराज करना तेरी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है।''[प] दूध की पहली बूँद से लेकर चूल्हे के सिरहाने से रोटियाँ उतारकर देने तक एक माँ के हाथ से न्यौछावर करने का जो सिलसिला शुरू होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। ममता भरा ये एक ऐसा बेमिसाल कर्ज है इसके लिये शुक्रिया भी कहे तो भी इस ममता का तिरस्कार हो जायेगा। जिंदगी में किसी भी मोड़पर खड़े होकर हम पीछे देखें तो सिर्फ यही नजर आता है कि करुणा की इस देवी ने हमेशा देने के लिये

हाथ बढ़ाया है लेने के लिये नहीं। वो माँ रातभर जागकर हमें सुलाती है, कितने अरमान लिये कि एक दिन मेरा लाल मेरे जिन्दगी का खेवनहार बनेगा। लेकिन आज समय परिवर्तनशीन है न जाने कौन सी हवा हमारे भारत देश को लग गयी है कि लोग अपने नैतिककर्त्तव्य एवं मूल्यों की तिलांजलि दे रहे हैं, जिससे वे अपने परिवार, गाँव एवं समाज का विघटन कर रहे हैं।

मिथिलेश्वर इस परिस्थिति को देखकर विक्षुब्ध होते हैं और अपने अन्तरमन की भावनाओं को अपने कहानी 'चल खुसरो घर आपने' के माध्यम से दिखाने का सफल प्रयास किया है कि आज हमारे घर और परिवार किस तरह विघटित हो रहे हैं किस प्रकार आज की युवा पीढ़ी अपने कर्त्तव्य बोध को विस्मृत कर रहे हैं। ठीक ही कहा गया है कि माता–पिता अपने बच्चों का पालन–पोषण कर लेते हैं किन्तु जब इन्हीं बच्चें को बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए तो वे किस प्रकार आपस में षडयंत्र रचते हैं और उन्हें अपने माता–पिता बोझ लगने लगते हैं। 'चलखुसरो धर आपने' कहानी में अपने पति द्वारा घर का विस्तार करवाने पर श्यामरंजन और रविरंजन की माँ कहती–''अब घर को और बढ़ाना ठीक नहीं, रहने भर का हो गया, काफी है, कोई जरूरी नहीं कि लड़के यही रहेंगे, जहाँ नौकरी लगेगी वहाँ उन्हें जाना ही होगा। फिर बुढ़ापे में हमें भी बच्चों के साथ रहना है।''[पप] किन्तु वहीं दोनों बेटे अपने पिता की उपेक्षा के साथ–साथ उनके न रहने पर माँ की भी उपेक्षा और तिरस्कार किये और अपनी पत्नियों के गर्भवती होने पर अपनी–अपनी जरूरत के हिसाब से आया' की तरह घर के कार्य के लिये माँ को ले गये और कार्यसिद्ध हो जाने पर वही माँ उन्हें बोझ लगने लगी और उसे गाँव की दायी मुनरी के साथ गाँव भेज दिया और बस में बैठने पर वे अपने पति के बातों को याद करती हैं कि–''बच्चे चाहे जहाँ नौकरी करें, जिन शहरों में घर बसायें, हमारा एक अपना घर तो होना ही चाहिए, जो हमारा बिल्कुल अपना हो, जिसमें अपनी इच्छा के अनुसार जीने का हमारा पूरा अधिकार हो।''[पपप]

इसी प्रकार 'जी का जंजाल' कहानी में कामता, रमता, भिभता और समता चार पुत्रों की माँ होने के बावजूद, उस माँ की अपने ही घर में तिरस्कार होता है उनके दिवंगत पति उनके बुढ़ापे के लिये कुछ रुपये उनके नाम पर बैंक में फिक्स किये थे जिस पर उनके चारों पुत्रों की नजर है, वे समय–समय पर उनसे पैसों की माँग करते हैं और रुपये न देने पर उन्हें रोजाना उनकी पत्नियाँ और वे चारों ताने मारते हैं। बच्चों के लिये अपनी सारी सुख–सुविधाओं को उन्होंने तिलांजलि दे दी थी। इसीलिये बच्चों की उपेक्षा उन्हें बहुत कचोटती है।

बचपन में बगैर उनके स्पर्श के उन्हें नींद नहीं आती। लेकिन अब तो माँ के पास कभी भूलकर भी बैठने और दुःख तकलीफ पूछने की उन्हें फुरसत नहीं मिलती। माँ को सर्दी, बुखार है वह चावल नहीं रोटी खाने को कहती हैं इस पर वे कहते हैं–''आपने हमको तबाह कर रखा है। इतने कम वेतन में मैं कैसे घर चलाता हूँ, यह तो आपने कभी नहीं सोचा। आपको तो तरह–तरह का खाना चाहिए।''[पअ] और पैसा माँगने पर न देने का समता कहता है–''इसीलिये आप भोग रहीं हैं और अभी और भोगिएगा। किस लड़के की कैसी आमद है, इस पर आपने कभी विचार नहीं किया।''[अ]

इसी प्रकार 'नरेश बहू' कहानी में मिथिलेश्वर ने स्त्री की दासता, शोषण और दीनता का बड़ा ही यथार्थ वर्णन किया है कि किस प्रकार आज भी हम पुरुष प्रधान समाज एवं मानसिकता से ग्रसित है, क्या आज भी एक औरत की साँस उसके पति की जागीर है। शादी के बाद उसका पति अपने आपको अपनी पत्नी का भगवान मानने लगता है। 'नरेश बहू' की स्थिति भी यही है कि वह अपने नाम से नहीं संबोधित की जाती बल्कि अपने पति के नाम से और शादी में दहेज न मिलने की वजह से नरेश बहू के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया जाता है। उसका पति उसे जानवरों की तरह पीटता है, जिससे वह क्षुब्ध होकर गाँव छोड़कर दूसरे गाँव भाग आती हैं, वहाँ 'वीरू' नामक युवक को देखकर घबराहट के स्वर में रोते हुये कहती है–''भैया मुझे बचा लो, वे पकड़ लेंगे तो जिंदा जला डालेंगे। उनके साथ अब एक मिनट भी नहीं रहूँगी अगर मैं जानती तो शादी से पहले जहर खा लेती।''[अप]

इस पर उसका पति उसके बाल पकड़कर चेहरे पर तमाचा लगाया बाल खींचते हुये ले चल पड़ा ''हरामजादी, भागकर कहाँ जाएगी इज्जत बिगाड़ने पर तुली है। चल तुझे इस बार काटकर आंगन में गाड़ नहीं दिया तो मेरा नाम नरेश नहीं।''[अपप]

'तिरियाजनम' कहानी में भी सुनैयना बचपन से ही पढ़ने में होशियार थी किन्तु उसके साथ भी लड़की होने की वजह से बचपन से ही उसके और उसके भाइयों में भेदभाव किया जाता था, उसे पुराने कपड़े और जूठन, भाइयों को नये कपड़े, जूते, चप्पल, दूध, घी, मक्खन। उसे कक्षा पाँच से ज्यादा पढ़ने भी नहीं दिया गया यदि वह ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो पढ़ा–लिखा लड़का खोजना होगा और तिलक, दहेज देना होगा और उसकी शादी एक देहाती, कम पढ़े–लिखे, उजड्ड लड़के से कर दी जाती है, जो लगातार सुनैयना का मारता–पीटता है, कहता है कि–''औरतें लतियाने वाली जाति होती है, बतियाने वाली नहीं।''[अपपप] उसकी सास भी कहती है–''पति की मार पर इरखा नहीं करनी चाहिए। पति की मार तो सुहाग भाग है, गाँव में कौन मर्द अपनी पत्नी को नहीं पीटता? लेकिन सभी तुम्हारी तरह खाना–पीना और काम धाम छोड़कर नहीं बैठ जाती जो मारता है, वहीं दुलारता भी है।''[पग]

'सीमाएँ' कहानी में भी ददुआबो की नारी संवेदना को उन्होंने अभिव्यक्त किया है कि किस प्रकार हमारे समाज में स्त्री को कमजोर समझकर पुरुष उसका शोषण करते हैं उसके पति को उसके जेठ–जेठानी मार डालते हैं और उसे सम्पत्ति से बेदखल करने के लिये उस पर आरोप लगाकर घर से निकाल देते हैं, वह अपने मलिक चन्द्रमोहन बाबू के यहाँ जहाँ ददुआ और वह काम करते हैं दौड़ते हुये उनके पैरो पर गिर पड़ी और कहती है–''मुझे बचा लीजिये मलिकार! सब मिलकर मारे रहे हैं और गाँव से निकाल रहे हैं। मेरे ऊपर झूठा अक्षरंग लगा रहे हैं–मैं इन मुदइयों से कुछ माँगती तो हूँ नहीं, फिर मेरे ऊपर पानी पीटकर क्यों पड़े हैं।''[ग] चन्द्रमोहन बाबू जो उससे बड़ा प्रेम करते थे किंतु भरे समाज में उसकी मदद करने से हाथ खड़ा कर दिये कि कहीं ददुआ बो की मदद करने से मेरी इज्जत पर कीचड़ न उछल जाये।

'युद्धस्थल' उपन्यास में मिथिलेश्वर के टिपिकल गाँव की कहानी है, गाँव में प्रायः उपेक्षित एवं विधवा औरतों को डायन कहकर प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें जिन्दा भी जला भी दिया जाता है, रामशरण बहू जिनको कोई संतान नहीं है और पति भी मर गया है, इसलिये गाँव वाले उसे डायन कहते हैं और दूधनाथ चौधरी नामक एक व्यक्ति के पुत्र की चेचक से मृत्यु हो जाती है, जिसका दोष वह रामशरण बहू को मानता है और अंधविश्वास से ग्रस्त उसकी हत्या भी कर देता है। गाँव की औरतें भी रामशरण बहू को उपेक्षा एवं तिरस्कार की नजर से देखती है, उसे देखते ही अपने घर के दरवाजे बंदकर बच्चों की छिपाने लगती है–''भागो–भागो, नहीं तो राक्षसी निगल जाएगी।''[गप] इस पर रामशरण बहू की दाई दुखन की माँ कहती–

''तुम सब मानवी हो और हम सब दानवी हैं।''[गपप]

इस पर वे कहती–''दुखन की माँ भी डायन हो चली है।''[गपपप]

मिथिलेश्वर का मानना है कि समाज के समुचित एवं सर्वांगीण विकास के लिये नारी को उचित सम्मान मिलना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि नारी पतिता बनने के लिये बाध्य नहीं हो और समाज में स्वाभिमान के साथ जीवन जी सके, परिणामस्वरूप वह अपने उपन्यासों और कहानियों में नारी के प्रति सहानुभूति तथा गौरव का भाव व्यक्त करते दिखाई देते हैं। मिथिलेश्वर पर प्रगतिवादी चेतना का प्रभाव दिखाई देता है। परिणाम स्वरूप उनके कथा साहित्य में विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, अंधविश्वास, बहुविवाह आदि की चर्चा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों विसंगतियों की कटु आलोचना की है। वह सर्वत्र इन कुप्रथाओं, रूढ़ियों बहुविवाह आदि अंधविश्वासों के प्रति घृणा व्यक्त करते है, वे समाज को इन विकृतियों से मुक्त करने को लालायित है, जिससे एक स्वस्थ एवं सुंदर समाज निर्मित हो जिससे स्त्री एवं पुरुष दोनों प्रसन्नता से रहकर जीवन का विकास करें और नवजीवन को प्राप्त करें।

संदर्भ :

1. दैनिक जागरण, पृ.4, मातृ दिवस, संस्करण
2. मिथिलेश्वर, चल खुसरो घर अपने, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, सं.2009, पृ.175
3. वही, पृ.176
4. मिथिलेश्वर, जी का जंजाल, सस्ता साहित्य मण्डल, प्रकाशन, संस्करण, 2009, पृ.238
5. वही, पृ.239
6. मिथिलेश्वर, नरेश बहू, लोक भारती प्रकाशन, संस्करण 2014, पृ.96

7. वही, पृ.96
8. मिथिलेश्वर, तिरिया जनम, राजकमल प्रकाशन, संस्करण 2012, पृ.214
9. वही, पृ.214
10. मिथिलेश्वर, सीमाएँ, संस्ता साहित्य मण्डल, प्रकाशन संस्करण, 2009, पृ.81
11. मिथिलेश्वर, युद्धस्थल, राजकमल प्रकाशन संस्करण 1994, पृ.142
12. वही, पृ.142
13. वही, पृ.143

मानवाधिकार और किन्नर – एक नई पहल

विधि शम्भरकर, जबलपुर

सृष्टि के निर्माण से अब तक मनुष्य कई रूपों में संघर्ष करता आया है। मावनाधिकारों के संदर्भ में देखें तो समाज के कई वर्ग और समुदाय अपने मानवाधिकारों के लिए आज भी संघर्षरत् हैं। 'किन्नर' समुदाय उन्हीं में से एक है। वैसे तो प्राचीन काल से ही समाज में इनका अस्तित्व होते हुये भीनहीं है। लेकिन इस संदर्भ में एक नई क्रांति और बहस कोजन्म मिला जब 2014 को किन्नरों के अधिकारों पर विधेयक प्रस्तुत किया गया और उच्चतम न्यायालय ने इन्हें तृतीय लिंग का दर्जा दिया।

निश्चय ही यह एक बड़ा परिवर्तन है। बहुत बड़ा परिवर्तन इसलिए क्योंकि जहाँ मानवाधिकारों की चर्चा, हम अधिकारों के लिए संघर्ष से प्रारंभ करते हैं, वहाँ किन्नरों के लिए ये मामला थोड़ा अलग है। अलग इसलिए कि किन्नरों का संघर्ष समाज की मुख्यधारा में शामिल होने से शुरू होता है अस्तित्व के लिए संघर्ष से शुरू होता है। इस विधेयक के माध्यम से किन्नरों को एक नई पहचान और विकास के अवसर देने की पहल की गई है। उक्त अधिनियम में कुल 58 धाराएँ है, जो किन्नरों को अधिकार और विकास के अवसर प्रदान करने का पुरजोर प्रयास करती है। अधिनियम की धारा 2(t) 'ट्रांसजेन्डर पर्सन' को परिभाषित करती है। यह विधेयक किन्नरों के अस्तित्व एवं सामाजिक स्वीकृति का द्योतक है। किन्नर हमारे समाज का हमारी कानून व्यवस्था का अभिन्न अंग है। भारत में किन्नरों की अनुमानित संख्या 30 लाख के आसपास है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके कल्याणार्थ उचित प्रावधान हो। शुभ अवसरों पर बधाई के मंगल गान गाने वाले मंगलमुखी किन्नरों को उच्चतम न्यायालय ने पहचान के साथकानूनी दर्जा देने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि किन्नरों की दशा पर विचार कर रही सरकार की कमेटी तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दे। सरकार उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए छह महीने के भीतर लागू करें। न्यायालय द्वारा नि. लि. दिया निर्देश दिये गये–

(1) किन्नरों को तीसरे लिंग के तौर पर शामिल कर संविधान और कानून में मिले सभी अधिकार और संरक्षण दिये जायें।

(2) किन्नरों को अपने लिंग की पहचान तय करने का हक है। केन्द्र व सभी राज्य सरकारें उन्हें कानूनी पहचान दें।

(3) किन्नरों को सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा मानते हुये शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आरक्षण दिया जाये।

(4) सरकार किन्नरों की चिकित्सा समस्याओं के लिए अलग से एचआईवी सीरो सर्विलांस केन्द्र स्थापित करें।

(5) सरकार किन्नरों की सामाजिक समस्याओं जैसे भय, अपमान, शर्म व सामाजिक कलंक आदि के निवारण के गंभीर प्रयास करें।

(6) किन्नरों को अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराऐं और अलग से पब्लिक टॉयलेट व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराएँ।

(7) सरकारें किन्नरों की बेहतरी के लिए सामाजिक कल्याण योजनाएँ बनाएँ।

(8) सरकार किन्नरों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के प्रयास करें ताकि किन्नर अपने को अछूत या अलग–थलग महसूस न करें।

किन्नरों के अधिकारों पर विधेयक 2014 आदि किन्नरों की सुदृढ़ विधिक स्थिति की ओर संकेत करती है। परन्तु विधि समाज को सुचारू रूप से चलाने की यांत्रिकी होती है। विधि की सफलता उसकी गरिमा समाज में प्रभावकारी बन जाने में होती है। आवश्यकता है एक सुदृढ़ सामाजिक सहयोग की जो किन्नरों के कल्याण के लिए किये गये सराहनीय विधिक प्रयास को पूर्णता दे।

Good Governance : A Genesis

Khyati Mishra

Good government is not created. Soloely by government. Every stakeholder has an equal role in achieving it. There is a need for greater accountability of any action/ decision taken within the public domain. Today there is a need to make governance participatory. Any programme bring implemented must be outcome orieted and achieved throgh larger stakeholder consevsus building. In any discussion on good governance, attention must be focused on the primary responsibilities of the government. These must include the maintenance of law and order, administration of justice and welfare of evonomically and socially weaher sectione of society in terms of provision of safety net for them India would not have presented a picture of such squalor filth, illiterary and poverty ever six decades after independence. The main question is wehther are prepared to learn lesson for the future from our experience of the post or not.

The proposed research work is an attempt to analyse the concept of governance and indeed good governance, understanding the realities of government,administration and their approaches towards beneficiaries especially downtrodden and her role towards illiterary and poverty elimination. What do people mean by good governance and what is their understanding about government and what does government mean by establishing their hypothesis and facts.

The term 'Governance' and 'Good Governance' are now increasingly being used indevelopment discourse. The urge for achieving 'common good' through the process of governance has led to focus the searchlight on the phenomenon of good governance. Since the very lavon of 'state' irrespective of its nature and from, the desire for goodness in administration has persisted. Good governance, now established as a romantic ideal, is rooted int he search for ways of removing and administrative ills and mat-governance. However, as an indicator of an effective and efficient administration good governance occupies a prominent place in the administrative set up of both developed and developing societies. The urge fo rth establishment of a transparent goverment has seen as new era of good governance. In 21st century the demand for participatory democracy is necessarily adhered to. The real sovereign aurthority, the people are still far behind from being the actual processor of authority. Mal-Governance and Mal-Administration can never bring democracy toa success. In India corution and unaccountable administration has remained an abstacle in the governance.

The necessary of bringing good governance is firmly established in every democratic society. In India, the efforts to establish good and clean governnace began with the establishment of democracy since indepencence. The pranble of the Indian constitution itself talk about the values and principles of good governance. Like soverignty residing with the people; liberty; equality; fratenity; social and economic justice; freedom of speech; expression; elief; faith and worship; secularisim; socialism etc. These are followed and upholed as the main goals of governance and the nation. These principles of democracy are further elaborated and maintained throughout the provisions of the constitutions specially under the chapter of Fundamental rights, Directive Principles of State policy, Foundamental Duties etc. Various legislation and policies are enacted by government of India and government of states to strenghten the base of democracy. A specific mention is needed here about right to information (RTI).

Keeping in mind these focal points of the isue of good governance, it is found prudential the revitialize public opinion about this matter. Looking to the growing phenomenon of good governancer, it is also necessary to know the level of awareness among the people about good governance, it is also necessary to know the level of awareness among the people about good governance. In this regard it is essential to examin good governance and its development in Madhya Pradesh.

OBJECTIVE OF STUDY

The presuit study would objectively examined the actual condition of good governance in Madhya Pradesh. In brief, the present study attempted to cover the phenomenon of good governance and its relation with transparancy and also to know the opinion of the common people about the changing role of government. The present study covers the following objectives :-

1. To analyze the policies of government and to asses their impact on the targeted groups.
2. To analyze key issue in good governance, identify problems and to suggest solutions for them.
3. Develop action plans and support implementation of these plans.
4. To provide consultancy services for improving previaling administrative system and their required restructuring.
5. To identify those areas for change and reform that will make the most positive impact in improving adminsitrative performance and achievements.
6. To provide institutional mechanism to local institutional mechanism to local institutions and stakeholders for peoples centric administration.
7. To provide technical support and advisory services to the local bodies, states, institutions in the areas of programme structuring and implementation action research, change management and administrative action.

RESEARCH METHODOLOGY

The present study is a Macro level critical analytical study seeking to detail and examine the Good Government in Madhya Pradesh. Both the primary and secondary sources would be utilized. Out of various approaches of study i.e. Inductive and Deductive Method. Theoritical, analytical, marxist and historical descriptive, the analytical approach could be used with the histirocal evidence to support the argument. So the present approach would be historical analytical. The behavioural methodology with the help of structured and open ended questionnaire would be used to have purposive sampling of leaders of various parties, legal luminaries, administrators and common people. The study would be based on secondary data. The required data would be collected from various i.e. library, R.D.V.V., Delhi University, News papers, publication of various Ministries, annual report of ministries, books and reserach journals. Modern Technology Internet and Email, Social Media also used in the research to make the study updated.

REVIEW OF LITERATURE

The area of research has not received much attention as far as structural good govermence in Madhya Pradesh.

(1) Public Administration Theories and Concepts : By Prof. B.L. Fadia, Dr. Kuldeep Fadia, Sahitya Bhawan Publication

Public Administration is an ancient activity common to just about all countries and all levels of government. But with the passage of time phenonenal changes are also perceptible in public administration's structure and activities which vary from one nation to another. It is a process of management which is practiced by all kinds of organization from the household to the most complex system of the government. In fact, public adminsitration is governmental administration.

This chapter titled citiaen and administration deals with the concept of good governance in chapter 86 on page no. 849. Good governance being an adjective expression, connotes certain value assumptions, whereas governance as a process denotes a value-free dispencation. Good Governance is associated with efficient and effective administration in a democratice framework. It is equivalent to purposive and development oriented administration which is comitted to improvement in quality of life of the people. It refers to adoption of new values of governance to establish greater effieicncy, legitimacy and credibility of the system. In the context of misgovernance which is found all around especially in developing countries, in rampaut degree. The concept of good governance becomes attractive as a remedy against state affairs.

(2) New Horizons of Public Administration : By Mohit Bhattacharya

This book deals with Good Governance in chapter 20 on Page No. 405 onwards. On reviewing the book the following ideas emerge.

Good Governance in any state is a recent entrant. There are three ways of understanding new developments.

Firstly, it is an attempt to widen the scope of public administration by going beyond formal government. Secondary, it is externally dictated term invented to prescribe aid conditionality.

Thirdly, it is a genuinely democracy intensiffing concept tomake public administration more open, transparent and accountable. It is the search for "new possibiliteis" that brings out the true meaning of good governance. The concept of good governance is a salutary departive from the overly formalistic character of conventional public administration. In to day's complex world of governing, government alone is not capable of coping with myriad problems. A degree of networking with other social organisations will enhance the capacity of governnace in the society as a whole. Also this will facilitate developjment of "social capital" in terms of social groups agreed involvement and co-sharing of problem-solving.

At least, the book reveals that to the extent governance would be bringing in transparancy, openness, rule of law and human rights observance, this will facilitate strengthening of democracy.

(3) Governance for Developments; Constitutional goals and Directives : By U.C. Agrawal

While carrying out review the following gist were offered by the author.

Finally, one needs to come to terms with the fact that there is a 'price' for good governance to deliver 'development'. Among many sacrifies, on that, deserves mention is that of the freedom from the 'polities fo appeasement'. By 'politics' it is not to point fingers only at 'politicians', but also to bureaucrats, heads of institutions, business leaders, managers and decision makers across society.

There is a need to let go the little pay-offs of allowing a compromise to please people in the short run that ultimately explains for much of the baggage of apathy indifference and the appalling conditions from which we now aspire governance for development. Good Governance especially for development will demand a new level of understanding, self imposed 'discipline' of one kind. In anticipation, in being proactive and in self-regulation lies the essence of good governance.

(4) Governance for Development : By N. Vittal

According to book, Good governance will be the engine for development in a liberalized economy. The two elements of honesty and transparency are need to 'ensure governance for development'. But the one single factor that has nullified the whole process of planned economic development is the rampant corruption in our system. The concuption is

anti-economic development, anti-poor and anti-national and the supreme importance of checking the corruption is therefore obvious. This is all the more so especially when we consider that the central focus of entire planning process is on removal of poverty, and alliviating the conditions of the poor. The ability to use governance as an effective check the corruption.

Nevertheless, corruption flourishes in our country because it ia a low-risk high-profit activity so a series of legislative measures are needed to check that corruption does not come in the way of development. Equally important is to encourage whistle blowers who can expose corruption in the system.

(5) Good Governance : New Public Management Perspective : By O.P. Minocha

Following a discussion on the concept and determinants of good governance, the author discussed the experience of USA. Common wealth countries and other nations in realizing good governance. He briefly takes a look at independent India's administrative reforms efforts during 50s, 60s 1983 and 90s before taking up for discussion the unifinished agenda in this regard. The aurhor then identifies the critical areas of governmental functioning where efforts need to be concentrated.

Over the years, a large number of philosophers, academicians and public fnctionaries have been discussing ways and means of governing societies they have advocated different forms of political and administrative systems and methods of governance to reconcile the interest of the citizens with that of the role of the state. The debate is still inconclusive. During the last decade or so, there has been remarkable change int he role of government in different societies. The World Bank's Report of 1992 and emergence of new paradigm in public administration have aded a new dimension to the whole issue of governance.

(6) Ethics – The Other Name for Good Governance : By R.C. Sekhar

On reviewing the book's underlying prepoistions, "Ethics is the name, be give to our concern for good behaviour"

Following an exploration of concepts of ethics and good governance and their inter-relationship, the author examines how emphasis on this ethics can facilitate realization ofgood governance. He realtes the discussion to the nature of state and bureaucracy in the etical web of mutual expectations and attaining adminsitrations objectives of optimum control with the least transaction cost. He then raises several issues having a bearing on realizing good governance.

The analytical content of the words is distinguished from the emotional and attitudinal overtones. Much of the present writing in this area rush to be prescriptive on "what augh to be". They describe "what is", most often in caricatured style, to highlights its deviation from "what ought to be".

While treating the past with great respect, let is also draw upon more recent ethical thought, untrammeted by overload of the heavy luggage of the past, Indian or Western.

(7) Citizen's Charter- An Instrument of Public Accountability Problems and Prospects in India : By R.B. Jain

The author reviews the canging notions of accountability of government towards its citizens in different nations and examines the strategy of enforcing citizen's charter as it evolved in the U.K. giving by principles and elements of setting of characters. He then critically examines the past 1995 process of its adoption in India, giving his assessment on its strong and weak points. While concluding, he deliveates on the measure that are necessary for the success of citizen's charter scheme in India.

The Westminister model of parliament democracy, the concept of administrative accountability has primarily rested on a single principle of responsibility – "The ministerial responsibility" – that is, the responsibility of the ministers of the state to parliament. However, in recent times, this concept has been found wanting in its ability to ensure democratic control of a large, active and increasingly complex executive branch of the government.

Among various arguments advance to argument this concept with other instrumentalities of administrative accountability is that "it is now incapable by itself of sustaining a system of administrative accountability or else is underiable in this role because of its adverse effects on efficiency or an openness and responsiveness in government.

(8) The constitution of India : By Government of India, Ministry of Law and Justice, Original constitution book.

On reviewing this book, I found that it has direct and effective relevance to the topic of good governance and how the directive principles of state policy work.

The provisions centained in this part not be enforceable by any court but the principles therein laid down are neverthless fundamental in the governance of the country and it should be the duty of the state to apply these principles in making laws.

The state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life.

The state shall in particular strive to minimize the enequalities in income and endeavour to eliminate inequalities in states, facilities and apportunities, not only emongest individual but also amongest groups of people residing in different areas or engaged in different vocations.

(9) Yojana Gramih Vikas Ko Samarpi Magazine by Industry and pulication division of Government of India.

The exports of this magazines deals with the concept of good governance and its components. The article titled communication revolution and future of Information Technology contributed by Durgadutta Ojha. This article comprices of the following elements through which drastic changes using computers can be witnessed.

E-Commerce
Electronic Data Interchange
E-cash
Digital Signature
Fire Wall
E-Procurement
E-Governance

The Government of India on october 17, 2000 brought into force the law of Information Technology and E-Commerce and E-Governance were assigned legal identify.

With the help of E-Governance, the government has shown transparency in the work and all citizens of India are benefitted by way of giving them information in the fastest manner. The common man is seeking benefit of Governmental schemes in a better way.

(10) Yojana Gramih Vikas Ko Samarpi Magazine by Industry and pulication division of Government of India.

While reviewing the article bearing title "Solid Foundation to Infrastracture" written by Naveen Pant it was revealed that each and every nation is passing through an unpreceedented chows of drying-up of financial resources and how to make provisions of a budget which can strike balance between the availability of funds and ensure optimum and expected growth rate. But Indian the then Finance Minister Pranab Mukherjee made it possible and attacked on

reducing dearness, promote savings, mitigating budgetary losses and increase in growth rate. It was the result of his sincere and timely attempts which made possible to reduce dearness from 8.4 to 6.9 percemt.

Inded, right approach to budget the finds and resources is an important postulate of Good Governance.

(11) A Journal of Asia for Democracy and Development : By The Council for Peace, Development and Cultural Unity

On recviewing the article appeared on page no. 74 bearing title Public Distribution System in India. Nature and scope written by Nidhi Singh is a part and parcel of Good Governance in any of the state.

The objective of the paper is to know what is PDS (Public Distribution System), what are its objectives, how does it works, what are its role and contribution in curbing food insecurity in India. The paper also bring-out the lacunae in the functioning of this system and the recent challenges. There are few sections depending on the issue that have been dealt with. For example, the first section deals wiht the meaning of food security and Public Distribution Systemn, the second section explains the origin and evolution of PDS in India. The third section deals with the mechanism of PDS while the fourth one gives an account of its evaluation. The third section deals with the mechanism of PDS while the fourth one gives an account of its evaluation. The last section discusses about implications of the existing phenomenon and the way forward.

(12) Public Administration : By M. Laxmikant

To review this book the followng chapter were of utmost importance from the good governance point of view in a state. It has distinct feature of comparing he administrative system prevalent in different in different nation viz USA, Great Britain, France and Japan.

Secondary, personal Administration in an important fact of good governance. It operates through 'Budget' instrument and encompasses the entire 'budgetary cycle', that is formulation of the budget, enactment of the 'budget', execution of the budget accounting and auditing . The principles of sound budgeting are :-

(1) Budget should be on annual Basis

(2) Estimate should be on departmental basis

(3) Estimate should be on cash basis

(4) On budget for all financial transactions

(5) Budget in should be gross and not net

(6) Estimating should be close

(7) Rule of Lapse should be followed

(8) Revenue and Captial should be separated.

(9) Form of Estimates should correspond to form of accounts.

(13) India's Politics ; A view from the Backbench : By Bimal Jain

In the review of the book, I found the following lines which can be of immence help in good governance. A major development in the working of India's democracy in the recent years has been the emergence of the multi-party coalition, without a common ideology, as a regular form of government. This has brought about palpable change in political dynamics which was perhape not fully visualized int he original provision of our acctaimed constitution.

Another recent development is the enactment of 'Anti-Defection Law', which was expected to reduce instability, has in fact increased the threat of political instability and fragmentation of parties. The power of leaders of political partides, particularly those of small parties, has increased substantialy at the expense of ordinary members of legislatiers and their coustituents. While elections are free and fair and all

citizens of India can take legitimate pride in the multiple freedom that they enjoy in a universally acclaimed domocracy a lot is happening below the surface which should be a source of services concern.

(14) Police and Good Governance : Promotion of Human Rights : By Ved Marwah

On review the book, the factual information on the sbject is as followes.

Begining with a broader view of problems confranting our police system and an adimiration of police role despite inherent constraints, the author suggests certain measures neded to enhance police accountability to check custodial deaths. Then, focusing on human rights, he analyses the causes of brutalization of police and suggests measures to safeguards human rights.

Effective policing and maintenance of law and order are essential components of good governance. The state is a distinct identity, apart from other orginazational structure, essentially because of its police powers. Take away the police powers of the state and it becomes a very different entity. Therefore, it is not surprising that the current crises of governnace in India can traced largely to the failure of police to perform its due role. Public criticism varies at one and of the spectrum for its allged brutalization of allegatious of ineffectiveness in enforcing the rule of law at the other.

India has reasons to be proud of its democracy, but what is happening in the name of democracy various parts of the country should shame every Indian. In the face of mounting violence and crime, police performance is bound to come under police scruting. The police images has generally suffered, but in same states, like Bihar, it is much worse than in other states.

15. Dindori bags Digital India Award

District Dindori received an award for 3rd best performing district in MP. Selected by Department of Electronic and Indormation Techololgy index the Union Ministry of communication and IT. During the Digital India Week observed from July 1 to 7 of year 2015.

Representatives from the District Adminstration received the award from Hon'ble Union Minister of Communication and IT Shri, Ravi Shankar Prasad in a function organized to work the 'Good Govermance Day' on 25th December 2015 at Stain Auditorium in New Delhi.

Digital India is a programme of the central government to minimize the gap between the government departments and the common people. The District administration here had organized various programmes at the district levle as part of the celebration.

This included the launching of e-Registry at District Registrar Office, Quiz competitions were organized for students rairing awareness for digital literacy and workshops were organized briefing the core infrastructural components of Digita India Initiative.

16. Collector- SP Jan Sammvad-District Katini (M.P.)

District Administration Katni has organized collector-SP Jan Samvad in one of the Janpad Panchayat-Rithi of Katni District, which was like a camp in the open field under tents and officials of different departments made to sit in tents with the purpose of reaching people of villages so as to provide the services and benefit of various government schemes at their place.

The main aim was to provide the asked services in the same day with completion of all required formalities on the same day.

District collector has given following responsibilities to NIC Katni :-

- Development of a software to register all the application which will generate a receipt for the applicant and when the same application goes to the concerned department, it should capture departments comments and finally District Collectors comments will be entered if the service is provided and disposal will be done by District Collector and again one receipt will be provided to the Applicant with all levles comments and final disposal comments and with the asked certificate or service. All levles should get completed in one day only.

The module developed by Shri. Prajapati Delau, ADIO, NIC Sagar (M.P.) for Tour Meeting was edited as per requirment of Katni and used for this purpose ha has provided grea help and support in this regard.

- Training to official and operators who will register the applications and provided the service and dispose the application. District Collector and SP Katni has disposed and used applications by self in the group.

- To co-ordinate with BSNL for internet facility in camps and hardware arragements with the help of Janpad CEO and Tehsildar of same block.

As it was huge success and appreciated by local MLA and common people, District Collector has given appreciation to NIC for the work executed and dicided to do these camps in every 15 days in different blocks of the district.

17. District Website inauguration and demonstration of RCMS module District Shajapur, M.P.

On occassion of foundation day celebration of Madhya Pradesh Honourable Revenue Minister Govt. of M.P. Shri Rampal Singh, Shajapur MLA Shri. Arun Bhimawad alongwith other public representatives visited collectorate, collector Shajapur Shri Rajeev Sharma and other officers were also present on the occassion. During this occassion DIC Shajapur introduced following two it related activites to the present diguitaries :-

1. RCMS (Revenue Court Monitoring System) module under UTTARA Developed by NIC MP State Centre, which was implemented in the district from new revenue year 2015-16 for all revenue courts of Shajapur districts. RCMS was briefly explained to all the public representatives and officers. Honourabel Minister Shri Rampal Singh expressed happiness to know about implementation of the RCMS system for monitoring of revenue related cases.

2. Redesigned bilingual district website was inaugurated by Honorable Minister Shri Rampal Singh and Collecter Shajapur Shri Rajeev Sharma. Main features of the website were explained to all present dignataries. Website is prepared as per tamplate and instruction issued by MP State. It department regarding use of GIGW guidelines. Redesigued district.

18. Madhya Pradesh Consistently holds rank no. 1 in e District MMR implementation.

Madhya Pradesh consistently holds rank no.1 for e District project implementation (Mission Mode, Project of Deity, MCIT, G 01) across all the states/ Uts. The ranking is given Deity with a view to assess the comparative progress based on the achievement of the key project milestones i.e. physical progress of the project.

MP Government entrusted NIC, MPSC to be Software Development Agency (SDA) for the development of this prestigious MMP. MP is the second lgargest state of India where about 7.25 crore citizen are geographically spread across. Rural and urban areas in 51 Districts. The project was rolled out statwide on 25th September 2012 with the

implementation of online eDistrict Portal. The portal currently delivers 72 services of 16 Departments through 336 Lok Seva Kendra (LSK) set up across the state. The portal has registered remarkable 3.34 crore application till date.

The portal has enabled creation of electronic repository of various certificates issued by differnt departments of Govt. of Madhya Pradesh which has facililated not onle online access but also instant verification of certificates issued. Considering successful delivery of more than 1.2 crore applications online, a special drive was launched by Govt. of MP in July 2014 to issue caste certificates to about 1.5 crore eligible school going students belonging to SC, ST, OBC and Nomad category keeping in view the prime focus on marginal section of the society leveraging the MP eDistrict Platform. The portal has registered more than 1.26 crore applications under this special Drive till date.

Salient Features :-

(a) Work flow based system.

(b) Digital movement of application along with Annexure/Note Sheets etc.

(c) Facitilty for Note sheet Preparation throgh customizable predefined templates.

(d) Preparation and Digital Singing of certificates/ Documents/ order/ sanction letter/Regection letter etc.

(e) online cacellation of issued certificates.

(f) Creation of electronic repository.

(g) SMS and Email alerts.

(h) Dashboard and various drill down reports.

(i) In depth Data analyis with graphical representation.

Project Outcome :-

(1) Easy and smooth migration towards electronic delivery of services and phasing out manual delivery of services.

(2) Efficient delivery of services with improved service levels.

(3) It has reduced

  (a) Number of visits of citizens to a government office availing the services.

  (b) Adminstrative burden and service fuffillment time and costs for the government and citizens both.

  (c) Direct interaction of citizens with the government and encourage ‘e’-interaction and efficient communication through portal.

(4) Delivey of services through Kiosks by leveraging the common infrastructure viz. NIC network (NICNET), State wide Area network (SWAN), state data center (SDC)

(5) Delivery of all public services at District/Book Level in electronic form through the portal ensuring reliability, efficiency, transparency and accountability.

(6) Creation of Digitally signed electronic repository of certificates/documents.

In this article I have tried to analyse and understand the concept of good governance, what are the cathodes of government and administration through which they are serving beneficiaries, alougioith thie I have also felt necessary to know the level of awareness among the people about the good governmane. Therefore I have realized the importance of examining good governance and its development in Madhya Pradesh.

छिंदवाड़ा जिले का प्राचीन इतिहास

प्रदीप ग्वालिया, एम.ए, एम.फिल (इतिहास)

संक्षिप्त इतिहास – छिंदवाड़ा जिले के प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के लिए कोई प्रमाणिक स्त्रोत नहीं पाये जाते केवल भारतीय पौराणिक गाथाएं ही है जिसके ऐतिहासिक स्वरूप सर्वमान्य न होने के कारण उसे गौण मानकर ही विचार किया गया है।

इसी प्रकार पाषाण युग के पूर्वकाल के विषय में कुछ कह पाना सम्भव नहीं है, केवल पाषाण युग के उत्तरकाल को ही 10,000 वर्ष का माना गया है। इस उत्तरकाल के पश्चात् ताम्रयुग और लौह युग प्रारम्भ होता है। पाषाण युग के प्रारम्भिक चिन्ह नर्मदा घाटी ही माने गये हैं, किन्तु इस तथ्य को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता।

वैदिक काल में जिले तक आर्यों का आगमन नहीं हुआ ऐसा माना जाता है, क्योंकि वेदों में नर्मदा घाटी तथा विंध्याचल के अंचल का उल्लेख नहीं है, केवल उत्तरकालीन वैदिक वाग्डःमय तथा शपतथ ब्राम्हण में रेवा का उल्लेख आया है। अनेक विद्वानों का मत है कि आर्य लोग और द्रविण उत्तर तथा दक्षिण भारत में पश्चिमी देशों से और उत्तरी ध्रुव से भारत में सहस्त्रों वर्ष पूर्व सें आ गये थे, और सिंधु नदी के मुहाने तथा नर्मदा नदी के मुहाने से एक दूसरे की संस्कृतियों को लाने ले जाने, प्रचार–प्रसार करने का उन्हें अवसर मिलते रहा। यहाँ आर्यों की संस्कृति तथा दर्शन के विषय में अधिक लिखना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ यह बताना अनिवार्य है कि इस देश में आर्यों एवं द्रविणों के अतिरिक्त आर्योत्तर जातियाँ भी यहाँ निवास करती थीं, वे कहीं अन्यत्र से नहीं आयी थी। इन्हीं जातियों के लोगों को इस देश में आदिम जाति के नाम से सम्बोधित किया गया है।

बालाघाट में जो चाँदी के सिक्के पाये गये हैं वे चार चिन्ह वाले हैं, और कलिंगों के पूर्व चेदिवंश के पाये गये हैं, इनका शासन इसवी सन् से 400 वर्ष पूर्व का माना जाता है। अतः इस क्षितिज (जिले) के सिरहाने का प्रथम राजवंश 'चेदिवंश' ही मानना पड़ेगा।

अशोक काल के (जो ईसा पूर्व 263 से 236 तक था) सिक्के छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं और कलिंगों से उसका युद्ध प्रसिद्ध ही है। इसलिए अशोक और कलिंग की छाया यहाँ अवश्य ही पड़ी होगी यह जिला यद्यपि वन्य प्रांत आदिम जाति वासियों का था, किन्तु इसका दक्षिण पूर्वी भू–भाग विदर्भ के अंतर्गत ही रहा है। इसलिए विदर्भ में जिन शासकों ने शासकों ने शासन किया है, उन सभी की छत्र–छाया इस जिले पर पड़ी है।

चूँकि मोर्यों ने नंदवंश का उच्छेद किया था। ऐसा माना जा सकता है कि चेदिवंश के पश्चात् नंदवंश का शासन रहा होगा। विदर्भ में शुंग वंश का शासन था, और उन्हीं के सेवारत आंद्रवंशीय सात वाहनों का शासन आंध तक फेला था। सात वाहनों का शासन ईसवी सन् 200 तक रहा। इसी काल में भारत का व्यापार संबंध रोम तक फेला चुका था। तीसरी शताब्दी से आठवीं शताब्दी तक इस क्षितिज के दक्षिण भू–भाग तथा विदर्भ में वाकाटक वंश का शासन है। ई.पूर्व तक इस भूमि पर आर्यों या द्रविणों की संस्कृति के कोई चिन्ह नहीं पाये गये हैं। छिंदवाड़ा जिले की पूर्व दक्षिण दिशा के मैदानी भू–भाग पर पुरातत्व वेक्ताओं द्वारा कुछ प्रकाश डाला गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि नीलकण्ठी नामक गाँव के पास जो 'भग्नावेश स्तम्भ', तोरण द्वार पर कोटा प्रस्तरखण्ड तथा शिलालेख और ताम्रपत्र उत्कीर्ण पाये गये हैं, उनमें कुछ ताम्रपत्र और शिलालेख सिवनी तथा अजंता की गुफाओं से भी प्राप्त हुए हैं। उनसे यह ज्ञात होता है कि ई.पू. तीसरी शताब्दी में यहाँ राजपूत राजवंशी वाकाटकों का शासन रहा है।

इस वंश का संस्थापक 'विंध्य शक्ति' नामक वीर पुरूष था। इसका शासन सतपुड़ा पर्वत के आसपास से अजंता तक फैला हुआ था। छिंदवाड़ा के भू–भाग का भी उसमें समावेश था।

छिंदवाड़ा के निकट नीलकण्ठी ग्राम में एक स्तम्भ पर जिस पर कृष्ण तृतीय का नाम अंकित है, तथा मंदिर

के भग्नावेश व तोरणद्वार खड़े हैं, वे इसी कृष्ण तृतीय के है। यह काल ईसवी सन् 967 का है। इसके पश्चात् इसका भाई खोटिटंग राजा हुआ इसके समय में 972 ई. में परमारों ने आक्रमण कर इसकी राजधानी मालखेड़ा को लूट लिया था। इसके पश्चात् 975 ई. में चालुक्य वंशीय राजा ने दक्षिण पथ को अपने अधिकार में कर लिया था।

गौड़ राजवंशी शासक –

गौंड़ जाति का प्रारम्भिक शासन कौन था, यह इतिहास के लिए अप्राप्त है। इस्लामी शासक जब इस देश में आये उन्होंने गौंड़ों को हिन्दूओं से अलग नहीं माना था। अंग्रेजों के आने क बाद ही प्रथक्करण किया गया। इतिहासकार मानते हैं, कि गौंड़ों का पहला राजा गढ़ाकोटा का यादव राजा राय नामक व्यक्ति था। इस यादव राय के विषय में जबलपुर के कमिश्नर मिस्टर स्लीमन ने कुछ प्रमाण किवदंतियों के रूप में लिख हैं। किवदन्ती अनुसार गढ़ा के पास कटंगा ग्रामवासी सकूत गौंड कन्या ने एक नागवंशी से विवाह किया था, जिसका पुत्र धारूशाह था। इसी धारूशाह का नाती यादव राय था। दमोह जिले के सिलायरी जनपद तथा रामनगर की 53 पीढ़ी वाली वंशाली में 34वीं में मदनशाह का नाम है। वहीं गौंड़ जाति का प्रथम राजा है। किन्तु इस जिले के निकट बैतूल जिले के बदनूर गाँव से प्राप्त ताम्रपत्र जो कि 137ई. के हैं। उसमें प्रौंढ़ प्रतापी चक्रवर्ती महाराजाधिराज अचलदास ने कुओं का उद्यायन करके जर्नादन उपाध्याय को आमादह गाँव दान में दिया। अतः यह कहा जा सकता है कि वनवासी भू–भाग का पहला गौंड़ शासक वहीं अचलदास ही है। इसके पश्चात् दूसरा गौंड़ शासक संग्राम शाह (1480–1542) है जिसका नाम अमनदास था। इसके सोने के सिक्के 1513 ई. अंकित प्राप्त हुए है। यह गौंड़ जाति का बहुत बड़ा प्रतापी राजा था। इसने 52 गढ़ जीत लिये थे। कुछ लोग छिंदवाड़ा जिले के देवगढ़ की सीापना को इसी संग्राम शाह के 52 गढ़ों में से मानते हैं। सिवनी, बैतूल, होशंगाबाद तथा मंडला इन जिलों में भी इसने अनेकों गढ़ बनवाये थे। वर्तमान छिंदवाड़ा जिले के आसपास का विस्तृत भू–भाग और जिसमें पश्चिम में बैतूल तथा होशंगाबाद का कुछ भू–भाग और पूर्व में सिवनी का भू–भाग भी इसके शासनाधिकार में ही था। इसकी राजधानी हरयागढ़ और फिर देवगढ़ बनी यह विस्तृत क्षेत्र नरेन्द्र शाही के समय तक रहा।

सन् 1542 ई. में संग्रामशाह के मरणोपरांत दलपतशाह गद्दी पर बैठा था। किन्तु दलपतशाह के 1548 ई. में मरने पर रानी दुर्गावती के शासन की समृद्धता को देख मुगल बादशाह अकबर ने दुर्गावती को पराजित कर सत्ता हथियाने का षडयंत्र रचा था, और जिसमें वह सफल हुआ। इस स्थिति में गौंड़ों का शासन बिखर गया। इसी समय देवगढ़ के गौंड़ी शासन पर रणसूर एवं घनसूर नामक गौली सरदारों ने अधिकार कर लिया था। ये रणसूर एवं घनसूर सम्भवतः गौंड़ी सरदारों के अधीनस्थ सेनापति के रूप में कार्य करते थे। जिन्होंने देवगढ़ पर अपना अधिकार जमा लिया था, और इन्हीं सरदारों से जाटवशाह ने सत्ता छीन ली थी। संग्रामशाह ने गौंड़ी राज्य के विस्तार के समय देवगढ़ तथा हरदयागढ़ का इलाका खेरला के राज्य से हथिया लिया था। खेला राज्य का शासन 1398 तक यहाँ पर था, और संग्रामशाह ने 1480 ई. के पश्चात् अधिकार कर किलों की सीापना की थी। छिंदवाड़ा जिले के हर्रई स्थित गढ़ों का निर्माण भी इसी संग्रामशाह के काल में हुआ होगा क्योंकि हर्रई जागीरदार की वंशावली में संग्रामशाह के नाम का उल्लेख है।

फरिस्ता ने लिखा है कि खेरला का राजा नरसिंह राय वैभवशाली था, और वह सम्पूर्ण गौंड़वाने का शासक था। नरसिंह राय ने फिरोजशाह से संधि करने के पश्चात् 27 वर्ष तक खेरला में राज करता रहा। किन्तु मालवा के सुल्तान दिलवार खाँ गौरी के पुत्र हुशंगशाह नेक खेरला पर आक्रमण कर नरसिंह राय को 1433 ई. में मार डाला। किन्तु यह संदेहास्पद है, तब क्षेत्र मालवा के अधीनस्थ हो गया।

नरसिंहराय की 1433 ई. में मृत्यु हो जाने के पश्चात् यह इलाका यद्यपि मालवा राज्य में मिला लिया गया था। किन्तु देवगढ़ के शासक अपनी सत्ता देवगढ़ पर बनाये रहे, और मालवा की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके कुछ काल पश्चात् ही गौंड़ जाति का प्रबल राजा संग्रामशाह गढ़ाकोट में अपनी शक्ति बहुत बढ़ा चुका था। उसने 52 गढ़ों पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया था। संग्रामशाह का शासनकाल 1480 ई. से 1541 ई. तक था

उसके बावन किलों में देवगढ़ तथा हरयागढ़ के नाम का भी उल्लेख है।

संग्रामशाह ने जो इलाका नरसिंह राय के अधीन था और जिस मालवा के सुल्तानों ने अधिकार कर लिया था उन सब पर अपना शासन स्थापित कर यहाँ का सम्पूर्ण गौंड़ी राज्य गढ़कोटा राज्य के अधीन कर लिया। उस समय भी ये देवगढ़ के गौली शासक संग्रामशाह की अधीनता स्वीकार करके देवगढ़ पर अपना शासन बनाये रहे और संग्रामशाह के ही प्रतिनिधि के रूप में यहाँ राज्य करते रहे। इसलिए जाटो ने जब सत्ता हथिया लिया। उस समय यहाँ गौलियों का ही शासन प्रबंध था। संग्रामशाह की मृत्यु 1541 ई. के पश्चात् गौली शासक स्वतंत्र हो गये और गौंड़ी भू–भाग पर अपनी सत्ता जमा ली। किन्तु यहाँ के गौंड़ी जमींदारों को यह बात अखरने लगी और वे इस क्षेत्र पर पुनः गौड़ी राज्य के विस्तार की प्रतीक्षा करने लगे। इस काल में नागपुर तथा सम्पूर्ण छिन्दवाड़ा के भू–भाग की राजधानी देवगढ़ ही थी।

यह देवगढ़ छिन्दवाड़ा नगर से दक्षिण पश्चिम में 45 कि.मी. दूर भग्नावशेष और किले के खण्डहर के रूप में आज भी देखा जा सकता है। गाँव से 2 मील तक किले की चाहर दीवारी के खण्डहर विद्यमान हैं। दुर्ग के भीतर पत्थर के हौज और इमारतें थीं। बादल महल, नगार खाना और प्रवेश द्वार गिरने से बचे हुए हैं, तथा बादल महल का अष्ठ कोणी कमरा पूर्वावस्थानुसार ही स्थित है।

समाज में नारी की स्थिति

आरती झारिया, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर

प्रस्तावना–विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के निर्माण में नारी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। सभी युगों में किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का मुख्य मापदण्ड नारी की स्थिति ही रही है। स्थिति से तात्पर्य यह है, कि एक समाज विशेष में स्त्रियों का क्या स्थान है, उन्हें पुरूषों से ऊँचा, बराबर या नीचा क्या माना जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी संस्कृति में स्त्रियों के प्रति पुरूषों का क्या दृष्टिकोण पाया जाता है। इसके अलावा स्त्रियों की स्थिति के निर्धारण में इस बात का भी विशेष महत्व है कि उन्हें कौन–कौन से अधिकार प्राप्त हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उनके क्या–क्या कार्य हैं तथा उनसे किन भूमिकाओं को अदा करने की आशा की जाती है। इन सभी बातों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति, विशेषतः हिन्दू समाज में काफी उच्च रही है। उन्हें शक्ति ज्ञान और सम्पत्ति का प्रतीक माना गया है और इसी कारण दुर्गा, सरस्वती एवं लक्ष्मी के रूप में उनकी पूजा होती रही है। यहां पुरूष के अभाव में स्त्री को और स्त्री के अभाव में पुरूष को अपूर्ण माना जाता है। इसी कारण हिन्दू समाज में स्त्री को पुरूष की ''अर्धांगिनी'' कहा गया है।

यहां वैदिक और उत्तर–वैदिककाल में स्त्रियों की स्थिति पुरूषों के बराबर रही है तथा उन्हें पुरूषों के समान ही सब अधिकार प्राप्त रहें हैं धीरे–धीरे पुरूषों में अधिकार प्राप्ति की लालसा बढ़ती गयी परिणाम स्वरूप स्मृति काल, धर्मशास्त्र काल तथा मध्यकाल में इनके अधिकार छिनते गये और इन्हें परतन्त्र, निस्सहाय और निर्बल मान लिया गया परन्तु समय पलटा खाया।

अंग्रेजी शासनकाल में देश में राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जागृति आने लगी। समाज सुधारकों एवं नेताओं का ध्यान स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिये उतना प्रयत्न नहीं करना पड़ा जितना पश्चिमी देशों में करना पड़ा। यहां पिछले कुछ वर्षों में स्त्रियों की स्थिति में काफी परिवर्तन एवं सुधार हुआ है। समाज में स्त्रियों की परिवर्तनीय स्थिति को समझने के लिये विभिन्न कालों में स्त्रियों की स्थिति पर विचार करना होगा।

जाति व्यवस्था एवं अनुसूचित जाति :–जातिव्यवस्था भारतीय सामाजिक संरचना का आधार है। अखिल भारतीय वृद्ध सामाजिक व्यवस्था में जाति सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था है। जिसका ढांचा वर्ण प्रारूप है। इसमें संपूर्ण भारत में व्यापक जातियों की असंख्य भिन्नतायें पायी जाती है। जाति व्यवस्था का वर्ण प्रारूप हिन्दू समाज को चार वर्णों में विभाजित करता है। ऋग्वेदकाल में वर्ण व्यवस्था ने विभिन्न समूहों को सामाजिक आर्दश तथा कार्य व्यवस्था के अंतर्गत ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चार वर्णों में संगठित किया था इनमें से प्रथम तीन वर्णों को द्विज तथा अंतिम वर्ण को शूद्र कहा जाता था।

शनैः शनैः चार वर्ण अनेक सामाजिक विधाओं के कारण असंख्य जातियों में परिवर्तित हो गये इन विभिन्न जातियों में रहन–सहन तथा खान–पान से संबंधी विभेद व्यापक हों गये असके अलावा यह जातियां वंशकुल तथा प्रकृति आदि में विभक्त हो गई धीरे–धीरे इनमें स्थानीय भेद भी बढ़ता गया जिसके कारण जातियों के परस्पर सामाजिक संबंध भी अपनी ही उपजाति तक सीमित होते गये इस जातिगत संबंधों ने अनेक प्रतिबंधों एवं वर्णनाओं को जन्म दिया।

जाति एक प्रकार की सामाजिक इकाई है और प्रत्येक जाति को अपना विशेष आदर्श और नैतिक विधान रखने की आजादी है। जातीय संस्कृति के अनुसार जातियों के धर्माधिकारी ब्राम्हण हैं और अन्य सभी जातियां ब्राम्हणों से नीचे हैं। परन्तु सबसे नीचे है, अस्पृश्य या अछूत जाति व्यवस्था की मूलभूत की विशेषताओं में अधिकांश संस्थात्मक प्रकृति रहती है तथा वे जाति व्यवस्था के आवश्यक तत्व माने जाते हैं इन्हीं में से कुछ जातियों की सामाजिक गतिशीलता पर निषेध और उसकी निम्न सामाजिक स्थिति एवं नियोग्यता से संबंधित है।

विभिन्न कालों में अस्पृश्य जाति की स्थिति

भारतीय ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था सामाजिक संरचना का आधार है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जाति व्यवस्था एक मूल तत्व के रूप में स्पष्ट होती है। तथा जाति व्यवस्था के मानकों के आधार पर यहां प्रत्येक जाति अपने सदस्यों पर एक निश्चित निषेधों एवं उत्तरदायित्वों को लादता है वही यह संपूर्ण हिन्दू समाज के लिए भी निश्चित निर्देशों को प्रस्तुत करता है। भारत में छोटी–बड़ी सभी जातियों की कुल संख्या 3000 से भी अधिक है। परन्तु मुख्य वर्ग या जाति केवल चार ही हैं। ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। प्रथम तीन वर्णों को द्विज कहा जाता है।

ऋग्वेद के पुरूषसूक्त जैसी उत्तर कालीन ऋचाओं में ब्राम्हण, राजन्य, वैश्य और शूद्र नामक चार वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, जो क्रमशः विराट पुरूष के मुख, बाहु, जांघ और पैर से उत्पन्न हुए थे इन वर्णों का शरीर के विभिन्न अंगों से तुलनात्मक संबंध तथा जिस क्र म से इनका निवेष किया गया है वह तत्कालीन समाज में उनकी क्रमानुसार स्थिति का परिचायक है।

प्रो. श्रीनिवास

1. गांव के नाई जब नगरों में चले जाते है तो वे बाल काटने की दुकानों में काम करने लगते हैं।
2. धोबी, धुलाई घरों में तथा लौहार फर्नीचर की दुकानों में काम करते हैं।
3. ऐली यदि तेल नहीं निकालते तो वह तेल बेचने का कार्य करने लगते हैं।
4. मली बागवानों में, चमार जूतों की दुकानों में तथा ब्राम्हण रसोइयों तथा शिक्षकों एवं वकीलों की तरह काम करने लगते हैं।

राजनीतिक सक्रियता:–डॉ. अम्बेडकर के अनुसार :– यदि अनुसूचित जातियां अपने को एक पृथक दल के रूप में संगठित करके राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ले तो उनका राजनीतिक उद्धार हो सकता हैं। 1928 में साइमन कमीशन से अनुसूचित जातियों के लिये विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व तथा वयस्क अधिकारों की मांग की एवं 1942 में अनुसूचित जाति संघ की सीापना की तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनुसूचित जातियों की बड़ी संख्या के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया।

इसके विपरात महात्मा गांधी ने हरिजनों को हिन्दू समाज में एकीकृत किया। इन्होंने देशव्यापी सृजनात्मक कार्यों व अस्पृश्यता के विरूद्ध चलाये अभियान के माध्यम से अन्य जातियों की चेतना जागृत करनी चाही। इन्हीं के प्रयासों से अंग्रेजी सरकार ने पूना समझौते के अंतर्गत विधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की स्वीकृति दी। गांधी जी की प्रभावशीलता के कारण ही डॉ. अम्बेडकर पुनः जाति व्यवस्था में शामिल हो गये एवं अनुसूचित जातियां हिन्दु धर्म में ही रही। स्वतंत्रता के 60 वर्ष के बाद भी अनुसूचित जातियां में वांछित परिवर्तन नहीं हो पाया है। इसमें कुछ व्यक्तियों परिवारों एवं समूहों ने सामाजिक गतिशीलता अर्जित की है, परन्तु अनुसूचित जातियों की एक बड़ी संख्या आज भी समाज में पिछड़े वर्ग का भाग है। यदि वर्ग सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है।

आदिकाल से ही मानव उत्सुकता के साथ अज्ञात के बारे में जानने एवं समझने का प्रयास करता रहा है। अपनी इस उत्कृष्ट अभिलाषाओं से वशीभूत होकर ही नई–नई चीजों का सफलतापूर्वक खोज करने में कामयाब रहा हैं। परिणाम स्वरूप विश्वसनीय निश्चयात्मक एवं प्रमाणिक ज्ञान कि तरफ सतत् प्रयत्नशील रहा है पी.वी. यंग का कथन है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक वास्तविकता की परस्पर संबंधित प्रक्रियाओं की एक अनुशासित पूछताछ एवं विश्लेषण हैं सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य प्रकट की गई बातों के एक दिये हुए समग्र में तथ्यों को स्पष्ट करना सामाजिक प्रस्थिति के अंतर्गत तथ्यों के क्रम एवं संबंधों के विशिष्ट निर्धारकों का पता लगाना स्पष्ट अवधारणाओं की पुर्न परीक्षा करना है जिनके विषय में सामाजिक जीवन की परिभाषा करने का विश्वास किया जाता है।

अनुसूचित जाति को सामाजिक, राजनीतिक चेतना व सक्रिय सहभागिता के विकास हेतु विभिन्न विविध प्रयास किया गया है। स्वतंत्रता के पूर्व अनुसूचित जातियों पर अनेक शोध हुये है यद्यपि इन शोधों में कुछ नये तथ्य सामने आये हैं, किन्तु अनुसूचित जाति में सामाजिक सहभागिता, राजनीतिक चेतना सत्ता स्तर पर अभी भी इसमें अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

कृपया अपने परिवार के विभिन्न पुश्तों के व्यक्तियों की शैक्षणिक उपलब्धियाँ बतायें–

पितामही

क्र.	पितामही की शिक्षा की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	निरक्षर	48	80.00%
2.	साक्षर	2	3.33%
3.	प्राथमिक	10	16.66%
4.	माध्य	–	–
5.	माध्यमिक	–	–
6.	कॉलेज	–	–
योग		60	100%

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि 80 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पितामही निरक्षर है, स्थिति के है। 3.33 प्रतिशत उत्तरदात्रियों की पितामही साक्षर स्थिति है तथा 16.66 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के पितामही प्राथमिक शिक्षा की स्थिति के हैं।

अतः निरीक्षण करने पर स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक(80%) प्रतिशत उत्तरदात्रियों की पितामही निरक्षर स्थिति के हैं।

सारांश :–भारतीय ग्रामीण हो या नगरीय समाज में जाति व्यवस्था सामाजिक संरचना का आधार है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जाति व्यवस्था एक मूल तत्व के रूप में स्पष्ट होती है तथा जाति व्यवस्था के मानकों के आधार पर जहां प्रत्येक जाति

अपने सदस्यों पर एक निश्चित निषेधों एवं उत्तादारत्रियों को लादता हे वहीं यह संपूर्ण हिन्दू समाज के लिए भी निश्चित निर्देशों को प्रस्तुत करता है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी, ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, जिसमें शूद्रों के द्वारा विद्या, शिक्षा, याज्ञिक क्रिया आदि करना वर्जित था इसके लिये दण्ड का प्रावधान था।

महाभारत से ऐसे संकेत मिलते हैं कि समाज में शूद्रों की स्थिति दयनीय थी किन्तु कुछ शूद्र अपने सत्कर्मों एवं सदाचरण से अपनी प्रतिष्ठा को उच्च बना सकते थे। शूद्रों के प्रति उदारता का बर्ताव किया गया तथा उनके प्रति सहृदय प्रदर्शित की गयी युधिष्ठिर ने अपने राजसूयश यज्ञ में शूद्रों को भी निमंत्रित किया गया था जो तत्कालीन उदान भावना का प्रतीक है। मध्यकाल के आते–आते वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो चुकी थी, प्रथा शूद्रों को अस्पृश्य जाति के रूप में सीान प्राप्त था। इस काल में विभिन्न सामाजिक सुधार हुए फिर भी अस्पृश्य जातियों की स्थिति पुरातन ही रही।

19वीं शताब्दी भारत के इतिहास में सुधार युग के रूप में प्रकट हुई ब्रम्ह समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज रामकृष्ण मिशन जैसे संस्थानाओं के माध्यम से राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि ने अस्पृश्यता निवारण के लिए अत्याधिक प्रयास किये गये तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं अन्य संस्था के माध्यम से अस्पृश्यता निवारण हेतु प्रयास आरंभ कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त अस्पृश्य जातियों के सुधार के लिये महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका निकाली तथा डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अस्पृश्य जातियों को निम्नता की मानसिकता से उभारने के लिये बौद्ध धर्म स्वीकार किया इस काल में स्वतंत्रता के पश्चात् विभिन्न नौकरियों, शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई।

उत्तरदात्री की आयु वर्गीय से स्पष्ट होता है कि अधिकांश (43.33) प्रतिशत उत्तरदात्रियां 31 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की है, अनुसूचित जाति में सर्वाधिक(48.33) प्रतिशत उत्तरदात्रियां 'मेहरा' जाति की हैं। तथा शत् प्रतिशत हिन्दू धर्म को मानने वाली हैं, तथा, शत् प्रतिशत विवाहित स्थिति की हैं जिसमें विवाह के समय आयु सर्वाधिक 56 प्रतिशत उत्तरदात्रियां 16 से 20 वर्ष के बीच की आयु की हैं। एवं उत्तरदात्रियों के यहां अधिकांश 80 प्रतिशत परिवार का स्वरूप एकाकी पाया गया जिसमें (73.33) प्रतिशत परिवार के मुखिया के रूप पति को निरूपित किया गया है, तथा (20) प्रतिशत परिवार में ससुर को, (6.66) प्रतिशत परिवार में स्वयं उत्तरदात्रियों को मुखिया पाया गया है एवं परिवार के सदस्यों की संख्या में (4सदस्य) वाले सर्वाधिक (30) प्रतिशत परिवार पाये गये, एवं सर्वाधिक (48.33) उत्तरदात्रियों की परिवार की आर्थिक स्थिति(5000 से कम) रूपये प्रतिमाह तक की है परिवार में मुखिया के व्यवसाय में सर्वाधिक (48.33) प्रतिशत मजदूरी करते हैं। अनुसूचित जातियों के बदलते परिवेश में सर्वाधिक (56.66) प्रतिशत मकान का प्रकार पक्का है, जिसमें (51.66) प्रतिशत उत्तरदात्रियों का स्वयं का मकान है।

उत्तरदात्रियों के विभिन्न पुश्तों के व्यक्तियों शैक्षणिक उपलब्धियों में अधिकांश (80) प्रतिशत उत्तरदात्रियों की 'पितामही' निरक्षर स्थिति की है, तथा (61.66) प्रतिशत 'मातायें' निरक्षर स्थिति की हैं, इसी प्रकार स्वयं की शिक्षा में परिवर्तन होकर अधिकांश उत्तरदात्रियां (33.33) माध्यमिक स्थिति की हैं। (अनुसूचित जाति) में महिलायें अपनी लड़कियों को शत् प्रतिशत शिक्षित करना चाहती है, जिसमें सर्वाधिक (45) प्रतिशत उत्तरदात्रियां लड़कियों को कॉलेज डिग्री की शिक्षा दिलाना चाहती हैं और आगे की पढ़ाई के लिये (53.33) प्रतिशत उत्तरदात्रियां से ज्ञात हुआ कि शिक्षा ही आधुनिक समाज में समानता लाने का शत् प्रतिशत सशक्त माध्यम है सर्वाधिक (83.33) प्रतिशत् उत्तरदात्रियां लड़कियों को पढ़ाकर उनका नौकरी करना उचित समझती हैं।

संदर्भ ग्रंथ –

1. समाजशास्त्र, प्रो. एम.एल. गुप्ता एवं प्रो. डी.डी. शर्मा, साहित्य भवन पब्लिकेशन, समकालीन उच्चतर
2. समाजशास्त्रीय सिद्धांत (2011) – डॉ. रवीन्द्र नाथ मुकर्जी, विवेक प्रकाशन
3. समाज कार्य, डॉ. जी.आर.मदन विवेक प्रकाशन
4. भारतीय सामाजिक, एम.एल, दोषी एवं पी.सी.जैन, नेशनल पब्लिसिंग हाउस,
5. समाजशास्त्र प्रतियोगिता साहित्य (2011)– डॉ. जी.एल. शर्मा, उपकार प्रकाशन, भोपाल।

गिरीश पंकज के व्यंग्य की धार और सामाजिक यथार्थ

डॉ. (श्रीमति) रूचि अर्जुनवार

मुख्य शब्द – विचारधारा, परिवेश, विसंगतियां, चेतना, चिट्ठा, चिकित्सक, अस्त्र

सारांश –

व्यंग्य साहित्य जगत् की सशक्त विचारधारा का सृजन हैं। साहित्य समाज का दर्पण हैं, इसलिए आज के सामाजिक जीवन की सही तस्वीर व्यंग्य साहित्य में स्पष्ट देखी जा सकती हैं, गिरीश पंकज के व्यंग्य वर्तमान समय की विसंगतियों, विषमताओं तथा विद्रूपताओं की तह में जाकर जॉच पड़ताल कर समाज की यथार्थता को उजागर करते हैं। तथा वर्तमान परिवेश की दुष्प्रवृत्तियों का सच्चा चिट्ठा खोलकर रखते हैं। व्यंग्यकार एक चिकित्सक के समान होता है, जो मरीज के रोग, कीटाणुओं या सड़े हुए अंगों का इजाल करता है। अच्छे अंगो को वह स्पर्श नहीं करता। व्यंग्यकार की दृष्टि भी इसी तरह की होती हैं।

प्रस्तावना–

व्यंग्य हिन्दी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा हैं। वह सार्थक व रचनाधर्मी साहित्य हैं। सरोकारों का साहित्य हैं। यह साहित्य अपेक्षाओं, नैतिकताओं और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए हैं। यह आदर्शो की स्थापना के लिए तिलमिलाहट का साहित्य हैं। व्यंग्यकार वास्तव में देश का पहरूआ होता हैं। व्यंग्य उसका अस्त्र हैं, जिससे वह सामाजिक, राजनैतिक, असंगतियों, विसंगतियों पर, विडम्बनाओं और विद्रूपताओं पर गहरी चोट करता हैं। साधारण आदमी के जीवन की भयावहता , उसकी त्रासदी, निर्दोष होने पर भी कसूरवार ठहराए जाने की यंत्रणा को व्यंग्यकार ही समझता हैं, और उसका साथ भी देता हैं।

गिरीश पंकज जिन्होंने हिन्दी व्यंग्य धारा को अपनी अप्रतिम सृजन प्रतिभा से समृद्ध किया हैं। हिन्दी व्यंग्य विधा को सफलता के शिखर पर ले जाने वाले गिरीश पंकज व्यंग्य के अनन्य हस्ताक्षर हैं। इनके व्यंग्य वर्तमान की राजनैतिक, धार्मिक व सामाजिक विसंगतियों का विस्तृत लेखा–जोखा हैं। उनके व्यंग्यों में विनोद का प्रभाव भी रहता हैं, जो पाठक को गुदगुदाता तो है, परन्तु उसे संज्ञा शून्य नहीं बनाता, बल्कि उसके मस्तिष्क को सक्रिय रखता हैं।

आधुनिक हिन्दी व्यंग्य में हमें कई प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियों के दर्शन एक साथ हो जाते हैं। प्रायः इन प्रवृत्तियों के पीछे व्यक्ति और समाज का संघर्ष हैं।

वर्तमान युग व्यक्ति और समाज के संघर्ष का युग हैं। व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की माँग हर दिशा में, हर स्थिति और हर क्षेत्र में करता हैं, तो समाज भी अपने प्रति व्यक्ति के दायित्व को समझते रहने की माँग और समझाते रहने का प्रयास करता हैं। सत्यान्वेषी प्रश्नों से आज का साहित्यकार जूझता रहा हैं। इन्ही प्रश्नों से बुद्धिजीवियों को भी झकझोरा व मथा हैं।

गिरीश पंकज जी ने वर्तमान के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए अपने व्यंग्य उपन्यास ' मिठलबरा की आत्मकथा' में पत्रकारिता की विद्रूपताओं को उजागर किया हैं। सम्पादक उद्योगपति के हाथ की कठपुतली होने को विवश हैं, क्योंकि अखबार एक उद्योग हैं। अखबार को चलाने के लिए मालिकों और संपादकों को कैसे–कैसे षडयंत्रों का सहारा लेना पड़ता हैं, इसका प्रत्यक्ष चित्रण करने का प्रयास लेखक ने अपने उपन्यास में किया हैं। विसंगतियों के विरूद्ध लिखने वाले प्रायः स्वयं विसंगतियों के शिकार होते हैं। छोटे शहर की मानसिकता, उसके मध्य पैसे के लिए अपने प्रभुत्व के लिए पूँजीपति का सारी नैतिकता को दरकिनार करके अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, उपन्यास के पन्नों को एक ऐसा आईना बना देता हैं, जिससे इस इक्कीसवी सदी की दशा या दुर्दशा को स्पष्ट देखा जा सकता हैं। लेखक जो स्वयं उपन्यास के नायक भी हैं, अपने अखबार के बारे में स्पष्ट करते है कि '' सरायपुर टाइम्स को ' कसाई बाडा ' कहते हुए अब मुझे

तनिक भी अफसोस नहीं हैं। कसाई मालिकों के यहाँ नौकरी करके में खुद भी कसाई बन गया था।''1

गिरीश पंकज ने संपादकों के प्रति असंतोष व्यक्त किया हैं, वे नाम छपास प्रेमी, नेताओं द्वारा किए जाने वाले दुष्कर्मो एवं षडयंत्रों को स्पष्ट किया हैं, और बताया हैं कि अपनी स्वार्थ सिद्धी के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाते है और किस हद तक गिर जाते हैं। पत्रकारिता जैसे सम्मानजनक कार्य के पीछे सज्जनता का नकाब पहने चरित्रहीन व्यक्तियों के चेहरे भी बेनकाब करके उनके चरित्रहीनता के काले कारनामों को प्रस्तुत किया हैं। गिरीश पंकज जी ने 'मिठलबरा' को साहित्य के नाम पर एक गहरा धब्बा कहा हैं। वह शर्म और लिहाज की सारी सीमाओं को लांघकर पत्रकारिता जगत् को कलंकित करता हैं। उसका चरित्र 'मिस जूली' के चारों आरे ही केन्द्रित रहता हैं वह कपडों की तरह अपनी प्रेमिका को बदलते रहता, तथा उनका शोषण करके चूसे हुए आम की गुठली की तरह फेंक देता हैं। लेखक ने मिठलबरा के चरित्रहीनता के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए कहा हैं कि '' चाय की चुस्कियों के साथ–साथ हम दोनों नजरों की चुस्कियाँ लेते रहे, फिर जिसका डर था, बेदर्दी वही बात हो गई। वह सब हो गया जो सामाजिक दृष्टि से अनैतिक और पाप माना जाता हैं।''2 गिरीश पंकज ने मिठलबरा की आत्मकथा उपन्यास में पत्रकारिता जगत् के अन्दर की अलग–अलग विकृतियों को ध्यान में रखकर भारतीय पत्रकारिता जगत् की समस्याओं की यथार्थ अभिव्यक्ति दी हैं।

वर्तमान युग में पाश्चात्य संस्कृति का किस प्रकार अंधानुकरण किया जा रहा है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 'मिठलबरा की आत्मकथा' उपन्यास की नायिका 'मिस जूली' में देखा जा सकता हैं। उपन्यास की नायिका–मिस जूली हैं, जो सरायपुर टाइम्स की मेनका कहलाती हैं। यह एक आधुनिक लड़की हैं जो जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हैं। चुलबुली बातें करके लोगों को फंसाना इसकी विशेषता हैं। जब नायक मिठलबरा चरित्र हीनता के सागर में गोता लगाता हैं, तो नायिका मिस जूली इससे कैसे अछूती रह सकती हैं, संस्कार हीनता उसके चरित्र को और भी धूमिल करती हैं। संस्कारों की कमी के कारण उसकी भाषा में अभद्रता झलकती हैं। मिस जूली एक बिंदास लड़की हैं, जो समाज में प्रतिष्ठा को कोई अहमियत नहीं देती हैं। अल्प शिक्षा के कारण वह अपने चरित्र को और अधिक गर्त में गिरा देती हैं। गिरीश पंकज जी ने अपने उपन्यास में बताया हैं कि पाश्चात्य सभ्यता को अपनाकर आज की युवा पीढ़ी चरित्रहीन होती जा रही हैं।

गिरीश पंकज ने वर्तमान समय में माँ के परिवर्तित रूप के माध्यम से उत्तर आधुनिकता के युग का यथार्थ; व्यंग्य शैली में प्रस्तुत किया हैं। जैसा बीज बोया जाता हैं, पौधा भी वैसा ही फल देता हैं। आज माताओं के पाश्चात्य संस्कृति के प्रति आकर्षण ने उनके बच्चों को भी पथभ्रष्ट किया हैं। फलतः उनके लिए भी परिवार और समाज तुच्छ हैं। बच्चों के मन में बडों के लिए सम्मान का भाव नहीं रहा। लेखक ने इसी तथ्य को 'पालीवुड की अप्सरा' उपन्यास में 'पैरी' के माध्यम से इस यथार्थ की पुष्टि की है, '' हुहँ, ये गाँव के बूढ़े–खूसट और गँवार लोग क्या जाने की इज्जत घटाई या बढ़ाई हैं ..... मुझे इन टुटपुजिएँ गाँव के लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं।''3

इस प्रकार गिरीश पंकज जी ने वर्तमान समय में बदलती विचारधारा के द्वारा वर्तमान के प्रति असंतोष व्यक्त किया हैं, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति परिवार से विरासत में प्राप्त होती हैं। जब माता पिता ही पथभ्रष्ट होंगे तो आगे की पीढी से क्या उम्मीद की जा सकती हैं। आधुनिक सभ्यता की अंधी दौड़ में शामिल प्रत्येक व्यक्ति अपने–अपने स्वार्थो की पूर्ति में लगा हुआ हैं। उसे अपने निजी स्वार्थो के चलते समाज तथा देश से कोई लेना देना नहीं होता हैं। लेखक ने समाज की इस प्रवृत्ति पर करारा व्यंग्य करते हुए अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को आईना दिखाने का प्रयास किया हैं ताकि परिस्थितियों में सुधार किया जा सकें।

सामाजिक यथार्थ को ग्रहण करने की प्रवृत्ति गिरीश पंकज जी की रचनाओं की प्रमुख प्रवृत्ति हैं। वे समाज की यथार्थता को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तथा समाज की वास्तविकता को सभी के सामने लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रवृत्ति के अन्तर्गत रचनाकार अपने निजी सुख–दुख को समाज के सुख–दुख में तिरोहित कर डालता हैं। उसका न अपना कोई दुख होता हैं, न सुख, सब समाज का होता हैं। वह अगर विद्रोह भी करता हैं तो उसकी मान्यताओं के प्रति, उसकी व्यवस्था के प्रति। वह परिवर्तन का मार्ग भी अपने विद्रोह के बल से खोज निकालना चाहता हैं। इनकी व्यंग्य रचनाओं में समष्टिवादिता के साथ–साथ मानव कल्याण की इच्छा भी हैं। मात्र आध्यात्मिक अथवा भौतिक उपलब्धियों

को अधिक महत्व न देते हुए इसमें जन कल्याण की भावना हैं। लेखक सामूहिक चेतना के माध्यम से सामाजिक यथार्थ को अधिक तीव्रता से व्यक्त करने का प्रयत्न किया हैं।

गिरीश पंकज ने समाज में फैली शिक्षित बेरोजगारी को ''ग्रेजुएट पान भण्डार'' के माध्यम से व्यक्त किया हैं। बेरोजगार व्यक्ति अथक प्रयास करता हैं, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पाती, इसलिए वह एक पान की दुकान खोल लेता हैं। जिसका नाम ग्रेजुएट पान भण्डार रखता हैं। धीरे–धीरे पान की दुकान लोकप्रिय होने लगती हैं, जिसमें बेरोजगारों को पचास प्रतिशत की छूट थी। यह तो बेकाम लाल की अपनी सद्भावना थी, बेरोजगारों के प्रति। वह 'नो लॉस, नो प्राफिट' के आधार पर बेरोजगारों के लिए सदैव समर्पित रहता था, तथा नेताओं, सेठों और इसी तरह की दूसरी नस्लों से पूरा पैसा वसूलता था। व्यंग्यकार गिरीश पंकज ने 'ग्रेजुएट पान भण्डार' व्यंग्य में आरक्षण एवं शिक्षित बेरोजगारी की समस्या पर गहनता पूर्वक विचार कर सामाजिक, यथार्थता का चित्रण किया हैं – '' धीरे–धीरे बेरोजगारों को यह 'ग्रेजुएट पान भण्डार' नई प्रेरणा देने लगा। कभी कभी पान भण्डार का टेपरिकार्डर जब 'हम होंगे कामयाब एक दिन' वाला गीत बजाता तो बेरोजगार युवक दोगुने उत्साह से आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भिड़ जाते। वे सोचते आज नही तो कल उन्हे नौकरी जरूर मिलेगी। आरक्षण के कारण वे जरूर पिछड़ रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक ? वे इस मुगालते में रहते कि कल जरूर आरक्षण खत्म होगा। उनके ऐसे विचार सुनकर एक बूढ़े से दिखने वाले आदमी ने कहा– '' वर्षो पहले तुम्हारी तरह मैं भी यही सोचता था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा सोचना मूर्खता थी। मेरे बाल सफेद हो गए हैं, और आरक्षण उसी तरह जवान हैं, जैसा बीस साल पहले था। मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं सत्तर प्रतिशत वाला था। एक दूसरा युवक तीस प्रतिशत अंक पाने के बावजूद नौकरी पा गया। कई प्रयास किये मैंने लेकिन 'आरक्षण' ने मेरे 'सरकारी भविष्य' का 'भक्षण' कर लिया।''4

गिरीश पंकज ने स्वास्थ्य सेवाओं के गिरते स्तर को अपने व्यंग्य के द्वारा व्यक्त किया हैं कि किस तरह शासकीय चिकित्सालयों की स्थिति खराब होती जा रही हैं। वहाँ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की अनदेखी की जा रही हैं। साथ ही साफ–सफाई का भी अभाव होता हैं। लेखक ने अस्पताल की दयनीय दशा का वर्णन '' कथा तीक्ष्णदंत के अस्पताल पहुँचने की '' शीर्षक व्यंग्य में किया हैं – '' सरकारी अस्पताल में तीक्ष्णदंत को प्रवेश करते हुए देख श्रीमान् काकरोच तो फूले नहीं समाये। गाना गाने लगें– ' दीवारों कचरा बरसाओं, मेरा मेहबूब आया हैं।' छिपकली बाई ने भी स्वागतम् गान पेश किया – ' बल्ड बैंक सजा हैं, चले आइये, आपकी बस कमी थी, चले आइये।' खटमल–मच्छर बंधु रक्तमाला लेकर पहुँचे। आइए आपका था इंतजार। आना था, आ गए, कैसे नहीं आते सरकार। मक्खी रानी ने भी कान के पास भिनभिनाते हुए कहा वेलकम इदन अवर हैंवेन।''5

शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा हैं। शिक्षा जैसे ज्वलंत मामले में प्रशासन भी कुछ कर पाने में असमर्थ हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए प्रशासन द्वारा नित नए प्रयोग किये जा रहे हैं, फिर भी शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर नहीं लाया जा सका हैं। प्राचीन गुरू–शिष्य परम्परा का तो जैसे अवसान ही हो गया हैं। एक तरफ जहाँ शिक्षित बेरोजगारी में दिनोंदिन वृद्धि होती जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा मानों अंको का खेल बनकर रह गई हैं। विद्यार्थियों के पास गहन चिंतन मनन् के लिए समय ही नहीं हैं। लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक डिग्रियाँ हासिल करने में लगे हुए हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए व्यंग्यकार गिरीश पंकज ने अपने पहले व्यंग्य संग्रह का नाम 'ट्यूशन शरणम् गच्छामि' रखा हैं। जिसमें उन्होंने शिक्षा के बदलते सामाजिक परिवेश का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया हैं। बच्चों पर लदे बस्ते के बोझ तथा शासकीय स्कूलों की दयनीय दशा पर गिरीश पंकज जी ने इस प्रकार व्यंग्य किया हैं '' उसी दिन दूसरे बस्ताधारी बालक से भी मुलाकात हो गई। उसकी पीठ पर भी बस्ता था। पीठ भी झुकी हुई थी। मैंने उसे रोका और पूछा– ' नन्हें मुन्ने बच्चे तेरे बस्ते में क्या हैं? लड़के ने बस्ता नीचे नहीं उतारा। बस मेरी तरफ देखने लगा– 'कापी–किताबें हैं।' बड़े होकर क्या बनना चाहते हों?' 'बाबू ..... । इससे अधिक का सपना मेरे पिताश्री देखते ही नहीं। कहते हैं, मन लगाकर पढ़ो, बाबू तो बन ही जाओंगे।'

मैं समझ गया। बालक मध्यम वर्गीय परिवार का रत्न हैं और किसी सरकारी स्कूल में पढता हैं। फिर भी पूछ लिया–

'किस स्कूल में पढ़ते हो?'

'आगे ही तो हैं शासकीय प्राथमिक पाठशाला। वही।'

'वहाँ क्या पढ़ते हो?'

'पढ़ना क्या, वहाँ तो ठीक से पढ़ाई ही नहीं होती। मास्टरों की कमी हैं। बिल्डिंग चरमरा रही हैं। बैठने में डर लगता हैं सारा ध्यान छत की तरफ लगा रहता हैं। जाने कब टपक जाए। हमारी असली पास होने वाली पढ़ाई तो परीक्षा के समय में ही होती हैं। वह भी ट्यूशन लगाने पर।''6

लेखक ने आतंकवादियों के द्वारा किए जा रहे अत्याचार को भी व्यंग्य के माध्यम से व्यक्त किया हैं। आतंकवाद, विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती हैं। आतंकवादी किस प्रकार मानवता को ताक पर रखकर खून की होली खेलते हैं, इसके संबंध में गिरीश पंकज जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं– '' हम समतावादी समाज रच रहे थे। वह हमारे रास्ते का रोड़ा था, बाधक था, शोषक था .....सो हमने उसे खल्लास कर दिया हमारी यही परम्परा हैं ..... '' हत्या करके समतावादी समाज की रचना? बाप रे, बड़ा भयानक काम कर रहे है आप लोग? मेरा मतलब हैं कि बड़ा पवित्र काम कर रहे हैं। यही सिलसिला चलता रहा तो देश तो स्वर्ग हो जाएगा। जै हो आप लोगों की।'' जी हाँ, और कोई रास्ता नहीं हैं। देखिएगा। कुछ ही दिनों में हम देश को श्मशान बना देगें। हम लोग सारे पापियों को निबटाने के लिए पैदा हुए हैं।''7

समाजवाद का ढोंग करने वाले देश को घुन की तरह खाने लगे। स्वार्थो के वशीभूत हुए विरोधी को हटाकर कुर्सी हथियाने के लिए सिद्धाँतहीन दलबदल की प्रवृत्ति इतनी तीव्रता से बढ़ी है कि 'आयाराम–गयाराम' इनका प्रतीक शब्द बन गया। सच्चाई से कटी हुई लम्बी–चौड़ी स्वार्थी बहसें, शांति के कृत्रिम प्रयत्न, राजनीति की बिडम्बनाओं और विसंगतियों के अहसास ने 'पालीवुड की अप्सरा' उपन्यास में गिरीश पंकज को ऐसी विद्रूपताओं पर प्रहार करने पर विवश कर दिया।

गिरीश पंकज जी ने राजनीतिक स्वार्थो को दिखाने का प्रयास किया है, कि कैसे शहरों में फैली भ्रष्ट राजनीति अब गाँवों में भी पसर रहीं हैं और उनको लील रही हैं। गरीब लोगों को मोहरा बनाकर अफसर अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। ' पालीवुड की अप्सरा' उपन्यास में वर्णित चैनपुर गाँव, जो कभी 'चैन' का प्रतीक था, उसकी शांति भंग करने, उसके स्वच्छ वातारण को दूषित करने व अपने कारोबार के प्रसार हेतु नेता लोग गाँव की जमीनों को हड़पते जा रहे हैं। गाँव निवासियों के सुखचैन को छीन उन्हें बेरोजगार बना रहे हैं। सुमेधा के शब्दों में – '' ये गाँव के लोग जोड़–तोड़ करके गाँव में अपनी फैक्ट्री तो लगा लेते हैं, लेकिन अपना पूरा प्रदूषण गाँव वालों के जीवन में डालकर मौज करते हैं, जैसे कुछ काम – पिपासु लोग किसी मासूम लड़की के साथ मुँह काला तो कर लेते हैं, लेकिन बेचारी को मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ते। ये पैसे वाले भी धरती के साथ यही करते हैं। धरती पर कारखाने लगाते है; और उसके चेहरे पर प्रदूषण की कालिख पोत देते हैं। नदियों को इंसान तो क्या पशुओं के पीने लायक भी नहीं छोडते।''8

आज का आदमी एक विचित्र प्रकार के आर्थिक चक्रव्यूह में फँसा हुआ दिखाई देता हैं। जहाँ एक ओर उसकी आवश्यकताएँ उत्तरोत्तर बढ़ती गई हैं, वहाँ दूसरी ओर उसके साधन अत्यंत सीमित हो गये हैं। एक सीमित वेतनमान पाते हुए मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपनी छोटी–छोटी आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं कर पाता। यहीं से रिश्वत का चक्कर शुरू हो जाता हैं। एक ओर वह स्वयं रिश्वत का शिकार बनता हैं, तो दूसरी ओर उसकी पूर्ति के लिए अथवा अपना आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए उसे दूसरों को रिश्वत का शिकार बनाने के लिए विवश हो जाना पड़ता हैं। वह रिश्वत देता हैं, तो उसे रिश्वत लेनी भी पड़ती हैं। यही रिश्वत का चक्कर हैं और विडम्बना यह हैं, कि वह इस भ्रष्टाचार को बुरा समझता हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही भ्रष्टाचार, उसके जीने की शर्ते भी हो जाता हैं। इसी तथ्य को गिरीश पंकज ने अपने व्यंग्य '' अथश्री रिश्वत गुण गानम्'' में प्रस्तुत किया हैं – '' रिश्वत एक ऐसी नदी है, जहाँ अफसर, बाबू और चपरासी, एक साथ पानी पीते हैं। जैसे– लुटेरे, डकैत, चौर एवं ठग आदि माल का बंटवारा बराबर करते हैं। रिश्वत को हम एक 'पुल' की तरह मान सकते हैं। जो दो दिलों को जोड़ने का काम करती हैं। रिश्वतवाली यारी जीवन भर चलती हैं। किसी न किसी रूप में रिश्वत शरणम् गच्छामि होना ही पड़ता हैं, इसलिए गड़बड़ कविराए फरमाते हैं –

'' लेन–देन में नहीं, करो तनिक संकोच,
कलजुग का परसाद है, जाने सब उत्कोच।''9

गिरीश पंकज जी ने वर्तमान में हो रहे मोहभंग के यथार्थ को अपनी व्यंग्य रचनाओं के द्वारा व्यक्त किया हैं। यह व्यंग्य लोगों को मन से जगाने का एक कठिन एवं अच्छा प्रयास हैं, मोहभंग की इस प्रणाली में लोग अपनी परम्पराएँ, संस्कृति, सभ्यता, नैतिकता और शिष्टाचार से व्यथित हो ही गए हैं और अपनी लज्जा का गहना छोड़ परम्परा को तोड़ रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि उन्हें अपना

देश भी बेगाना लगने लगा हैं, उनका अपने देश के प्रति मोहभंग हो चुका हैं और वह अपना देश छोड़कर विदेश पलायन कर रहे हैं। इस मोहभंग की शीतलता से अपने शहर गाँव की बालाएँ भी नहीं रही हैं, वह इस चुनरी का मोहभंग कर सड़कों पर ऐसे ही घूमती नजर आती हैं। गिरीश पंकज जी ने सभ्यता की इस डोर को छोड़ चुकीं कुछ गोरियों पर ऐसे ही व्यंग्य किया हैं, किसी गोरी से पूछा जाए, आपकी चुनरी कहाँ गई? तो वह कहती हैं, वह गुलामी का प्रतीक थी, जिसे हमने निकाल फेका उससे हम बंधन में थे, चुनरी उतारने के बाद हम आजाद हैं। विदेशों में देखों कैसी आजादी हैं, वहाँ मानमाफिक संस्कृति आदान–प्रदान करते हैं, यहाँ हमने चुनरी क्या उतारी सभी कहने लगे, क्या हमें स्वतंत्र रहने का कोई हक नहीं हैं। लेखक समाज की इस यथार्थता से चिंतित होकर कहता है कि इस मोहभंग की शीत लहर में कब तक और कितना बच पांइगें हम? अब तो संस्कृति, परम्परा, सभ्यता, नैतिकता और शिष्टाचार से भी मोहभंग होने लगा हैं। चरित्र और मर्यादा की जो चुनरी कभी हमारी परम्परा थी, अब उस परम्परा से मोहभंग होने लगा हैं। लेखक ने 'चुनरी संभाल गोरी' नामक व्यंग्य के माध्यम से समाज में मोहभंग की स्थिति को उजागर किया हैं – '' आजकल मोहभंग का दौर हैं। जिधर देखो, उधर मोहभंग। बाप का बेटे से मोहभंग, बेटे का बाप से मोहभंग। पति का पत्नि से मोहभंग तो पत्नि का पति से मोहभंग। चाचा का भतीजे से तो भतीजे का चाचा से मोहभंग। अध्यापक का अध्यापन से मोहभंग तो छात्रों का अध्ययन से मोहभंग। एक ही पार्टी के नेताओं का एक–दूसरे से मोहभंग हो रहा हैं। ग्रामीणों का अपने गाँव से मोहभंग हो रहा हैं। छोटे शहर में रहने वाले का अपने शहर–कसबे से मोहभंग हो रहा हैं। अविकसित या विकासशील देश के नागरिक का अपने देश से मोहभंग हो रहा हैं। भागे जा रहे हैं विदेश। कुछ ऐसी भी आत्माएँ है, जिनका इस दुनिया से ही मोहभंग हो रहा हैं और वे 'चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना' गाती हुई पैदल की प्रस्थान कर रही हैं।''10

निष्कर्षतः कहा जा सकता हैं कि गिरीश पंकज ने समाज की समस्त विकृतियों को देखते हुए सामाजिक यथार्थता को व्यक्त करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया हैं। प्रायः व्यंग्य समाज की कमियों को उजागर करता हैं। जिससे उसकी वास्तविकता का पता चलता हैं। समकालीन समय में जिस तरह से बाजारवाद और अराजकता फैली हैं, उसे देखते हुए सामाजिक बैचेनी व्यंग्यकार महसूस करता हैं। तब उसके लेखन में कहीं न कहीं कुंठा दृष्टव्य होती हैं। इसी का प्रमाण हैं कि गिरीश पंकज ने अपनी रचनाओं में कुंठा की अभिव्यक्ति भी दी हैं। जिससे समाज की सभी विसंगतियों को उकेरकर सामने लाया जा सकें। गिरीश पंकज जी ने समाज में फैली शिक्षित बेरोजगारी, चिकित्सालयों की बदत्तर स्थिति, शिक्षा का गिरता स्तर, रिश्वतखोरी, आतंकवाद तथा नारी अस्मिता जैसे यथार्थ दृष्टिकोणों को ग्रहण करके अपने व्यंग्यों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी हैं। इनकी समस्त रचनाओं में सामाजिक यथार्थता की प्रवृत्ति दिखाई देता हैं। लेखक सामाजिक यथार्थ को व्यक्ति की पीड़ाओं, कुंठाओं आदि के माध्यम से ग्रहण करने की दिशा में प्रयत्नशील हैं।

संदर्भ सूची –

1. गिरीश पंकज, मिठलबरा की आत्मकथा पृष्ट सं. 10
2. गिरीश पंकज, मिठलबरा की आत्मकथा पृष्ट सं. 45
3. गिरीश पंकज, पालीवुड की अप्सरा पृष्ट सं. 30
4. गिरीश पंकज, ट्यूशन शरणम् गच्छामि (ग्रेजुएट पान भण्डार) पृष्ट सं. 61
5. गिरीश पंकज, ईमानदारों की तलाश (कथा तीक्ष्णदंत के अस्पताल पहुँचने की) पृ.सं. 10
6. गिरीश पंकज, ट्यूशन शरणम् गच्छामि (नन्हें मुन्ने बच्चे तेरे बस्ते में क्या हैं) पृ.सं. 16, 17
7. गिरीश पंकज, मैं खल्लास होते होते बचा, कटघरा, नई दिल्ली, जुलाई 2013
8. गिरीश पंकज, पालीवुड की अप्सरा पृ.सं. 135
9. गिरीश पंकज, हिट होने के फामूर्ले (अथश्री रिश्वत गुणगानम्) पृ.सं. 117
10. गिरीश पंकज, मंत्री को जुकाम (चुनरी सम्भाल गोरी.....) पृ.सं. 43 ।

दलितोद्धार एवं वैधानिक प्रावधान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

जितेन्द्र कुमार चौधरी, शोधार्थी नेट जेआरएफ, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)

भारत में जाति, अस्पृश्यता एवं शोषण का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही पुराना इतिहास जातिविहीन समाज का निर्माण दलितोद्धार एवं अस्पृश्यता उन्मूलन का है। ईसा से सदियों पूर्व महावीर स्वामी ने भारत में प्रचलित जाति प्रथा एवं भेदभाव का विरोध किया। महावीर का आगमन प्राचीन भारतीय चिंतन में एक क्रांतिकारी युग रहा है। उन्होने मानव की समानता, अपरिग्रह, अस्तेय एवं सम्यक क्रांति का सूत्रपात किया।[1] महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना की तथा अपने उद्देश्यों में जाति भेद एवं ऊँच–नीच का विरोध किया।

महात्मा बुद्ध की प्रथम सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों का प्रणेता कहा जा सकता है। इन्होने सर्वप्रथम जन्म पर आधारित हिन्दू जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर अस्पृश्यों को एक नये धर्म में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त किया।[2] इन्होने ईश्वर आत्मा कर्म एवं पुर्नजन्म पर आधारित हिन्दी सामाजिक दर्शन पूरी तरह से अमान्य कर दिया।[3]

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार बुद्ध धर्म ने वेदों की पवित्रता तथा उनके अपरिवर्तनीय, अपौरूषीय एवं ईश्वरीय रचना होने के दावे को चुनौती दी। बुद्ध ने वेदों के साथ–साथ उपनिषदों को भी अस्वीकार किया क्योंकि उनकी नजर में उनमें वर्णित बम्हा और आत्मा का सिद्धान्त रहस्य और अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नही है।[4] पिछड़े एवं दलितों के मार्गदाता के रूप में महात्मा बुद्ध ने धर्म के नैतिक, सामाजिक और लौकिक स्वरूप को उजागर किया। उन्होने विचार में तर्क, बुद्धि और अनुभव को महत्व दिया, वही व्यवहार में करूणा व प्रेम को स्थान दिया।[5] बुद्ध के सामाजिक दर्शन के आधार सामाजिक समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व थे। उन्होने पशुबलि प्रथा, संस्कृत भाषा एवं ब्राम्हण रूढ़िवादिता पर जमकर प्रहार किया। जिसे समाज के पीड़ित वर्ग धर्म की ओर तेजी से आकर्षित हुए।[6]

भक्ति आंदोलन और दलितोत्थान :–तेरहवी से पन्द्रहवी शताब्दी के बीच हिन्दू समाज में महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं आर्थिक बदलाव आया। इस बदलाव के फलस्वरूप समाज में मध्यम व निम्न वर्गों में से लोग कट्टरपंथी इस्लाम के आक्रमण से हिन्दू धर्म और हिन्दू संस्कृति को बचाने के लिए आगे आये। इस प्रकार तेरहवी सोलहवी शताब्दी जिसकों सामान्यतया भक्तिकाल कहा जाता है, के बीच भारत में, अनेक सन्तों का आविर्भाव हुआ। इनमें से अधिकांश सन्त मध्यम, छोटी व निम्न दलित जातियों से आये।

उत्तर भारत में कबीर (जुलाहा), नानक (छोटा व्यापारी), रैदास (चमार), धर्मदास (अछूत जाट किसान), सेना (नाई), सधना (कसाई), धन्ना (जाट), दादू (नागर ब्राम्हण) आदि अधिकांश सन्त मध्यम व निम्न जातियों में से थे। दक्षिण के प्रसिद्ध सन्त रामानुजाचार्य ग्यारहवी शताब्दी में तथा रामानंद चौदहवी शताब्दी में जन्मे थे, जो ब्राम्हण थे। बल्लभाचार्य, तुलसीदा, निम्बार्क आदि सन्त भी ब्राम्हण कुल के थे, किन्तु बल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षा लेने वाले कृष्ण भक्त संतों में कृष्णदास, कुभनदास और चतुर्भुजदास शूद्र जातियों में पैदा हुए थे।[7]

वास्तव में भक्ति आंदोलन रूढ़िवादी, धार्मिक कट्टरता, जातिभेद सम्प्रदायवाद हिन्दू एवं मुसलमानों में व्याप्त अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध आंदोलन था। इन सामाजिक एवं धार्मिक बुराईयों के विरूद्ध जो आवाज बुलंद की गई वह भजनों एवं वाणियों के माध्यम से समाज के सामने आई रोगग्रस्त समाज में भक्ति आंदोलन का विकास उस समय की परिस्थितियों की देन थी।[8]

पाश्चात्य चिंतन का प्रभाव :–भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ भारतीय समाज पश्चिम में समाज और संस्कृति के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आ गया। समय के साथ–साथ यह सम्पर्क बढ़ता गया और घनिष्ठ होता गया। यह वह समय था जब पश्चिम का समाज प्राचीन परम्पराओं के बंधन से मुक्त होकर आधुनिक युग की आधुनिकता में प्रविष्ट हो चुका था। तर्क–संगतता एवं प्रत्यक्ष अनुभव पश्चिम के चिन्तन तथा आचरण में मौलिक तत्व के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। भारत में शासक के रूप में अंग्रेज अपने साथ एक नया चिन्तन और नया सामाजिक

दृष्टिकोण लेकर आये। अंग्रेजों सम्पर्क में आने के कारण भारत के जनमानस में एक नई चेतना जागी, जिसके परिणामस्वरूप भारत में सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों के विरूद्ध एक व्यापक जागृति पैदा हुई। अंग्रेजों ने समान रूप से सभी जातियों को शिक्षा, व्यवसाय एवं सरकारी सेवा के अवसर प्रदान किये। पश्चिमी सामाजिक दर्शन जन्मजात ऊँच–नीच के भेदभाव के स्थान पर स्वतंत्रता एवं समानता पर आधारित प्रजातांत्रिक संबंधों एवं संस्थाओं के विकास का पक्षधर था।[9]

सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आन्दोलनः– दलितोद्धार एवं अस्पृश्यता उन्मूलन का दूसरा प्रमुख चरण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में सामाजिक–धार्मिक पुनर्जागरण आन्दोलन के रूप में आंरभ हुआ। इस आन्दोलन के प्रणेता स्वतंत्रता समानता एवं संसदीय प्रजातंत्र में विश्वास रखते हुए मानते थे कि ईश्वर एवं कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है।

राजा राममोहन राय (1772–1833):–आधुनिक युग में सामाजिक आन्दोलन का स्वरूप भले ही धार्मिक रहा हो, किन्तु इसकी प्रवृत्ति उदारवादी थी। राजाराम मोहन राय भारतीय इतिहास की वही कड़ी है जो उसके अतीत को वर्तमान से जोड़ती है। राजा राममोहन राय पुनर्जागरण के प्रणेता तथा आधुनिक भारत के जनक थे। उन्होने हिन्दू धर्म की कट्टरता का विरोध किया तथा धार्मिक पाखण्ड, अन्धविश्वास व कर्मकाण्ड को बुरा बताया।[10]

स्वामी दयानन्द सरस्वती (1824–1883):–स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जाति प्रथा का विरोध किया। स्वामी दयानन्द सरस्वती जाति पर आधारित सामाजिक असमानता के विरूद्ध थे। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का मूल ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' है। आर्य समाज ने मूर्ति–पूजा, कर्मकाण्ड तथा पाखण्ड लीला का विरोध कर वैदिक धर्म का पुनरूत्थान किया। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हिन्दू समाज में व्याप्त ऊँच–नीच तथा छुआछूत का खुलकर विरोध किया। आर्य समाज ने शूद्रों व दलितों को जनेऊ धारण करने, मंत्रों का उच्चारण करने और वेदों को पढ़ने की स्वतंत्रता प्रदान कर उनको सामाजिक हीनता से मुक्ति दिलाने का उल्लेखनीय कार्य किया।[10]

महादेव गोविन्द रानाडे (1842–1901):–महादेव गोविन्द रानाडे ने 1897 में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रार्थना समाज ने जाति विरोधी आन्दोलन को व्यापक तथा मजबूत बनाने का प्रयत्न किया। इस समाज में दलितों को ऊँचा उठाने के लिए उपयोगी तथा प्रशंसनीय कार्य किया।[12]

सत्य शोधक समाज और ज्योतिराव फूलेः–महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले ने 1873 में 'सत्य शोधक समाज' की स्थापना की ज्योतिबा फूले ने जातीय भेदभाव और ब्राम्हण प्रभुता को खुली चुनौती दी। उन्होने देश में सर्वप्रथम 1843 में अछूतों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। महात्मा फूले ने दलित, शोषित, पीड़ित मानवता के अज्ञान को समाप्त किया, जन्मगत विषमताओं एवं निर्योग्यताओं को दूर किया तथा विश्व का ज्ञान भंडार सबके लिए खोल दिया। उन्होने मानसिक रूप से मंद तथा आर्थिक रूप से पंगु बनाये गये समाज में क्रांति का बीज बोया। महात्मा ज्योति राव फूले ग्रामीण, कुनबी, किसानों खेतिहर, मजदूरों, शूद्राणि–अतिशूद्रों एवं नारी वर्ग सहित बहुजन समाज के दार्शनिक थे। उन्होने वर्ण व्यवस्था तथा जाति भेद के निर्माता ब्राम्हणी धर्म एवं संस्कृति के विरूद्ध शक्तिशाली आंदोलन चलाया। उन्होने शूद्रो, अस्पृश्यों किसानों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गो को हिन्दू धर्म एवं समाज व्यवस्था द्वारा थोपी गई मनसिक एवं सामाजिक दासता से मुक्त करवाकर उनको मानवाधिकार दिलाये तथा उन्हे सम्मानपूर्वक एवं गरिमापूर्ण जीवन जीना सिखाया।[13]

दक्षिण भारत में छुआछूत विरोधी आन्दोलनः–मैसूर में सामाजिक भेदभाव तथा ऊँच–नीच के विरोध में वोक्कालिंग और लिंगायत संगठित हुए इनको देखकर अछूत भी अपनी मुक्ति के लिए एकजुट हुए। मद्रास में बी.पंतलू तथा आर. वेंकटरमन ने जाति प्रथा के विरूद्ध आवाज उठाई और लोगों का ध्यान आकर्षित किया। केरल में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आन्दोलन श्रीनारायण गुरू के नेतृत्व में चलाया गया। उनका प्रमुख लक्ष्य था ''एक जाति, एक धर्म एवं एक ईश्वर का'' इसका प्रमुख लक्ष्य दलितों को आत्मिक उत्थान की दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक अग्रसर करना था।[14]

ब्राम्हण वर्चस्व के विरोध में तमिलनाडु में 'द्रविड़ आंदोलन' चलाया गया जिसका नेतृत्व रामास्वामी नायर ने

किया। उनका कहना था कि ''भारत में जब तक ईश्वर का अस्तित्व रहेगा, तब तक छुआछूत रहेगी।''[15]

अछूतानंद का पंजाब में आदि धर्म आन्दोलनः—पंजाब में जाति प्रथा के विरूद्ध 1926 में ''आदि धर्म आन्दोलन'' का सूत्रपात हुआ। इस आदि धर्म आन्दोलन की स्थापना स्वामी अछूतानंद ने की जो स्वयं निम्न जाति के थे। इस आन्दोलन के अनुसार जाति प्रथा बाहर के विजेताओं द्वारा उन पर थोपी गई व्यवस्था है। यह भारत की मूल व्यवस्था नही है। अतः इस प्रकार के आन्दोलनों ने ''जाति मल्लाह'' के नियम तथा जातिगत भेदभाव का विरोध किया।

सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंटः—अब्राम्हण आन्दोलन की चरम परिणति दक्षिण भारत के मद्रास प्रान्त में द्रविड़ आन्दोलन के रूप में दिखाई देती है, रामास्वामी नायकर ने 'सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट' चलाया और अपने अनुयाइयों से ब्राम्हण को पुरोहित रखने के स्थान पर अपनी ही जाति का पुरोहित रखने के लिए कहा।[16]

महात्मा गांधी (1869—1948):—बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में राष्ट्रीय आन्दोलन की कमान महात्मा गांधी के हाथ में आ गई। महात्मा गांधी की पहल पर 1932 में 27 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक देश में 'अस्पृश्यता निवारण सप्ताह' मनाया गया। अमृतलाल बी.ठक्कर के नेतृत्तव में 'अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग' की स्थापना हुई। इसी समय महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र 'हरिजन' का प्रकाशन शुरू किया। इस पत्र के द्वारा उन्होने अस्पृश्यता के विरोध में जनमत तैयार करने का काम किया। अस्पृश्यता विरोधी लीग का नाम आगे चलकर 'सर्वेन्टस ऑफ अनटचेबिल सोसाइटी' रखा गया जो अन्त में 'हरिजन सेवक संघ' के नाम से प्रसिद्ध हुई।[17]

डॉ. भीमराव अम्बेडकर (1891—1956):—डॉ. भीमराव अम्बेडकर दलितों में शिक्षा के प्रचार—प्रसार को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। दलितों में शिक्षा के प्रचार—प्रसार के उद्देश्य से उन्होने 1924 में 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' 1928 में, डिप्रेस्ड क्लास एज्यूकेशन सोसाइटी तथा 1944 में, 'पीपुल्स एज्यूकेशन सोसायटी की स्थापना की। डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि से शिक्षा दलितों के उद्धार का सशक्त माध्यम थी। डॉ. अम्बेडकर ने 'पीपुल्स एज्यूकेशन सोसायटी' के अन्तर्गत मुम्बई में 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज तथा 1951 में औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का विचार था कि दलित लोग तब तक न्यायपूर्ण अधिकारों की प्राप्ति और अपने हितों की रक्षा नही कर सकते जब तक कि राजनीतिक शक्ति पर उनका अधिकार नही होता, क्योंकि अपनी निर्धन स्थिति के कारण आर्थिक शक्ति पर अधिकार कर पाना उनके लिए सम्भव नही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी उल्लेखनीय संख्या के कारण ये लोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकते है। राजनीतिक शक्ति पर अधिकार हो जाने से इस वर्ग के लिए आर्थिक व सामाजिक हितों की रक्षा करना कठिन नही होगा।

दलित वर्गों में राजनीतिक जागृति लाने की दृष्टि से डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 'ऑल इण्डिया शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन' की ओर 1942 में स्थापना की। उन्होने 1927 में 'समता सैनिक दल' का गठन किया और इस संगठन के झण्डे के नीचे उन्होने दलितों को संगठिन किया।

निष्कर्षः—दलितोद्धोर हेतु विभिन्न संतों, महात्माओं द्वारा अनेक प्रयास किये गये किंतु अस्पृश्यता और दलितों की स्थिति में यथोचित सुधार संभव न हो सका। दलितों की स्थिति को सुधारने में तथा दलितों पर थोपी गई सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनैतिक निर्योग्यताओं को संवैधानिक रूप से समाप्त करने का प्रयास डॉ. भीम राव अम्बेडकर द्वारा किया गया अतः वर्तमान समय में दलितों की हितों की रक्षा हेतु विविध कानून एवं प्रावधानों के माध्यम से दलितों की स्थिति में सुधार संभव हुआ अस्पृश्यता का पूर्णतः अंत हुआ तथा दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ सामाजिक एवं धार्मिक नियोग्यताएं समाप्त हुई। नौकरियों एवं शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण के माध्यम से दलितों की स्थिति में यथोचित सुधार संभव हुआ।

संदर्भ–ग्रंथ सूची –

1. रोमिला थापर, (1996); भारत का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 42
2. पूरणमल, (1999), अस्पृश्यता एवं दलित चेतना, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, पृ. 43
3. बी.आर. अम्बेडकर, (1973) भगवान बुंद्ध और उनका धर्म, भंदत आनंद कौसल्यायन (अनु.), सिद्धार्थ प्रकाशन, मुम्बई, पृ. 193
4. जी.एस. लोखंडे, (1982), भीमराव रामजी अम्बेडकर,: ए क्रिटीकल स्टडी इन सोशल डेमोक्रेसी, इन्टेलुक्चुअल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ. 283–284
5. वही, पृ. 241
6. रोमिला थापर, वही पृ. 45
7. वी.एन. सिंह, एवं जनमेजय सिंह, (2007) भारत में सामाजिक आंदोलन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ. 203
8. रामगोपाल सिंह; भारतीय दलितों की समस्याएँ एवं उनका समाधान, (1986), हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल मध्यप्रदेश, पृ. 76
9. वी.एन. सिंह एवं जनमेजय सिंह, वही. पृ. 54
10. के.एम. पणिक्कर, (1986), द फाउंडेशन ऑफ इंडिया, दिल्ली, विवेक प्रकाशन, पृ. 29–30
11. डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर सम्पूर्ण वांगमय, खण्ड–1, नई दिल्ली, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत सरकार 1993, पृ. 260–261
12. धनंजय कीर, (1974), महात्मा ज्योतिराव फूलेः फादर ऑफ इंडियन सोशन रिवॉलयूशन, पापुलर प्रकाशन, मुम्बई, पृ. 125
13. वी.टी. सेम्यूल, (1977) वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड–ए स्टडी ऑफ श्री नारायण गुरू, स्टर्लिंग पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 10
14. वी.एन. सिंह एवं जनमेजय सिंह, वही, पृ. 216
15. रामगोपाल सिंह, वही. पृ. 99
16. वही, पृ. 78
17. नानकचंद रत्तू, (2005), डॉ. अम्बेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, नई दिल्ली, सम्यक प्रकाशन, पृ. 78

'विभिन्न बौद्धिक स्तर के किशोर छात्र एवं छात्राओं के सृजनात्मक चिंतन क्षमता में लिंग भिन्नताओं का अध्ययन''

श्रीमती डिम्पल वर्मा, अतिथि व्याख्याता शिक्षा विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर

शोध सार –

प्रस्तुत शोध कार्य का उद्देश्य विभिन्न बौद्धिक स्तर की किशोर छात्र एवं छात्राओं के सृजनात्मक चिंतन क्षमता के कारक धाराप्रवाहशीलता/लचीलापन एवं मौलिकता में लिंग भिन्नताओं का अध्ययन किया गया। अध्ययन में जबलपुर (म.प्र.) शहर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से नवमी कक्षा के 400 विद्यार्थियों (200 छात्र एवं 200 छात्राओं) को न्यादर्श स्वरूप लिया गया। अध्ययन में शाब्दिक बुद्धि परीक्षण–डॉ. पी. श्रीनिवासन एवं सृजनात्मक चिंतन क्षमता शाब्दिक परीक्षण – डॉ. बॉकर मेहदी का उपयोग किया गया। शोध परिणामों में सृजनात्मक चिंतन क्षमता के कारकों एवं बुद्धि के संदर्भ में लिंग भिन्नतायें पाई गई।

प्रस्तावना–

प्रागैतिहासिक काल से आज तक मानव सभ्यता का विकास और उत्थान केवल ज्ञान की खोज और अविष्कारों का ही परिणाम है। ये सभी अविष्कार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मानव कुशलता और सृजनात्मक क्षमता से जुड़ी है। सृजनात्मकता मनोवैज्ञानिक रचना है जो सभी व्यक्तियों में कम या ज्यादा हो सकती है, जिसको अच्छी शिक्षा और योजना के द्वारा उभारा जा सकता है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत जैसा विकासशील देश एक विकसित राष्ट्र होने की दशा में अग्रसर है, वहाँ किशोरों की बुद्धि एवं सृजनात्मक चिंतन क्षमता के साथ संबंध देखा जाये जिससे देश को सही दिशा प्राप्त हो सके। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें अच्छे वातावरण, उपयुक्त एवं पर्याप्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा किशोरों को वांछित दिशा प्रदान की जा सकती है। ऐसे में बुद्धि एवं सृजनात्मक चिंतन क्षमता में लिंग भिन्नताओं का अध्ययन करना अतिआवश्यक होगा। बुद्धि एवं सृजनात्मक चिंतन क्षमता में लिंग भिन्नताओं का अध्ययन कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। त्रिवेदी कुंजन एवं भार्गव रिचा (2010) ने अपने अध्ययन में उच्च एवं निम्न उपलब्धि समूहों की सृजनात्मकता में लिंग भिन्नतायें पाई है। बार्ट विलियम एम. एवं अन्य (2015) ने अपने अध्ययन में भी लिंग भिन्नतायें पाई है। घोश मित्रा स्मृतिकाना डॉ. (2013) ने सृजनात्मक परीक्षण के विभिन्न आयामों के मध्य भी लिंग भिन्नतायें पाई है। अतः मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किशोरों की बौद्धिक क्षमता एवं सृजनात्मकता चिंतन क्षमता में लिंग भिन्नताओं का अध्ययन कर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाये, जिससे भविष्य में विकास के क्षेत्र में लिंग भिन्नताओं के कारण कोई रूकावटे न आये।

न्यादर्श :–'नवमी कक्षा में अध्ययनरत 14–16 वर्ष के विद्यार्थी''

तालिका क्र.1

न्यादर्श तालिका

समूह	संख्या
छात्र	200
छात्रायें	200
कुल योग	**400**

उपकरण :–

प्रस्तुतशोध कार्य में निम्नांकित परीक्षणों का उपयोग किया गया –

1. शाब्दिक बुद्धि परीक्षण– डॉ.पी.श्रीनिवासन

2. सृजनात्मक चिंतन क्षमता शाब्दिक परीक्षण – डॉ. बॉकर मेहदी।

विधि :–

न्यादर्श में चयनित विद्यार्थियों पर ''शाब्दिक बुद्धि परीक्षण–डॉ.पी. श्रीनिवासन'' का प्रयोग किया गया। फलांकन के उपरांत छात्र एवं छात्राओं को उच्च एवं निम्न बौद्धिक स्तर में वर्गीकृत किया गया। इन चुने हुये छात्र–छात्राओं पर सृजनात्मक चिंतन क्षमता शाब्दिक– डॉ. बॉकर मेहदी परीक्षण का प्रशासन एवं फलांकन किया गया।

परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या :–

परिणामों को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है –

तालिका क्र.02

उच्च एवं निम्न बौद्धिक स्तर के छात्र–छात्राओं के सृजनात्मक चिंतन क्षमता के कारकों में अंतर संबंधी परिणाम

कारक (सृजनात्मकता)	बौद्धिक स्तर	समूह	N	Mean	SD	F- अनुपात	'पी' मान
धाराप्रवाहशीलता	उच्च	छात्र	85	29.20	8.57	16.55	<0.01
		छात्रायें	65	29.52	8.99		
	निम्न	छात्र	73	21.60	8.97		
		छात्रायें	77	23.17	7.94		
लचीलापन	उच्च	छात्र	85	24.06	6.48	15.55	<0.01
		छात्रायें	65	23.15	6.42		
	निम्न	छात्र	73	17.34	7.16		
		छात्रायें	77	20.18	6.82		
मौलिकता	उच्च	छात्र	85	22.29	10.17	12.31	<0.01
		छात्रायें	65	22.14	10.30		
	निम्न	छात्र	73	14.26	8.60		
		छात्रायें	77	17.51	9.06		

व्याख्या :–

प्रस्तुत शोध कार्य में विभिन्न बौद्धिक स्तर के किशोर छात्र एवं छात्राओं के सृजनात्मक चिंतन क्षमता के कारक धाराप्रवाहशीलता/लचीलापन एवं मौलिकता में लिंग भिन्नताओं का अध्ययन किया गया।

प्राप्त परिणामों में (तालिका क्र. 02) सृजनात्मकता के तीनों कारकों में Fअनुपात सार्थक प्राप्त हुआ हैं। धारा प्रवाहशीलता एवं मौलिकता में छात्रों से उच्च बौद्धिक स्तर छात्राओं का अधिक आया है तथा लचीलापन में छात्राओं के अपेक्षा छात्रों का बौद्धिक स्तर अधिक आया है। निम्न बौद्धिक स्तर में सृजनात्मकता के कारकों धारा प्रवाहशीलता एवं लचीलापन में छात्रों ने छात्राओं से अधिक अंक प्राप्त किये हैं तथा मौलिकता में निम्न बौद्धिक स्तर में छात्राओं ने छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किये हैं। सृजनात्मकता एवं बुद्धि में धनात्मक सहसंबंध होता है, व्यक्ति अपने ही तरीके से सोचता है और किसी जानकारी को व्यक्तिगत तरीके से प्रक्रिया में लाता है। उपरोक्त शोध परिणामों से यह स्पष्ट होता है एवं लिंग भेद भी यहॉ प्रदर्शित होता है। कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बुद्धि एवं सृजनात्मक चिंतन क्षमता में लिंग भिन्नताओं को पाया गया हैं – त्रिवेदी कुंजन एवं भार्गव रिचा (2010) ने अपने अध्ययन में उच्च एवं निम्न उपलब्धि समूहों की सृजनात्मकता में लिंग भिन्नतायें पाई। इसी प्रकार बार्ट विलियम एम एवं अन्य (2015) तथा घोश मित्रा स्मृतिकाना डॉ. (2013) ने भी अपने अध्ययनों में लिंग भिन्नतायें पाई। सामाजिक स्तर को उच्च करने एवं राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिये व्यक्ति में बौद्धिक स्तर एवं सृजनात्मक चिंतन क्षमता में लिंग भेद समाप्त करने के प्रयास किये जाने चाहिये। अतः यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इन संबंधों का अध्ययन करके विद्यार्थियों को उचित दिशा निर्देश प्रदान किये जाये।

निष्कर्ष :–प्रस्तुत शोध के परिणामों से ज्ञात निष्कर्ष इस प्रकार से है –

1. सृजनात्मक चिंतन क्षमता के कारक धारा प्रवाहशीलता में बुद्धि के संदर्भ में लिंग भिन्नतायें हैं।

2. सृजनात्मक चिंतन क्षमता के कारक लचीलापन में बुद्धि के संदर्भ में लिंग भिन्नतायें हैं।

3. सृजनात्मक चिंतन क्षमता के कारक मौलिकता में बुद्धि के संदर्भ में लिंग भिन्नतायें हैं।

इस प्रकार प्राप्त परिणामों में बुद्धि एवं सृजनात्मकता के संदर्भ में लिंग भिन्नतायें पाई गई।

संदर्भ :–

अस्थाना, विपिन (1999). मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, नवीनतम संस्करण, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर, पृष्ठ संख्या 276–279

Guilford, J.P. (1950). "Creativity", The American Psychologist, Vol.9, pp 444-45.

मित्तल, संतोष; (1995), शैक्षिक तकनीकी, प्रथम संस्करण, जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पृष्ठ क्र. 56

पाण्डेय, गणेश/पाण्डेय, अरूणा (2005). शोध प्रविधि,प्रथम संस्करण, नई दिल्ली : राधा पब्लिकेशन, पृष्ठ संख्या 124–128

Palanippan, A.K.(2005).Creativity and Academic Achievement, A Malasysian Perspective, Shah Alam: KarisPub.

शर्मा आर.ए. (2003). शिक्षा अनुसंधान, नवीनतम संस्करण, मेरठ : सूर्या पब्लिकेशन, पृष्ठ क्र. 70, 94, 120

वर्मा, प्रीति एवं श्रीवास्तव, डी.एन. (2008), आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सोलहवॉं संस्करण, आगरा : अग्रवाल प्रकाशन

भारत में नागवंश का विस्तारः एक अध्ययन

कन्हैया लाल धुर्वे, सहायक प्राध्यापक (इतिहास), शासकीय निवास महाविद्यालय, मण्डला, म.प्र.

सारांशः—नागवंश भारत के प्राचीन राजवंशों में माना जाता है, जिनमें नाग जाति के लोग रहा करते थे। नागवंश का विस्तार भारत के कई हिस्सों तथा फिजी एवं मैक्सिको आदि देशों में भी फैला हुआ था। महाभारत काल में पूरे भारत वर्ष में नाग जातियों के समूह फैले हुए थे। विशेष तौर पर कैलाश पर्वत से सटे हुए इलाकों से असम, मणिपुर, नागालैंड तक इनका प्रभुत्व था। कुछ विद्वान मानते है कि शक या नाग जाति हिमालय के उस पार की थी। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा था जबकि नाग समुदाय पूरे भारत (पाक–बांग्लादेश सहित) के शासक थे। उस दौरान उन्होंने भारत के बाहर भी कई स्थानों पर अपनी विजय पताकांए फहराई थीं। तक्षक, तनक और तश्त नागाओं के राजवंशों की लम्बी परम्परा रही है। संपूर्ण भारत में नागवंश के लोग फैले हुए थे वे सारी जातियों और वर्णों में विद्मान थे वे अनुसूचित जाति और जनजाति में मौजूद है। नाग, जल, पर्वत, पाताल, अर्थात् संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजाति समूह था।

प्रस्तावनाः— प्राचीनकाल में नागवंशियों का राज्य भारत में कई स्थानों में तथा सिंहल में भी था। पुराणों में स्पष्ट लिखा है, कि सात नागवंशी राजा मथुरा भोग करेंगे, उसके पीछे गुप्त राजाओं का राज्य होगा। नौ नाग राजाओं के जो पुराने सिक्के मिले हैं, उन पर 'बृहस्पति नाग', 'देवनाग', 'गणपति नाग' इत्यादि नाम मिलते हैं। ये नागगण विक्रम संवत 150 से 250 के बीच राज्य करते थे। इन नव नागों की राजधानी कहाँ थी, इसका ठीक पता नहीं है, फिर अधिकांश विद्वानों का मत यही है कि उनकी राजधानी 'नरवर' थी। मथुरा और भरतपुर से लेकर ग्वालियर और उज्जैन तक का भू–भाग नागवंशियों के अधिकार में था।

पुराण उल्लेखः— प्राचीनकाल से ही भारत में नागों की पूजा की परंपरा रही है। माना जाता है कि 3000 ईसा पूर्व आर्य काल में भारत में नागवंशियों के कबीले रहा करते थे, जो सर्प की पूजा रकते थे। उनके देवता सर्प थे। यही कारण था कि प्रमुख नागवंशों के नाम पर ही जमीन पर रेंगने वाले नागों के नाम पड़े थे। पुराणों के अनुसार कश्मीर में कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू से उन्हें आठ पुत्र मिले थे, जिनके नाम क्रमशः इस

प्रकार थे– अनंत (शेषनाग), वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक।

कश्मीर का अनंतनाग इलाका अनंतनाग समुदायों का गढ़ था। उसी तरह कश्मीर के बहुत सारे अन्य इलाके भी कद्रु के दूसरे पुत्रों के अधीन थे। कुछ अन्य पुराणों के अनुसार नागों के प्रमुख पाँच कुल थे– अनंत, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक और पिंगलां जबकि कुछ और पुराणों ने नागों के अष्टकुल बतायें हैं– वासुकी, तक्षक, कुलक, कर्कोटक, पद्म, शंख, चूड़, महापद्म और धनंजय। अग्निपुराण में 80 प्रकार के नाग कुलो का वर्णन है, जिसमें वासुकी, तक्षक, पद्म, महापद्म आदि हैं। नागों का पृथक नागलोक पुराणों में बताया गया है। अनादिकाल से ही नागों का अस्तित्व देवी–देवताओं के साथ वर्णित है। जैन, बौद्ध, देवताओं के सिर पर भी शेष छत्र होता है। असम, नागालैंड, मणिपुर, केरल और आंध्र प्रदेश में नागा जातियों का वर्चस्व रहा है। भारत में इन आठ कुलों का ही क्रमशः विस्तार हुआ, जिनके नागवंशी रहे थे– नल, कवर्धा, फणि–नाग, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदि, शिशुनंदि या यशनंदि तनक, तुश्त, ऐरावत, धृतराष्ट्र, अहि, मणिभद्र, अपापत्र, कम्बल, अंशतर, धनंजय, कालिया, सौंफू, दौद्धिया, काली, तखतू, धूमल, फाहल, काना, गुलिका, सरकोटा इत्यादि।

अध्ययन के उद्देश्यः—कुषाण शक्ति को खास धक्का नाग सम्राटों के हाथों लगा था। पर साथ ही यह बात भी प्रायः निश्चित ही है कि इन बड़े–बड़े प्रजातंत्रों का एक संघ था और इसलिए नागों को अपने इन युद्धों में इन प्रजातंत्री समाजों से भी अवश्य ही सहायता मिलती रही होगी।[6] हम कह सकते हैं कि नाग साम्राज्य एक प्रजातंत्री साम्राज्य था। जान पड़ता है कि मगध में 'कोट' राजवंश

का उत्थान भी इन्हीं नागों की अधीनता से हुआ था। गुप्त राजवंश की जड़ भी नागकाल में ही जमी थी। पुराणों में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। यहाँ यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि नाग लोग भी उत्तर से ही चलकर आये थे और पूर्व में आकर बस गए थे। मगध के कोट और प्रयाग के गुप्त भी संभवतः नाग साम्राज्य के अधीनस्थ और अन्तर्गत् ही थे। वायु और ब्राह्मण पुराण में इस बात का उल्लेख है कि बिहार में नवनागों की राजधानी चंपावती थी। नागों ने अपना राज्य विस्तार मध्यप्रदेश तक कर लिया था और इस बात का प्रमाण परवर्ती वाकाटक इतिहास से और नागवर्द्धन तथा नागपुर आदि स्थानों के नामों से मिलता है।[2] विन्ध्य पर्वतों के ठीक मध्य में पुरिका में भी उनकी एक राजधानी थी और वही मानों मालवा जाने के लिए प्रवेश द्वार था। हम यह मान सकते हैं कि मोटे तौर पर बिहार, आगरा, और अवध के संयुक्त प्रदेश बुंदेलखण्ड, मध्यप्रदेश, मालवा, राजपूताना और पूर्वी पंजाब का मद्र प्रजातंत्र सभी भारशिवों के साम्राज्य के अर्न्तगत् थे। कुषाणों ने भारशिव काल के ठीक मध्य में अर्थात् सन 226–241 ई0 में अर्द्धशिर की अधीनता स्वीकार की थी और सन् 238 से 269 ई0 के बीच में उन्होंने अपने सिक्कों पर शापुर की मूर्ति को स्थान दिया था। यह भारशिवों के दबाव का ही परिणाम था। इस प्रकार भारशिवों के दस अश्वमेध कोरे यज्ञ ही नहीं थे।[3]

अन्य तथ्य:–कृष्णकाल में नागजाति ब्रज में आकर बस गई थी। इस जाति की अपनी एक पृथकसंस्कृति थी। कालिया नाग को संघर्ष में पराजित करके श्रीकृष्ण ने उसे ब्रज से निर्वासित कर दिया था, किंतु नाग जाति यहाँ प्रमुख रूप से बसी रही। मथुरा पर उन्होंने काफ़ी समय तक शासन भी किया।

- नागसेन आदिनाग नरेश ब्रज के इतिहास में उल्लेखनीय रहे, जिन्हें गुप्त वंश के शासकों ने पराजित किया था। नाग देवताओं के अनेक मंदिर आज भी ब्रज में विद्यमान है।
- इतिहास में यह बात प्रसिद्ध है कि महाप्रतापी गुप्तवंशी राजाओं ने शक या नागवंशियों को परास्त किया था। प्रयाग के किले के भीतर जो स्तंभलेख है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि महाराज समुद्रगुप्त ने गणपति नाग को पराजित किया था। इस गणपति नाग के सिक्के बहुत मिलते हैं।
- महाभारत में भी कई स्थानों पर नागों का उल्लेख है। पांडवों ने नागों के हाथ से मगधराज्य छीना था। खांडव वन जलाते समय भी बहुत से नाग नष्ट हुए थे।
- जनमेजय के सर्प–यज्ञ का भी यही अभिप्राय मालूम होता है कि पुरूवंशी आर्य राजाओं से नागवंशी राजाओं का विरोध था। इस बात का समर्थन सिंकदर के समय से प्राप्त वृत्त से होता है। जिस समय सिंकदर भारत में आया, तब उससे पहले तक्षशिला का नागवंशी राजा ही मिला था। उस राजा ने सिकंदर का कई दिनों तक तक्षशिला में आतिथ्य किया और अपने शत्रु पौरव राजा के विरूद्ध चढ़ाई करने में सहायता पहुँचाई। सिकंदर के साथियों ने तक्षशिला में राजा के यहाँ भारी–भारी साँप पले थे, जिनकी नित्य पूजा होती थी। यह शक या नाग जाति हिमालय के उस पार की थी। अब तक तिब्बती भी अपनी भाषा को 'नागभाषा' कहते हैं।

निष्कर्ष:–प्राचीन साहित्य के इन सूत्रों से स्पष्ट होता है कि गंगा के दक्षिणी तट से लेकर समुद्र तट तक नाग जाति का क्षेत्र विस्तार था। यह आर्य जाति की ही एक शाखा थी जो आपसी संघर्षो के कारण दक्षिणारण्य में जा बसी थी। रामायण काल का दण्डकारण्य इसी दक्षिणारण्य का एक भाग था, जिसे महाकान्तार भी कहा जाता था।[4]

ज्ञातव्य है कि आर्य जाति ही संसार की प्रथम कृषक जाति थी जो मध्य एशिया से आकर सप्त सिन्धु प्रदेश में बस गई थी। इस समय नाग जाति आर्य जाति के साथ ही साथ सिन्धु प्रदेश में बसती थी। सिन्धु घाटी की सभ्यता में मिले नाग जाति के अवशेष, नागशिव की मूर्ति आदि इस तथ्य को प्रमाणित करते है।[5]

दक्षिणारण्य में नागों, पर्वत, हाथी, खनिज पदार्थ तथा नाग जाति आदि की प्रधानता थी। आज भी प्राचीन दक्षिणारण्य के उत्तर पूर्वी भाग को झारखण्ड या नागपुर कहा जाता है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक दक्षिणारण्य के उत्तर पूर्वी भाग को विविध नामों से अभिहित किया जाता रहा है। मगध, ब्रत्य प्रदेश, कीकट प्रदेश, पुण्ड्र, पौण्डरिक देश, अर्क खण्ड, कर्क खण्ड,

नागपुर, झारखण्ड कोकराह, खुखरा, हीरानागपुर, चुटियानागपुर अथवा छोटानागपुर आदि इनमें प्रमुख हैं। मुगलकाल में यह प्रदेश हीरे के लिए प्रसिद्ध था जिसके कारण इसे हीरानागपुर कहा जाता था। यहाँ के पौराणिक मुण्डारी, उरांव आदि लोकगीतों में इसे हीरानगर कहा गया है।

कालान्तर में मध्यवर्ती आरण्य प्रदेश या झारखण्ड, राजनैतिक आदि कई कारणों से कई खण्डों और उपखण्डों में विभाजित होता चला गया। प्राचीन तथा मध्य केकीकट, अंग, बंग, मगध, मिथिला, कलिंग, विंध्य, पांचाल तथा आधुनिक बड़ा नागपुर, चुटियानागपुर जो छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है आदि इन्हीं खण्डों के विभिन्न रूप हैं।[6]

संदर्भ–

- विमलेश्वरी सिंह, नागवंश
- डॉ0 डी0पी0 दुबे, उपाचार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा साक्षात्कार से प्राप्त जानकारी
- श्री डी.एस. नाग, न्यूस्मैटिक सोसायटी, ऑफ इण्डिया नर्जल, 1973, में लेख, दि ओरिजिन एण्ड डेव्हलेपमेण्ट ऑफ मालवा डायनेस्टीज विद द बेसिस ऑफ क्वायन्स
- विमलेश्वरी सिंह – नागवंश, पृ. 44
- विमलेश्वरी सिंह – नागवंश, पृ. 44
- डॉ0 अवन्तिका प्रसाद मरमट – नाग संस्कृति, उज्जैन 2000

Relationship between Foreign Direct Investment Inflows and Exports in India

Namrata Shrivastava

It has long been argued that Foreign Direct Investment (FDI) plays an important role in promoting export and economic growth of an economy. It is argued that Foreign Direct Investment promotes exports of the host countries by increasing the productivity and productive capacity of the host country by increasing capital stock, transfer of technology, managerial skills and upgrading the skills of the local workforce through training. However, the role of Foreign Direct Investment in promoting export is a controversial topic and basically depends upon the motive for such investment. If the motive for Foreign Direct Investment is to bypass the trade barriers (high tariff) of the host countries, to gain access to large overseas market and to reap the benefits of economies of scale, this may not promote export. Such kind of market seeking investment is called horizontal Foreign Direct Investment. However, if the motive for Foreign Direct Investment is to reap the benefits of host country's comparative advantage so as to produce at relatively low cost, such investments are likely to promote trade and hence complement trade. Such Foreign Direct

Investment is called export oriented or vertical Foreign Direct Investment.

India has also witnessed growth of Foreign Direct Investment inflow since the eighties and particularly since the nineties with the liberalization of the economy. This period has also witnessed rapid growth of exports. However, despite these, there has not been much study on the relationship between Foreign Direct Investment inflows and exports and economic growth. **Kishor Sharma (2000)** study covers only few years of the reform period i.e. up to 1997. In order to fill this gap, the present paper tries to examine the relationship between Foreign Direct Investment inflows and exports.

Foreign Direct Investment plays an important role in promoting exports of host countries. It promotes exports by facilitating the host countries access to customers in global, regional and home-country markets. In addition, host countries sometimes also get benefits of lobbying activities of the MNCs in their home countries for favorable treatment of exports from their affiliates abroad as happened in case of US, China etc.

Foreign Direct Investment also helps in improving productivity of labour force by providing training to the local workforce and upgrading technical and managerial skills. These activities benefit the country's exports through improvement in productivity of the labor force. This is especially true for export-oriented investments in advanced technological capabilities.

Foreign Direct Investment has both direct and indirect effect on host country's exports. The direct effects refer to exports by foreign affiliates themselves. The indirect effect includes spillover effect of MNCs on local firms' export activities (**UNCTAD, 2002**).

The export of a country is directly affected by foreign direct Investment in following ways:

(a) Exports through processing and assembling: Many of the developing countries increase its exports of labour intensive and technology intensive products by assembling and processing of intermediate and unfinished products imported from home country. Generally, these exports are organized by MNCs within vertically integrated

international production network (**Zhang and Markusen, 1999**).

(b) Exports of new labor-intensive final products: By providing links to final buyers in different countries including the home country, Foreign Direct Investment helps in increasing exports of labour and technology intensive final products of the host countries (**Zhang,2005**).

(c) Exports of locally processed raw materials: Because of the business contacts abroad, marketing skills, and superior technology, both in product and in processes, and greater general know-how, MNCs may have better export potential than indigenous firms in the processing of locally produced raw materials and exporting the same. This is especially true in the early stage of development when the country lacked the assets. (**Zhang, 2005**)

Foreign Direct Investment also enhances the developing countries (host country's) manufacturing exports through spillover effects on local firms' exporting activities. (**Zhang (2005**)

(a) Learning and imitating of domestic firms from foreign firms: Local firms benefit themselves by watching, learning and imitating the export activities of the foreign affiliates and by making use of the infrastructure of transport, communications and financial activities.

(b) Instilling competition and efficiency: The second spillover effect involves the influence of Foreign Direct Investment on the competitiveness of domestic firm's exports and the diffusion of new technologies. By bringing their advanced product-process technology, management, and marketing competence, MNCs may increase competition in the markets and force local firms to adopt more efficient methods.

(c) Linkage between foreign and local firms: The third spillovers are related to the linkage between foreign and local firms. If export-oriented foreign subsidiaries increase their purchase of inputs from local firms as the subsidiary matures, the exports of the country increases (**UNCTAD, 2001 and 2002**).

The relationship between Foreign Direct Investment inflows and exports has been examined by the theories of international trade and Foreign Direct Investment. Two divergent views have come up to establish the relationship between Foreign Direct Investment and international trade. One regards Foreign Direct Investment and exports as substitutes of each other; and the other treats the two as complements. **R. Mundell (1957)** on the base of H-O-S (Heckscher-Ohlin-Samuelson) model (two countries, two products and two factors) model demonstrated that the difference in comparative advantage is the basis of trade. In the absence of factor mobility, trade between two countries takes place to a level at which factor price tends to equalize in both countries, in absolute as well as in relative terms. However, once capital is allowed to move freely across the countries, i.e., from the abundant to a country where it is scarce, the difference in factor prices are reduced, the difference in comparative cost will diminish and eventually will vanish. Hence trade will decline and will be substituted completely by Foreign Direct Investment. This view assumes that Foreign Direct Investment comes only in those sectors in which the host country has comparative disadvantage. Such Foreign Direct Investments come only to supply domestic market of host countries and hence plays no role in increasing exports. So Foreign Direct Investment replace imports with domestic production.

The conclusion that both trade in goods and factors work as substitutes is derived from the H-O factor endowment theory based on allocative efficiency in a static framework characterized with perfectly competitive markets, identical constant returns to scale production function and in the absence of transportation cost. However, the generality of this proposition has been questioned in an imperfectly competitive international market,

based on economies of scale, imperfect competition, and differences in technological changes that explains the possibility of intra-industry trade (**Grossman and Helpman, 1991; Krugman, 1979**) and is compatible to explain vertical Foreign Direct Investment (intra-firm transfers).

Vernon (1966) in its Product Life Cycle (PLC) theory also explained a positive role of Foreign Direct Investment in promoting exports from host countries. He argued that technology passes through four stages of production. Theses stages are innovation, growth, maturity and decline. In the third stage of maturity, innovating firms, in order to reduce cost and protect them from imitating competitors, start production in foreign countries and export a part of production to home country. In the last phase, product and technology becomes mature and standardized, and becomes accessible to local imitators that thanks to the low labour cost become international competitors. This leads to increase in export of the host countries. In this case flow of trade may be reversed. The original innovating may relocate production further into host countries and reimport the product to the home country. Applying Vernon model at industry level, **Kojima (1973, 1985)** found when Foreign Direct Investment is made in the sector in which the country of origin has comparative disadvantage and the host country has comparative advantage, then this kind of investment has trade creating effect implying that the host country's export will increase.

According to New Trade Theory, the separation of different stages of production in different countries (vertical Foreign Direct Investment) would most likely to cause trade creation effect. **Helpman (1984)** and **Helpman and Krugman (1985)**, assuming no transaction cost, argues if choice of location of production facilities is based on relative factor prices and resource endowments, then, vertical Foreign Direct Investment would cause trade creation effect in the form of export of finished product from affiliate company to parent company and intra firm transfer of intangible services from parent company to affiliate company. **Brainard (1993)**, on the ground of proximity advantage, also postulated a positive relationship between Foreign Direct Investment and trade. Just as the there are differences of opinion about the relationship between the Foreign Direct Investment inflow and amount of exports, the empirical studies also provide mixed results for different countries.

Khan and Leng (1997) while examining the interactions among inward – Foreign Direct Investment, exports and economic growth for Singapore, Taiwan and South Korea, did not find any evidence of causal relation between Foreign Direct Investment and export in the case of Taiwan and South Korea. In the case of Singapore, a one – way causal relationship from exports to inward Foreign Direct Investment was found. **Liu et al (2002)** investigated the causal relationship between inward Foreign Direct Investment, trade and economic growth in China using quarterly data at aggregate level for the period 1981 to 1997 and found two – way causal relationship between inward Foreign Direct Investment and exports. Similar result was also found by **Baliamoune – Lutz (2004)** for Morocco for the period 1973 to 1999.

Soliman, M. (2003) examined the role of Foreign Direct Investment in export promotion of four MENA countries (Egypt, Tunisia, Morocco and Turkey) for the period of 1970-1995. Applying gravity model, he found a positive relationship between Foreign Direct Investment inflow and export; however, an insignificant relationship has been found in the case Foreign Direct Investment and share of manufacturing export in total merchandise exports. **Metwally (2004)** tests the relationship between Foreign Direct Investment, exports and economic growth in three countries, viz., Egypt, Jordan and Omen, during the period from 1981 to 2000 by using a simultaneous

equation model. The result suggests that the export of goods and services is strongly influenced by the inward Foreign Direct Investment in these three countries.

Pacheco – Lopez (2005) demonstrated the causal relationship between inward Foreign Direct Investment and Export performance on Mexico by using the Granger causality test. The result indicates that there is a bi – directional causality between inward Foreign Direct Investment and export performance. **A.M.M. Abdel Rahman (2007)** using causality test found that Foreign Direct Investment does not Granger cause export growth in Kingdom of Saudi Arabia but export growth Granger cause Foreign Direct Investment growth. **Alici and Ucal (2003)** investigated the causal links among inward Foreign Direct Investment, exports and economic growth in Turkish economy during the period of 1987 to 2002 on a quarter bases. The linkage of Foreign Direct Investment – led export growth is not found in Turkey.

The empirical studies done so far in the case of India however do not show any significant impact of Foreign Direct Investment in promoting India's exports. For example, **Lall and Mohammad (1983)** found that Foreign Direct Investment inflows have not played any significant role in promoting export from India. Similarly, firm level analysis of the determinants of exports by **Aggarwal (2001)** found no significant contribution of Foreign Direct Investment inflows as compared to the domestic counterpart on export performance of high tech industries in India during the 1990s. **Kishor Sharma (2000)**, applying simultaneous equation model on annual data for the period 1970-1998, found no significant contribution of Foreign Direct Investment inflow on export performance of India. There are other studies (**Pant 1993, Lall 1986, Kumar and Siddharthan 1994, Agarwal 1997, Kumar 1998**) also that did not find any significant role played by Foreign Direct Investment in India's export growth. All these studies show that Foreign Direct Investments in India are mainly market seeking and not export oriented in nature.

A.M. Njong (2008) examined the association between Foreign Direct Investment and export in the case of Cameroon. Using the data for the period 1980-2003, he found positive impact of Foreign Direct Investment on export through increase in supply capacity and spillover effects. **Won et al (2008)**, using panel data Granger causality test for nine Asian newly industrialized countries, found bi directional causality between inward Foreign Direct Investment and export growth.

K.H. Zhang (2005) on the basis of cross section studies of 186 industries concluded a positive relationship between FDI and export growth in China and this effect is larger in labour intensive industries than that in capital intensive industries. Further, he also found that the Foreign Direct Investment has more export promoting effect than that of domestic capital.

Sultan (2013) has studied Causal Relationship between Foreign Direct Investment Inflows and Exportsin India.Foreign Direct Investment (Foreign Direct Investment) is considered as an important means of promoting export of the host countries. By training the local work force and upgrading the technical and managerial skills, it helps in raising the efficiency and productivity of the factors and hence competitive strength in the international market. In addition to this, by facilitating access to large international market, Foreign Direct Investment makes a significant positive contribution to the host country's exports. However this is true if Foreign Direct Investment comes for efficiency reason and not for domestic market. The present study examines the nature of relationship between export and Foreign Direct Investment in India over the period 1980-2010. Using Johansen co-integration method, the study finds a stable long run

equilibrium relationship between Foreign Direct Investment and export growth. The result of Granger causality based on vector error correction model (VECM) shows that causality runs from export to Foreign Direct Investment inflow direction and not from Foreign Direct Investment inflow to export direction. In the short run, however, neither export Granger cause Foreign Direct Investment inflow nor Foreign Direct Investment inflow Granger cause export from India.

India has also witnessed growth of Foreign Direct Investment inflow since the eighties and particularly since the nineties with the liberalization of the economy. This period has also witnessed rapid growth of exports. However, despite these, there has not been much study on the relationship between Foreign Direct Investment, export and economic growth. In order to fill this gap, the present study tries to examine the relationship between Foreign Direct Investment inflows and exports. Most of these studies, however, cover only a short span of post reform era. Present study, therefore, will try to re examine the role of Foreign Direct Investment in promoting India's export by covering a relatively longer period of post reform era.

Foreign Direct Investment, as said earlier, increases the supply capacity of the country through increase in the factor supply of the country in the form of more amount of capital. Further, it also increases the competitiveness of the country's exports by increasing total factor productivity. However, the actual increase in exports would also depend upon the intention of the investors and the allocation of Foreign Direct Investment, whether to exploit the comparative advantage of the host country or take the advantage of the host country's local market. If the intention of the Foreign Direct Investment is to benefit from comparative advantage of the country, then we may expect a positive relationship between Foreign Direct Investment inflows and exporst of the country. However, if the investment is made to bypass trade barriers and to exploit the large size of the market, Foreign Direct Investment may not lead to export growth.

Foreign Direct Investment has long been considered as an engine of economic growth of the host countries. One of the channels of accelerating economic growth is through promoting exports. Because of its advantageous position in terms of technology, managerial skills and access to international markets, Foreign Direct Investment inflow may accelerate host country's exports. Since there is debate about the intention of Foreign Direct Investment, whether market seeking or efficiency seeking, the present study tries to examine the kind of relation found in the case of India using VECM technique of determining causality. The study may finds that there is one co-integration relation between the variables implying that Foreign Direct Investment and export has long run relationship. The VECM result will shows that there is unidirectional causal relation from export to Foreign Direct Investment direction and not from Foreign Direct Investment to export direction. This implies that inflow of Foreign Direct Investment in India is mostly not for efficiency seeking (vertical Foreign Direct Investment). This may be coming to take advantage of growing market size determined by large population with high population and economic growth (horizontal Foreign Direct Investment).

Bibliography :

- Aggarwal Aradhana (1997). "Liberalization, internationalization advantages and foreign direct investment: the Indian experience in the 1980s", Transnational Corporations, Volume 6, Number 3, 33-57.
- Alici, A.A. and Ucal, M.S. (2003), "Foreign direct investment, exports and output growth of Turkey: Causality Analysis", Paper presented at the European Trade Study Group

(ETSG) fifth annual conference, Madrid, 11-13, Sept.

- Baliamoune-Lutz, M.N. (2004), "Doest FDI contributes to economic growth? Knowledge about the effects of FDI improves negotiating positions and reduces risk for firms investing in developing countries", Business Economics, 39(2), pp. 49-56.
- Brainard, S.L. (1993), "An Empirical Assessment of the Factor Proportions Explanation of Multinational Sales", NBER Working Paper No. 4583.
- Dickey, D. A., and W. A. Fuller (1979), "Distribution of the Estimator for Autoregressive Time Series with Unit Root", Journal of the American Statistical Association, vol.74, 427-431.
- Dickey, D. A., and W. A. Fuller (1981), "Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root", Econometrica, vol. 49, 1057-1072.
- Engle, R. F. and C. W. J. Granger (1987), "Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing", Econometrica, vol. 55, 251-276.
- Grossman, Gene and Helpman, Elhannan (1991),"Innovation and Growth in the Global Economy", MIT Press, Cambridge.
- Helpman, E. (1984), "A simple theory of international trade with multinational corporations", Journal of Political Economy 92.
- Helpman, E., Krugman P. (1985), "Market Structure and Foreign Trade", The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
- Johansen S. (1988) "Statistical analysis of Co-integration vectors", Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 12, 231-54.
- Johansen S. and Juselius K. (1990), "Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Applications to the Demand for Money", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 169-210.
- Khan, K. and Leng, K (1997), "Foreign Direct Investment, exports and Exonomic growth", SingaporeEconomic Review, 42(2), 40-60.
- Kojima, Kiyoshi (1973),"A Macroeconomic Approach to Foreign Direct Investment", Hitotsubashi Journal of Economics, vol. 14, 1-21.
- Kojima, Kiyoshi (1985),"Japanese and American Investment in Asia: A Comparative Analysis",Hitotsubashi Journal of Economics, vol. 26, 1-35/
- Krugman P. (1979), "Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade", Journal of International Economics, vol. 9, 469-479.
- Kumar, Nagesh and Siddharthan, N.S (1994), "Technology, Firm Size and Export Behaviour in Developing Countries: The Case of Indian Enterprises", The Journal of Development Studies, Volume 31, pp. 289 - 309.
- Kumar, Nagesh (1998), "Multinational Enterprises, Regional Economic Integration, and Export-Platform Production in the Host Countries: An empirical Analysis for the US and Japanese Corporations", Weltwirtschaftliches Archiv, Volume 134 (3), 450-483.

भारत में नारीवाद : एक अध्ययन

डॉ. सदन मरावी, (राजनीति शास्त्र), प्रभारी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, निवास, मण्डला, म.प्र.

सारांश :– भारत के इतिहास में 19वीं शताब्दी परिवर्तन की नयी लहर लेकर आयी थी, इस नयी लहर ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों एवं धार्मिक अंधविश्वासों को उखाड़ने के लिए जोर लगाना प्रारंभ किया था, पुनर्जागरण ने एक चेतना नये विचार और विश्वासों को जन्म दिया। पिछले कुछ वर्षों में नारी सम्बन्धी अध्ययनों के अवधारणात्मक एवं सैद्धान्तिक पक्षों पर काफी कुछ विचार एवं मंथन हुआ है। महिलाओं पर किए जाने वाले अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण, लैंगिक असमानता, महिलाओं की प्रस्थिति, उनकी भूमिका एंव उनके योगदान तथा उनके उत्थान के बारे में विभिन्न विचारधाराओं ने बौद्धिक जगत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है उत्तर आधुनिकता में भी 'नारीवाद' चिंतन का एक प्रमुख विषय माना गया। औद्योगिक क्रांति के बाद सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक मूल्यों एवं सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया। व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के विचारों ने जोर पकड़ा। प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था ने भी स्त्री–पुरुष को समान मताधिकार प्रदान कर शासन में उनकी भागीदारी के अवसर प्रदान किए। समाज सुधारकों द्वारा भी नारी की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयत्न किए गए। पिछले कुछ वर्षों में नारी से सम्बन्धित पुस्तकों पत्र–पत्रिकाओं में नारी की समस्याओं के बारे में बहुत कुछ लिखा और व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक पक्षों पर भी विचार किया गया है।

खोज शब्दः– नारीवाद का तात्पर्य, 21वीं शताब्दी में नारीवाद, भारत में नारीवाद

प्रस्तावना :– नारीवाद का क्या तात्पर्य है ? इस सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि ''नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अर्न्तगत स्त्री व पुरुष के बीच असमानता को अस्वीकार किया गया है तथा उसके सबलीकरण की प्रक्रिया को बौद्धिक एवं क्रियात्मक रुप से प्रस्तुत किया जाता है।'' यह एक विचारधारा के साथ–साथ एक आन्दोलन भी है। एक विचारधारा के अन्तर्गत इसमें कई प्रकार के सम्बोधों एवं सिद्धान्तों का समावेश किया गया है, एक सिद्धान्त के रुप में नारीवाद के अन्तर्गत समानता व सबलीकरण के द्वारा स्त्री व पुरुष के बीच पाई जाने वाली सामाजिक असमानता को नकारा गया है। नारीवाद को एक आन्दोलन के रुप में स्वीकार किया गया है। नारी आन्दोलन में प्रायः पुरुष की भागीदारी को नकारा गया हैं। नारीवाद को एक आन्दोलन के रुप में स्वीकार किया गया है। नारी आन्दोलन के अन्तर्गत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर नारी सम्मेलनो, गोष्ठियो, प्रदर्शनों का आयोजन किया गया हैं। तथा विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं लेखो एवं प्रचार के आधुनिक साघनों का सहारा लेकर अपने हितो के प्रति नारी में जागृति लाने के प्रयत्न किए गए है।[1]

अध्ययन के उद्देश्य :– भारतीय परिप्रेक्ष्य में नारी की स्थिति में सुधार हेतु प्रारंभ हुए नारीवादी आंदोलन, समाज सुधारकों के प्रयासों द्वारा नारी की स्थिति में हुए सुधार जो 21वीं शताब्दी में महिलाओं की सशक्त भूमिका में सकारात्मक योगदान को दर्शाती है प्रदर्शित करना है। **21वीं शताब्दी में 'नारीवाद'** विशेष स्वरूप से भारतीय पक्ष में नारी की स्थिति का ज्ञान वर्तमान समय में चल रही महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा स्पष्टता से समझा जा सकता है। जिसका प्रमाणीकरण विविध शोध कार्यो एवं समाज में महिलाओं की प्रभावी भूमिकाओं से प्रकट होता है। 21वीं शताब्दी में भारतीय नारीवाद का चित्रण प्रदर्शित करने से पूर्व हमें इतिहास के कुछ पृष्ठों को खंगालना आवश्यक है जिसके आधार पर हम भारतीय नारीवाद की सफलता का सही विकास क्रम ज्ञात कर सकते है। जिस समय भारतीय समाज में बुद्ध का प्रार्दुभाव हुआ, उस समय समाज में पितृसत्तात्मक तत्व व्यापक पैमाने पर

विद्यमान थे। उस समय लड़की का जन्म दुख का कारण माना जाता था[2] तथा स्त्रियों को जुए और शतरंज के साथ तीन प्रमुख बुराइयों के रुप में माना जाता था,[3] उस समय ऐसी महिला को आदर्श पत्नी के रुप में स्वीकार किया जाता था जो पति को देवता के रुप में स्वीकार करती थी (पति देवता)[4] और उसके चरणों में गिरकर (पादपरिचारिका)[5] स्वयं को भाग्यवान मानती थी। उस समय महिलाओं को वस्तुओं की तरह बेचा भी जाता था।[6] ये उदाहरण इस तथ्य को स्पष्ट कर देते है कि नारी की समाजिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी।

आधुनिक युग में अंग्रेजी शासन के दौरान ही नारियों की अवस्था पर समाज सुधारको का ध्यान गया। वस्तुतः नारी मुक्ति संबंधी विचार सभी समाज सुधारको द्वारा चलाये गये। समाज सुधार आन्दोलनों की शुरुआत मुख्य रुप से पुरुषों के द्वारा की गई। यथा राजा राममोहन राय, दयानन्द, सरस्वती ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस, केशवचन्द्र, महादेव गोविन्द राणाडे आदि के द्वारा।[7] इन महापुरुषों ने ब्रिटिश शिक्षा पद्धति से लाभ उठाया था और उनके उपर पाश्चात्य उदारवादी विचारो का प्रभाव था। महादेव गोविन्द राणादे के शब्दों में उन्नीसवीं सदी के समाज सुधार आन्दोलन का स्वरुप महान हिन्दू परम्परा के अनुकूल था..... इनका आधार प्राचीन सिद्धान्त था।[8]

भारत में 'नारीवाद' का प्रारम्भ स्वतंत्रता प्राप्ति की लड़ाई से प्रारंभ होता है। गाँधीजी के आह्वान पर अनेक विदुषी महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नारियों को उनके अधिकार दिलाने, बाल विवाह को रोकने विधवाओं का पुनर्विवाह कराने उन्हें पारिवारिक सम्पत्ति में हिस्सा दिलाने, पर्दा प्रथा को समाप्त करने बहुपत्नीत्व पर रोक लगाने आदि के संदर्भ में कई महापुरुषों द्वारा प्रयास किये गए, कई महिला एवं स्त्री संगठनों जैसे 'अखिल भारतीय महिला संघ', 'अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा संस्था', 'कस्तूरबा गाँधी स्मारक ट्रस्ट' आदि ने भी स्त्रियों की नियोग्यताओं का दूर करने एवं उनकी स्थिति को सुधारने के प्रयत्न किऐ। इनके प्रयत्नों के कारण ही सती प्रथा निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिन्दु स्त्री उत्तराधिकार अधिनियम, स्त्रियो एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम आदि बने, जिन्होंने स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।[9]

भारतीय नारीवाद 20वीं शताब्दी के अंतिम दौर को तिलांजली देते हुई 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है 21वीं सदी भारतीय नारी के लिए उपालब्धियों की सदी कही जा सकती। यह सदी कम्प्यूटर के प्रयोग पर आधारित जिसमे कम्प्यूटर मशीनी मस्तिष्क का स्थान लेने लगा है। कम्प्यूटर चुनाव–विश्लेषण एवं सरकारी कार्यालयों का काम करने तथा सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है जिसमें नारियों का योगदान वर्तमान समय में बड़ा एंव विविध क्षेत्रो में उनकी उपस्थिति भारतीय नारी के 21वीं सदी में प्रवेश की सूचक मानी जा रही है।

इक्कीसवी सदी सूचना प्रौद्योगिकी की सदी है – इस सदी में कम्प्यूटर इंटरनेट, ई–मेल, फैक्स, चैटिंग आदि की सुविधाएँ चरम सीमा पर है। जिसमें महिलाओं द्वारा उनका प्रयोग करना बड़ा जिसके माध्यम से उन्हें विश्व से सम्बन्धित जानकारियों का बोध एवं उनका ज्ञान का स्तर बड़ा एक प्रकार से मानसिक चेतना का तीव्रगति से विकास संभव हुआ आज देश की 30 प्रतिशत से भी अधिक महिलाओं द्वारा आधुनिक यंत्रो का इस्तेमाल किया जाता है।

शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार ने महिलाओं हेतु शिक्षा पद्धति में मूलभूत परिवर्तन करने का प्रयास लगातार कर रही है, नई शिक्षा नीति का ही परिणाम रहा की भारत की 65 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हुई।

सरकारी नौकरियों में सहभागिता – सेना प्रशासन रक्षा चिकित्सा शिक्षा आदि सभी क्षेत्रो में महिलाओं का योगदान बड़ा है। प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति, प्रतिभा पाटिल द्वारा सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के समान समानता को बडावा दिया।

औद्योगिक विकास में महिलाओं का योगदान निरंतर बढ़ता जा रहा है संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में महिला श्रमिको की सहभागिता बड़ी।

मीडिया एवं सिनेमा जगत में महिलाओं का बढ़ता रुझान – 21वीं सदी ग्लैमर की सदी के नाम से भी चर्चित है जिसमें सिनेमा जगत में लता मंगेशकर जया बच्चन, एवं ऐश्वर्या राय जैसी महिलाओं ने अपनी प्रभावी

भूमिकाओं का प्रदर्शन किया है, एवं मीडिया सोशल नेटवर्किंग में अपना स्थान बनाया जो महिलाओं की गतिशीलता का परिचायक है।

चिकित्सा एवं आतरिक्ष विज्ञान, खगौल, भौतिक विज्ञान सम्बन्धी खोजो एवं योगदान भी महिलाओं के ज्ञान तथा 21वीं सदी में उनकी प्रभावी भूमिका का परिचायक कहा जा सकता है।

राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता :– 21वीं शताब्दी के भूमण्डलीकरण के इस दौर ने निस्संदेह भारतीय नारी को ओर अधिक निश्चयी एवं अक्रामक बनाया हैं, राजनीतिक महिलाएं ही नहीं बल्कि साधारण महिला भी अक्रामक होती जा रही है। मायावती, ममता बेनर्जी से लेकर उमा भारती, जयललिता, सोनिया गाँधी सभी अक्रामक है नव–नारीवाद आज देश की असंख्य महिलाओं के राजनीति में सहभागी होने की प्रेरणा के साथ–साथ अपने देश में जनता का प्रतिनिधित्व करती नजर आ रही है। हॉल ही में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स सूची में सोनिया गाँधी सहित भारत की दो महिलाएं है। इस सूची के लिए 6 विभिन्न श्रेणियों में शक्तिशाली महिलाओं का चिह्नंकन किया जाता है, उनमें सम्पन्नत, व्यापार, लाइफ, स्टाइल (मनोरंजन व फैशन सहित) मीडिया नॉन प्राफिट व पॉलिटिक्स शामिल है वर्ष 2011 की ऐसी सूची अगस्त 2011 में जारी की गई जिसमें सोनिया गाँधी के अतिरिक्त भारत की दो अन्य महिलाओं आई.सी.आई.सी. आई. बैंक की सी ई.ओ. चंदा कोचर (43 वाँ स्थान) व बायोफॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ (99वाँ स्थान) को इस सूची में शामिल किया गया है। वहीं इतिहास की सर्वाधिक विद्रोही महिलाओं की एक सूची 'टाइम' पत्रिका ने मार्च 2011 के अपने एक अंक में प्रकाशित की थी जिसमें शीर्ष स्थान यमन की लोकतंत्र समर्थक मानवाधिकार कार्यकर्त्ता करमान का था वहीं भारत की दस्यु से सांसद बनी फूलनदेवी को 16 विद्रोही महिलाओं की इस सूची में चौथा स्थान दिया गया।[10]

21वीं सदी में महिलाओं को मिले अधिकार :–

- घरेलू हिंसा के खिलाफ, दहेज विरोधी कानून
- प्लांटेशन लेबर एक्ट, सम्पत्ति में बराबर का अधिकार
- वेतन में बराबरी का अधिकर, मातृत्व लाभ कानून
- स्पेशल मैरिज एक्ट, सती विरोधी कानून
- गर्भपात कानून

जहॉ 21 वी सदी में महिलाओं को इतना स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाया है। वही कुछ ऐसे कानून एवं प्रावधान है। जिनपर स्वीकृति न होना महिलाओं की गतिशीलता के मार्ग में बाधक सिद्ध हुआ है।

असमर्थ कानून :– आजाद हिन्दुस्तान में भारतीय महिलाओं को विश्व पटल पर छाते देखा, अंतरिक्ष पर जाते देखा लेकिन अपनी ही भूमि पर उन्हें छला भी गया सदियों से चली आ रही आम महिला की समानता की जंग अभी खत्म नहीं हुई। शक्ति और धैर्य का पर्याय मानी जाने वाली महिला को समानता दिलाने में पुराने कानून असमर्थ है। इस छलनी में तमाम छेद है पर देखने वालो की नजर में सब ठीक है। 21वीं सदी में भी पति के जारकर्म (अनैतिक संबंध) के खिलाफ पत्नी आपराधिक मामला नहीं दर्ज करा सकती। मसला चाहे तलाक के बाद पति की संपत्ति पर हक का या कार्यालयों में छेडछाड़ और यौन उत्पीड़न करने वालो के खिलाफ कार्यवाही का महिलाओं के बचाव मे कानून फिलहाल असमर्थ हैं।

- सड़क दुर्घटना के हाउस वाइफ को कम मुआवजा।
- जारकर्म (अडव्ट्री) कानून में भेदभाव।
- रोना में महिलाओं को अस्थायी कमीशन।
- पति से तलाक तो संपत्ति पर कोई हक नहीं।

- ऑफिस में छेड़छाड, यौन उत्पीडन कानून नहीं।

लंबित बिल – महिला सशक्तिकरण हेतु जिसका इंतजार अभी बाकी है :–

- महिला आरक्षण बिल
- हिन्दू विवाह कानून संशोधन बिल 2012
- कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकथाम बिल
- अश्लील चित्रण रोकथाम संशोधन बिल 2012
- अपराधिक कानून संशोधन बिल 2012

निष्कर्ष :– 21वीं सदी जहां महिलाओं की उपलब्धियों की बात करती है वहीं महिलाओं की दयानियता को भी दर्शाती है। 21वीं सदी का आगमन जिस जिज्ञापूर्वक उत्साह के साथ नारीयों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने वाले सपने के साथ आया था वह पूर्णतः उस रुप में स्थापित न हो सका कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज, हत्या, बलात्कार, अपहरण, शीलभंग, अश्लील महिलाओं का चरित्र करना जैसी घटनाओं ने 21वीं सदी में नारीउत्थान के क्रम को पैरो तले रैंद डाला जिसका जीवंत उदाहरण दिसम्बर 2012 में दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार की घटना से उपजे आंदोलन ने जिसने देश के नागरिको को प्रशासन को न्यायव्यवस्था एवं सरकार को जगाने का इतना प्रयास किया, परन्तु परिणाम संतोषजनक नही मिला। महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार एवं बलात्कार की घटनाओं में कमी न आना 21वीं सदी की नारियों के उत्थान पर प्रश्न चिन्ह ? खडा करती है। तथा 21वीं सदी में नारीवादी आन्दोलन को उग्र और तीव्र बनाने की आशा रखती है ताकि नारियों को समाज में अपना वास्तविक हक और सम्मान प्राप्त हो सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. हसनैन नदीम, 'समकालीन भाारतीय समाज', भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, 2007.
2. ऐतरेय ब्राह्मण, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, 1998.
3. मैत्रायणी संहिता, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी, 1998
4. जातक ग्रंथों में वर्णित है, द जातक, एडिकेट बाई.बी. फॉसवॉल II–वॉल्यूम, पृष्ठ 406.
5. वही. पृ. 95 VI वॉल्यूम 268.
6. वहीं
7. आर्या साधना, 'वीमने, जेंडर इक्विलिटी एण्ड स्टेट', नई दिल्ली, पृ. 30–32.
8. राणाडे महादेव गोविन्द, 'रिलिजियस एण्ड सोशल रिफार्म', मुम्बई 1902, पृ. 50.
9. गुप्ता एम.एल., शर्मा डी.डी. 'समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धान्त', साहित्य भवन, पब्लिकेशन, 2008.
10. प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिक वार्षिकी 2012, वॉल्यूम II

''भक्ति कालीन संगीत में प्रहरों का महत्व''

शैली धोपे

प्रस्तावना :– भारत के सांस्कृतिक जीवन में संगीत का विशेष स्थान है। यदि उपासना भारतीय जीवन का अभिन्न अंग है तो संगीत उपासना का अंग है। वेदमंत्रों में उदान–अनुदान स्वरित रूप से भारत के प्राचीनतम् साहित्य में संगीत के स्वर जागते हैं। आदि काव्य रामायण से पुराण, संस्कृत और पाली साहित्य तक काव्य संगीत उपासना का ही अंचल पकड़ कर सामने आये हैं, प्रहरों से मेल करते हुये। भक्तिमय संगीत जीनव में ताजगी व आनन्द भर देता है। चिंता, थकान, अवसाद में कमी लाता है। भगवान, इष्टदेव या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति श्रद्धा ''भक्ति कहलाती है तथा गीत वाद्यों द्वारा भगवत प्रेम की प्राप्ति एवं भगवान का गुणगान करना ''भक्ति संगीत'' कहलाता है। वेदों से चली आ रही परम्परा भक्ति संगीत एवं प्रहर का एक दूसरे से अटूट संबंध है।

संगीत वह ललित कला है, जिसमें स्वर और लय के द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हैं। ललित कलाओ में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संगीत मानवीय लय, ताल, वाद्य अभिव्यक्ति है। आचार्य शार्ग्ङदेव ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ''संगीत रत्नाकार'' में कहा है –

''गीत वाद्यं तथा संगीत मुच्यते''

अर्थात् गायन, वादन और नृत्य ये तीनों ही मिलकर संगीत कहे जाते हैं। नृत्य वाद्य का अनुगमन करता है और वाद्य गीत के पीछे–पीछे चलता है। अतः जब उपयुक्त राग–रागिनी में जब भी कोई गीत गाया जाये उसके अनुकूल ही वाद्य बज रहे हों और उस गीत के भावों को नृत्य की मुद्राओं के द्वारा व्यक्त किया जाये तभी संगीत पूर्णता को प्राप्त करता है। इस प्रकार तीनों कलायें एक दूसरे के पूरक हैं और अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति के लिये एक दूसरे पर अवलम्बित है, जैसे सत, रज और तमस इन तीनों से मिलकर यह दुनिया बनी है। इन तीनों में से किसी एक के भी न होने पर सृष्टि संभव नहीं है। उसी प्रकार गायन, वादन, नृत्य इन तीनों से मिलकर ही संगीत का संसार रचा है।

''सम्यक प्रकारेण यद् गीयते तत्संगीतम्''

अर्थात् सम्यक प्रकार जिसे गाया जा सके वही संगीत है। स्वर, ताल, शुद्ध आचरण, हाव–भाव और शुद्ध मुद्रा के गेय विशय ही संगीत है।

भक्ति कालीन संगीत – भक्ति संगीत की परम्परा प्राचीन काल से चली आ रही है। ''ऋग्वेद'' में भक्ति संगीत के प्राचीनतम गीत आज भी विद्यमान है। ''सामवेद'' को ऋग्वेद का रूपांतर कहा जाता है क्योंकि ऋग्वेद के मन्त्रों को जब गाया जाता है तो उसे ''सामवेद'' कहा जाता है। ''सामवेद'' को संगीतमय एवं भक्तिमय कहना उचित है तथा प्रथम भक्ति संगीत का अधिकारी भी। सामवेद उन ऋचाओं का संग्रह मात्र है जो गेय है। प्राचीन काल से ही ईश्वर की आराधना हेतु भजनों के प्रयोग की परम्परा काल से ही ई" वर की आराधना हेतु भजनों के प्रयोग की परम्परा रही है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति धार्मिक प्रेरणा से ही हुई है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद नवीन संस्कृति की जानकारी वेदों से मिलती है। ब्रम्हा ने सरस्वती को, सरस्वती ने नारद को, नारद ने भरत को और भरत ने नाट्य" शास्त्र द्वारा जन साधारण को दी। वेदों का मूल मंत्र है 'ओम'। 'ओम' शब्द में तीन अक्षर, अ, उ और म सम्मिलित हैं जिसे ब्रम्हा (सृष्टिकर्ता) विष्णु (जगतपालक) और महेश (संहारक) की शक्ति का द्योतक है। स्वर शब्द की उत्पत्ति भी 'ओम' के गर्भ से हुयी है। 'ओम' अर्थात सम्पूर्ण सृष्टि का एक अंश हमारी आत्मा में निहित है और संगीत उसी आत्मा की आवाज है अतः संगीत की उत्पत्ति हृदयगत भावों से मानी जाती है।

भक्ति काल – 1375 से 1700 ई. तक माना जाता है। इस समय श्रेष्ठ कवियों की उत्तम रचनायें प्राप्त हुयी। रामानुजाचार्य प्रमुख थे। रामानंद ने भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच का भेद तोड़ दिया। उन्होंने एक सूत्र दिया–

''जाति पाति पूछे नही कोई

हरि को भजे सो हरि का होई।

रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। रामानंद और उनकी मंडली ने दक्षिण की भक्ति गंगा का प्रवाह उत्तर में किया। समस्त उत्तर भारत भक्ति के प्रवाह में बहने लगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कृष्णावतार की उपासना का प्रचार किया। लीला गान का उपदेश देशभर में प्रवाहित किया। भक्ति युग की 4 प्रमुख काव्य धारा मिलती है :–

(1) सगुण भक्ति – (अ) रामाश्रयी शाखा (ब) कृष्णाश्रयी शाखा

(2) निर्गुण भक्ति – (अ) ज्ञानाश्रयी शाखा (ब) प्रेमाश्रयी शाखा

(1) **रामाश्रयी शाखा** :– प्रमुख कवि तुलसीदास ने मर्यादा पुरूषोत्तम का ध्यान करना चाहा इसलिये रामाचन्द्र को आराध्य माना और रामचरित मानस द्वारा राम कथा को घर–घर पहुंचा दिया।

(2) **कृष्णाश्रयी शाखा** :– इस गुण की शाखा का सर्वाधिक विकास हुआ। प्रमुख कवि सूरदास हुये। कृष्ण के बाल रूप एवं किशोर रूप का वर्णन किया। प्रायः सभी कवि गायक थे इसलिये कविता और संगीत का अद्भुत सुन्दर समन्वय इन कवियों की रचनाओं में मिलता है। गीत–काव्य की जो परम्परायें जयदेव और विद्यापति द्वारा पल्लवित हुई थी उसका चरम विकास इन कवियों द्वारा हुआ। राधा–कृष्ण की प्रेम–लीला द्वारा जन–मानस को रसाप्लावित कर दिया। आनंद की लहर देशभर में फैल गयी। प्रमुख कवि सूरदास, नंददास, मीरा बाई, हरिदास, रसखान, रहीम इसी समय के हैं।

(3) **ज्ञानाश्रयी शाखा** :– इस शाखा के भक्ति कवि निर्गुणवादी थे और नाम भर की उपासना करते थे। गुरू का वे अधिक सम्मान करते थे। कबीर दास प्रमुख थे। नानक, रैदास, दादूदयाल, सुंदर दास आदि अन्य कवि थे।

(4) **प्रेमाश्रयी शाखा** :– मुसलमान सूफी कवियों की इस समय की काव्य धारा को प्रेमार्गी माना गया है। उनका मानना था कि प्रेम से ईश्वर प्राप्त होता है। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी तत्व है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम संबंध ही हो सकता है। प्रेमगाथायें फारसी की मसनवियों की भौली पर रची गयी है। इन गाथाओं की भाषा अवधी है। इसमें दोहा, चौपाई, छन्दों का प्रयोग हुआ है। इन कवियों ने भौतिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम का वर्णन किया है। प्रमुख कवि मलिक मुहम्मद जायसी हैं। मंझन, कुतुबन और उसमान अन्य कवि हैं।

भक्ति संगीत का चरमोत्कर्ष :– 14,15,16 वीं शताब्दी मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के स्वर्णिम अध्याय का उदय हुआ। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। कीर्तन प्रणाली भक्ति संगीत में समाहित हुयी। हरिदास जी ने संगीत को उपासना के स्तर पर प्रतिष्ठित किया वहीं राज दरबार की शोभा भी बना। संगीत सम्राट तानसेन ने ध्रुपद की शास्त्रीय विधि को निखारा। गौड़ीय संप्रदाय ने वृंदावन को केन्द्र बनाकर कीर्तन भक्ति का प्रसार किया।

संगीत के आठ प्रहर :– भारतीय शास्त्रीय गायन विभिन्न समय, रात एवं दिन के निश्चित समय से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि किसी निश्चित समय पर निश्चित राग गाने से मनुष्य अपने उच्चतम् शिखर पर दिखायी देता है। कुछ राग सुबह के समय मधुर होते हैं, कुछ शाम के समय तो कुछ राग मध्य रात्रि के समय अपनी मधुरता फैलाते हैं। रागों के इस

दिन और रात के समय का संबंध हमारे शरीर और मन के समय से जुड़ा है जो हमारे शरीर को झन्कृत करता है। मनुष्य के स्वभाव में धनात्मक परिवर्तन लाता है मनुष्य के शरीर के विभिन्न अवयव विभिन्न समय में अपने उच्चतम् स्वर पर कार्य करते हैं।

प्राचीन आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य के शरीर में तीन मुख्य दोष कफ, पित्त, वात कार्य करते हैं। समय चक्र के अनुसार ये दोष कम या ज्यादा होते हैं अतः ऐसा माना जाता है प्रहर के अनुसार संगीत सुनना या गाना शरीर पर प्रभाव डालता है। प्रहर के अनुसार राग का वर्गीकरण निम्न प्रकार है :–

(1) 4am – 7 am - ये राग भोर, अरूणोदय या सूर्य निकलने के पहले गायी जाती है, जिसकी मुख्य राग भैरवी, भैरव, रामकली, जोगिया आदि हैं।

(2) 7am – 10 am - सुबह के समय गायी जाती है। मुख्य राग कोमल, ऋशभ आसावरी, देशकार, जैत आदि हैं।

(3) 10am – 1 pm - सुबह से दोपहर तक के समय में गायी जाती है। मुख्य राग गौड़ सारंग, वृन्दावनी सारंग, शुद्ध सारंग, अहिर ललिता आदि है।

(4) 1pm – 4 pm - दोपहर से देर दोपहर गायी जाती है। मुख्य राग मुलतानी, मधुवन्ती, भीम पलासी आदि।

(5) 4pm – 7 pm – शाम से सूर्य अस्त होने तक, गोधुली बेला में गायी जाती है। मुख्य राग काफी, मधुवन्ती, मिश्र पीलू, पूरिया धनश्री।

(6) 7pm – 10 pm – देर भाम से रात तक गायी जाती है। मुख्य राग पूरिया रागश्री, विहाग, देश, दुर्गा आदि।

(7) 10pm – 1 am – रात्रि से देर रात्रि तक गायी जाती है। मुख्य राग दरबारी, बागे" वरी, अभोगी, मालकौंस आदि।

(8) 1am – 4 am – देर रात से भोर तक गायी जाती हैं। मुख्य राग सोहनी, बसंत, ललिता, भटियार आदि।

भक्ति संगीत में प्रहरों का महत्व :– प्रहर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में संगीत प्रहर के अनुसार ही चलता था। मंदिरों में पूजा अर्चना संगीत के द्वारा ही की जाती थी। विभिन्न प्रहर में विभिन्न प्रकार का भक्ति संगीत था। हमारे दैनिक जीवन में बदलाव प्रहर के अनुसार संगीत सुनना या गाना शरीर में स्फूर्ती तथा ताजगी देता है।

ब्रम्ह मुहूर्त पर ईश्वर आराधना से दिन प्रारम्भ होता है इसलिये भैरव राग से आराधना की जाती है। पूजा–अर्चना समाप्त होने के बाद दिन शुरू होता है, कामकाज से जीवन आरम्भ होने लगता है तब तोड़ी राग गायी जाती है। सूरज माथे पर चढ़ने लगता है अलसाई हुयी दोपहर की दहलीज पर शरीर का थकना स्वभाविक क्रिया है तब सारंग राग से थकान दूर हो जाती है। पैरों के पास की परछाई शरीर से दूर होने लगती है। रूके थके हाथ फिर कामकाज में मग्न हो जाते हैं संध्या का आभास होने लगता है तब राग मुलतानी गायी जाती है। थका हारा सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगता है तब मन की उदासी में होंठो पर राग मारवा के शब्द गुनगुनाने लगते हैं। संध्या की बेला में श्याम रंग में लीन होने के लिये मन अधीर हो उठता है ऐसे समय पूरिया, धनाश्री राग गाया जाता है। रात का रंग चढ़ने लगता है मन की चंचलता के लिये राग बागेश्री गाया जाता है। गहराती श्यामल रात में अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिये मालकौंस गाया जाता है। मध्यरात्रि भौतिक सुख–दुख की अनुभूतियाँ लेने के बाद भी मन का खालीपन पूर्ण नहीं होता तब इस सांसारिक बन्धनों के पार उस ईश्वर के दर्शन की अभिलाषा मन में जाग्रत होती है तब कन्हड़ा गाया जाता है। रात्रि का अंतिम प्रहर ईश्वर तक पहुंचने के लिये अधीर मन राग अड़ाना गाता है। इसी चक्र के अनुसार रागों का चलन चलता रहता है और ये चलन भक्ति रस से ओत–प्रोत होते हैं। प्रहर के अनुसार भक्तिमय संगीत जीवन में शिथिलता प्रदान करता है।

संगीत धर्म निरपेक्ष है। भक्ति संगीत स्वास्थ्य और विजय का उपहार देता है। सभी धर्म के लोग जब हाथ में हाथ डालकर नाचते गाते हैं तो उनके शरीर ही नहीं मन और प्राण भी एक हो जाते हैं। आत्मा तन के बंधन से उन्मुक्त हो जाती है। प्रहर के अनुसार भक्ति गायन में विविध भावों से परिपूर्ण शाब्दिक चित्रण होते हैं। ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना जहॉ भक्ति रस से परिपूर्ण होती है वहीं यह प्रेम, वात्सल्य, करूणा का भाव लिये होती है। कृष्ण, शिव, देवी की भक्ति परक रचनायें विराट कार्यों में विस्मय एवं रौद्र से अभिभूत होती हैं। इसके अलावा रौद्र एवं वीर रस का भी वर्णन मिलता है। रचनात्मक एवं कलात्मक सौन्दर्य को सहजते हुये सत्व की उच्चता में जाकर आध्यात्मिक भाव की आत्मिक तृप्ति में ले जाता है। इतना ही नहीं मनुष्य भावमय हो जाता है। स्थिरता, भाांति, धैर्य, सहनशीलता, सुख, आनन्द का अनुभव करता। बुद्धि, ऊर्जा, आयु बढ़ती है। एक प्रकार का ठहराव विश्रांति को प्राप्त करता है।

भक्ति संगीत आठ प्रहरों के द्वारा ही पूर्ण होता है। वर्तमान में मनुष्य जीवन की भाग दौड़ से थका हारा महसूस करता है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्षीण होता जा रहा है। आधुनिकता और विकास की होड़ में दौड़ रहा है। रात दिन का फर्क भूल गया है। ऐसे समय भक्ति प्रहर ही जीवन में संतुलन पैदा कर सकता है। भक्ति संगीत तो विश्व के कोने–कोने में बसा है। पाश्चात्य शैली–पूर्वात्य शैली में अंतर है। हमारी भक्ति संगीत जो हमारी धरोहर है उसकी भाुद्धता एवं पवित्रता को कायम रखकर जीवन को समृद्ध बनाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिये।

संदर्भ :–

1. श्री कैलाशचन्द्र देव बृहस्पति, भरत का संगीत सिद्धांत।
2. प्रो. बलदेव उपाध्याय, वैदिक साहित्य।
3. श्रीयुत अश्विनी कुमार दत्त, भक्ति योग।
4. डॉ. पूनम शर्मा, प्राचीन भारत में संगीत
5. इन्टरनेट के माध्यम से।

सतना जिले में सीमेंट उद्योगों का विकास एवं समस्या

देवांशु गौतम, शोधार्थी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर

प्रस्तावना – सतना प्रशासनिक मुख्यालय और मध्य भारत में मध्यप्रदेश के सतना जिले का एक नगर निगम है, सतना राज्य एक सीमावर्ती शहर है और उत्तरप्रदेश, जिले के राज्य की सीमाओं उमरिया और कटनी जिलों में दक्षिण में रीवा जिला पूर्व और पश्चिम, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर में घिरा हुआ है पन्ना जिलों से, जिला रीवा संभाग का एक हिस्सा है, सतना मध्यप्रदेश में 7वीं सबसे अधिक आबादी वाले शहर है, यह मध्य प्रदेश, टोन्स के सबसे तेजी से बढ़ते शहर में से एक है, बेटा और पाईसुनी गंगा के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती जिले की महत्वपूर्ण नदियाँ है, हिस्ट्री सतना या सतना नदी रामायण काल की प्राचीनकाल की ''सुतीकसन मुनि'' नामक लोक प्रिय ऋषि के नाम से अपने नाम मिल गया है कि अपने आसपास के क्षेत्र में बहने से अपने नाम मिल गया, इस जग के साथ जुड़े इतिहास काल भगवान राम चित्रकूट के क्षेत्र में रूके रामायण के हिंदू पवित्र पुस्तक में बताया गया है, इसमें से आधा रेस्ट, सतना पहले एक ब्रिटिश स्टेशन गया जो उत्तर प्रदेश, साथ सण सतना के बाहरी इलाके में है, बघेलखण्ड के लिए राजनीतिक एजेंट के मुख्यालय, 1871 में सतना में स्थापित किया और 1931 में समाप्त कर दिया, निकटवर्ती भरहुत तथापि, खुदाई अवशेष के सबसे तत्कालीन ब्रिटिश रूरल्स कल्चर सतना द्वारा भारतीय संग्रहालय के लिए भेजा गया पहला कनिंघम द्वारा 1873 में खोज की एक दो शताब्दी ई.पू. बौद्ध स्तूप के अवशेष, वहाँ रहे हैं, आध्यात्मिकता के एक भूमि के लिए प्रसिद्ध है दो प्रमुख धार्मिक पर्यटक स्थल, चित्रकूट धाम और मैहर, सतना जिला भी जिसका पुरातात्विक अवशेष देश और दुनिया में प्रमुख संग्रहालयों को उपहार में दिया गया है। भरहुत नाम बौद्ध संस्कृति के प्राचीन शहर के रूप में जाना जाता है, राम वैन में तुलसी संग्रहालय में इस क्षेत्र में पाया प्राचीन काल के कई अनूठी कलात्मक मूर्तियाँ है, बिरसिंहपुर में भगवान शिव मंदिर भी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, भी प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक जंगलों की तरह संसाधनों दिनयों और माउंटेन्स लाईमेट ड्यूरिंग गर्मी के साथ भेंट की है अधिकतम तापमान –45 ए डिग्री सेल्सियस और न्यनूतम है 22. 3Aसी.^{0} सर्दियों में तापमान 24A डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम –4 ए डिग्री सेल्सियस है बरसात के दिनों की संख्या जुलाई और अगस्त के महीनों में अधिकतम और मध्य नवम्बर से फरवरी तक सर्दियां है, ठंड, एजुकेशन सतना को बरसात से अक्टूबर जलवायु परिवर्तन के महीने से 59.5% के राष्ट्रीय औसत से अधिक 70% की एक औसत साक्षरता दर है; पुरूष साक्षरता 76% है, और महिला साक्षरता 62% है, यह 1993 में चित्रकूट में भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय को मिली है 16 राज्य सरकार विश्वविद्यालय की जो 1 (महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय) अवधेस प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कई कॉलेज परिसरों कर रहे हैं, सतना आदि जैव प्रोद्योगिकी, कम्प्यूटर, मैनेजमेंट, पत्रकारिता जैसे कई पाठ्यक्रमों भारत के चूना पत्थर बेल्ट में है विभिन्न इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रीस सतना द्वारा की पेशकश कर रहे विंध्य क्षेत्र के एक शैक्षिक केन्द्र है, नतीजतन, यह लगभग 8% भारत के कुल सीमेंट उत्पादन का –9% योगदान देता है, और दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादन जिले के रूप में जाना जाता है, शहर में सीमेंट के उत्पादन और भारत के सीमेंट शहर के रूप में जाना जाता है। कंट्री सतना के अन्य भाग के लिए एक ही निर्यात कर रहे हैं कि सीमेंट कारखानों के सात नंबर है, कारण क्षेत्र में चूना पत्थर और डोलोमाइट की बहुतायत है, सतना में बिजली के केबल कम्पनी 'यूनिवर्सल केबल्स' देश में अग्रदूतों में से है, शहर क्योंकि देश में प्रतिष्ठित औद्योगिकतम घरानों में से कुछ ने योजना बनाई कई नए उद्योगों का मध्य प्रदेश के कुछ सबसे होनहार शहरों के बीच है, सतना इस इंडस्ट्रीज सीमेंट विनिर्माण, हथकरघा बुनाई, आटा, तिलहन मिलिंग और सड़क और रेल जंक्शन।

पूर्व शोध साहित्य का अध्ययन

1. **अग्रवाल डॉ.राधा** ने अपने राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी ''पर्यावरण संतुलन के अस्तित्व पर मँडराता संकट, चिंतन–मनन एवं निदान'' में ज्ञात किया है कि विश्व पर्यावरण संकट में है।

2. **मिश्रा, डॉ. सुलेखा, मिश्रा, डॉ. राजेन्द्र** ने अपने शोध आलेख ''ग्राम स्वावलंबन व पर्यावरण प्रबंधन के लिए जरूरी'' में ज्ञात किया है कि प्रकृति ने संपूर्ण जीवनमंडल के लिए स्थल, जल और वायु के रूप में एक विस्तृत आचरण निर्मित किया है जिसे हम ''पर्यावरण'' की संज्ञा देते हे। पर्यावरण के संतुलन के लिए प्रकृति ने कुछ नियम भी निर्धारित किये है, किंतु जब से इस पृथ्वी पर मनुष्य का अवतरण हुआ है तब से पर्यावरण संतुलन के प्राकृतिक नियमें का खुला उल्लंघन शुरू हुआ है और निरंतर प्रकृति की अनदेखी के कारण आज हमारे पर्यावरण को अनेक समस्याओं सें जूझना पड़ रहा है।

3. **डॉ. सोमवती विनादिया**, ने अपने शोध आलेख "पर्यावरण प्रबंधन के उभरते सामाजिक मुद्दे एवं पर्यावरण" में ज्ञात किया है कि,पर्यावरण का अर्थ है आधुनिक मानवीय समाज के पर्यावरण के साथ संबंध तथा उससे पड़ने वाले प्रभाव से है अर्थात् यह भी कहा जा सकता है कि पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ संरक्षण ही नही बल्कि समस्त मानव जाति के लिये पर्यावरण के संरक्षण से है। इन प्रबंधकों को प्रभावित करने वाले मुद्दे है किंतु इनमें प्रमुख मुद्दा सामाजिक, राजनीतिक एवं उनके संरक्षण के लिये किये जाने वाले कार्य या कार्यक्रम या नीतियां है।

4. **श्रीमती, निधि विश्वकर्मा,** ने अपने शोध आलेख "सामाजिक मुद्दे एवं पर्यावरण" में ज्ञात किया है कि, जल को कोई विकल्प नही हैं।मनुष्य सहित पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव–जंतु एवं वनस्पति का जीवन जल पर ही निर्भर है। जल का कोई विकल्प नही है। यह हमे प्रकृति से प्राप्त निःशुल्क उपहार है। किन्तु विडंबना यह है कि पृथ्वी की सतह का 70 प्रतिशत हिस्सा जलमग्न होने के बावजूद मानव के उपयोग लायक जल केवल 2.5 प्रतिशत ही है। शेष जल लवणीय होने के कारण न तो मानव द्वारा निजी उपयोग में लाया जा सकता है और न ही इससे कृषि कार्य हो सकता है।

सतना जिला मध्यप्रदेश का जिला हैं इसका मुख्यालय सतना है। सतना जिला रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। इसकी सीमा उत्तर में उत्तरप्रदेश के बांदा जिले से लगी हुई है। जिले की पूर्वी सीमा रीवा जिले की त्थौथर, सिरमौर, और हुजूर तहसील से तथा सीधी जिले के गोपतबनास तहसील से लगी हुई है। दक्षिण पश्चिम में शहडोल जिला है। दक्षिण में उमरिया और कटनी जिला है, एवं पश्चिम में पन्ना जिला है। यह जिला 6 तहसीलों में बटा हुआ है– अमरपाटन, मैहर, नागोद, रघुराजनगर, और सतना।

आर्थिक रूप से यह अन्य जिलों की अपेक्षा उच्च हैं। यहाँ पर सीमेंट के कारखाने है, हेण्डलूम है, तेल मिल और कृषि से संबंधित अन्य उद्योग लगाये गए है। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना प्रिज्म सीमेंट यहीं पर स्थापित किया गया है। जिले में परिवन के साधन बहुत है। यहाँ से 120 कि.मी. खजुराहो हवाई अड्डा स्थित है। यह जिला राष्ट्रीय राज्य मार्ग 7 से जुड़ा है। और यह रेल परिवहन को देखा जाए तो यह मुख्य शहरों से जुड़ा है।

पर्यावरण का अर्थ – पर्यावरण का सामान्य अर्थ भौतिक परिवेश से है, जो पृथ्वी के जीव जगत को चारों ओर से घेरे हुये है। दूसरे शब्दों में सम्पूर्ण पृथ्वी का जीवन एक आवरण से आवृत है जो इसे परिचालित करता है एवं स्वयं भी प्रभावित होता है। पर्यावरण अंग्रेजी के शब्द ''एनवायरमेन्ट'' शब्द का अनुवाद है जो दो शब्दों एनवायरन व मेन्ट से मिलकर बना है। जिसका अर्थ आवृत करना है। अर्थात् जो चारों ओर से घेरे हुए है।

पर्यावरण किसी एक तंत्र समूह का नाम नहीं है वरन् अनेक तंत्रों का सामूहिक रूप हैं जो सम्पूर्ण जीव जगत को प्रभावित करता है तथा उसे घेरे रहता है। इस घिराव को पर्यावरण कहते हैं। वह पर्यावरण है सम्पूर्ण जीव जगत, स्थल मण्डल, वायु मण्डल और

जल मण्डल से आवृत है और यह आवरण ही पर्यावरण कहलाता है।

पर्यावरण को परिभाषित करते हुए हर्सकोविट्स ने लिखा है ''पर्यावरण समस्त परिस्थितियों और उसका जीवधारियों पर पड़ने वाला प्रभाव है जो जैव जगत के विकास चक्र का नियामक है।''

युनिवर्सल विश्वकोष के अनुसार– ''पर्यावरण के अन्तर्गत उन सभी दशाओं, संगठन एवं प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी जीव अथवा प्रजाति के उद्‌भव, विकास एवं मृत्यु को प्रभावित करती है।''

एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने भी परिभाषा दी है– ''पर्यावरण उन सभी बाह्य प्रभावों का समूह है जो जीवों को भौतिक एवं जैविक शक्ति से प्रभावित करते रहते हैं तथा प्रत्येक जीव को आवृत किये रहते हैं।'' इस परिभाषा से पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट होता है कि पर्यावरण के अन्तर्गत विभिन्न तत्वों की क्रिया–प्रतिक्रिया से वातावरण का निर्माण होता है। यदि वातावरण जीव के अनुकूल होता है तो उसका उद्‌भव एवं विकास संभव हो पाता है अन्यथा प्रतिकूल परिस्थितियों में जीव का अन्त हो जाता है। वर्तमान मानव की वैज्ञानिक सोच के कारण एवं उसके निरंतर महत्वाकांक्षी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किये जाने वाले क्रियाकलापों के कारण, मानवीय पर्यावरण, उससे संबंधित जीव–निर्जीव पदार्थों, पेड़–पौधों, प्राणियों सहित बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

पर्यावरण के विभिन्न कारक –

पर्यावरण अनेकों जैविक और अजैविक कारकों का एक जटिल समूह है। इसके मुख्य कारक निम्नलिखित है –

1. **अजैविक कारक** – इसके अन्तर्गत भौतिक कारक जैसे– ताप, प्रकाश, आर्द्रता, मृदा इत्यादि और रासायनिक कारक जैसे– वायुमण्डलीय गैसें, pH, पोषक तत्व इत्यादि आते हैं। ये सभी कारक परस्पर एक–दूसरे से सम्बन्धित हैं। किसी स्थान विशेष के जीवों पर पड़ने वाला प्रभाव इन सभी कारकों की क्रिया–प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थिति पर निर्भर करता है। कोई एक कारक पृथक रूप से जीवों को प्रभावित करता हो ऐसा नहीं है। माध्यम जिसमें प्राणी निवास करते हैं एवं जलवायु दोनों ही की रचना में इन कारकों का प्रमुख योगदान रहता है। पर्यावरण के अजैविक कारकों को मृदीय, स्थलाकृति और जलवायुगत कारकों में प्रविभाजित किया जाता है। अजैविक कारकों का वर्णन निम्नलिखित है –

1. **ताप** – ताप ऊष्मा की ही अभिव्यक्ति है। पृथ्वी को ऊष्मा सूर्य से किरणों के रूप में प्राप्त होती है। ताप का पर्यावरण में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह पेड़–पौधों एवं जीव–जन्तुओं दोनों को ही प्रभावित करता है। तापमान का प्रत्यक्ष प्रभाव मनुष्य, वनस्पति, जीव जन्तु व वायुमण्डल पर पड़ता है। तापमान जल, धल के जीव–जन्तु व वनस्पति तथा मनुष्य के लिए आवश्यक है।

प्रत्येक प्राणी में तापक्रम का एक परिसर होता है, जिसे वह सहन कर सकता है। वे प्राणी जो तापक्रम के लम्बे परिसर को सहन कर सकते हैं, पृथुतापी कहलाते हैं, जैसे– टोड, छिपकली, मुनष्य आदि। छोटे तापक्रम परिसर वाले प्राणी तनुतापी कहलाते हैं, जैसे– दीमक, मछलियाँ आदि। जिसे तापक्रम का प्राणी अपनी जीवन क्रियाएँ दक्षतापूर्वक सम्पन्न करता है, उसे अनुकूलतम तापक्रम कहते हैं।

2. **प्रकाश** – प्रकाश का मुख्य स्त्रोत सूर्य ही है, जिससे विकिरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके पौधे भोजन बनाते हैं। वास्तव में प्रकाश द्वारा संश्लेषित ऊर्जा ही सभी जीवधारियों के जीवन का मूलभूत आधार है। साधारणतः आँख से दिखने वाली बैंगनी, नीली, आसमानी, हरी, पीली, नारंगी तथा लाल रंगों की किरणों को ही प्रकाश कहते हैं। परन्तु वास्तव में सूर्य के प्रकाश में कॉस्मिक किरणें, गामा व x-किरणें, अल्ट्रा–वाइलेट, इन्फ्रा–रेड किरणें, ताप तरंगे, राडार तरंगे, रेडियो तरंगे आदि भी पायी जाती है। सूर्य द्वारा प्राप्त होने वाले प्रकाश का प्रत्यक्ष प्रभाव मुनष्य, वनस्पति, जीव–जन्तु व वायुमण्डल पर पड़ता है।

3. **जल** – पृथ्वी का लगभग 71 प्रतिशत भाग जल से ढँका हुआ है और समस्त जैव–भूमण्डल के जीवों के लिए प्रयत्क्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल का असीमित

महत्व है। जल के बिना जीवन की संकल्पना करना भी कठिन है। पृथ्वी पर जल का वितरण सब जगह एक समान नहीं है। जल में कुछ अनोखे गुण हैं जिसके कारण यह जीवन को तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभावित करता है। इसके भौतिक गुणों में हवा से अधिक भारीपन, पारदर्शिता, श्यानता तथा ताप सम्बन्धी उल्लेखनीय गुण बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक प्राणी को जल की आवश्यकता होती है। इसलिए प्राणियों का वितरण जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। उपलब्ध जल के परिमाण की दृष्टि से पृथुजलीय प्राणियों का सहनशीलता परिसर विस्तृत होता है, जबकि तनुजलीय प्राणियों में जल के लिए सहनशीलता परिसर संकीर्ण होता है। थल पर पौधों का वितरण प्रत्यक्ष रूप से जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जहाँ जल की अधिकता होती है वहीं पेड़–पौधों की संख्या भी अधिक होती है। अतः उस स्थान का पर्यावरण भी शुद्ध रहता है।

4. आर्द्रता – आर्द्रता का सामान्य अभिप्राय वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा से होता है और इसे दो प्रकार से दर्शाया जाता है–

(अ) सम्पूर्ण आर्द्रता – किसी स्थान पर वायु की प्रति इकाई में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा का भार सम्पूर्ण आर्द्रता कहलाती है।

(ब) सापेक्ष आर्द्रता – सापेक्ष आर्द्रता समान ताप और दबाव पर संतृप्त बिन्दु की तुलना में वायु में जलवाष्प की प्रतिशत मात्रा दर्शाती है।

सापेक्ष आर्द्रता ही विशिष्ट प्रकार की वनस्पति की उपलब्धि और जीव–जन्तुओं की उपलब्धि और वितरण निश्चित करती है। नमी वायु में उपस्थित रहती है। तापमान के अनुरूप वायु में नमी बनी रहती है।

5. मृदा – पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को मृदा कहते हैं जिसका निर्माण मिट्टी से ठीक नीचे वाली चट्टानों के विघटन और उन पर कार्बनिक पदार्थों और सूक्ष्म जीवधारियों की निरंतर अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है और जिसमें अधिकांश वनस्पतियाँ और जन्तु स्थायी रूप से निवास करते हैं।

मिट्टी में अनेकों अकार्बनिक लवण, पोषक तत्व, कुछ कार्बनिक यौगिक आदि रासायनिक पदार्थ होते हैं। मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता भी सीमाकारी कारक है। खनिज कणों का आकार, वायु और जल की मात्रा को निर्धारित करके मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जन्तुओं जैसे बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ तथा केंचुए आदि की श्वसन व अन्य जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं।

पर्यावरण, परितंत्र, तथा मानवसहित अन्य सभी जीव प्रकृति के महत्वपूर्ण घटक हैं। ये घटक अपने विभिन्न दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं द्वारा परस्पर प्रभावित करते हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने में मदद करते हैं।

मुख्य रूप से भौतिक पर्यावरण मानव को निम्नलिखित माध्यमों से प्रभावित करता है –

1. जैव–भौतिक सीमाओं द्वारा,
2. पारिस्थितिकी जलवायु
3. व्यवहारिक नियंत्रणों द्वारा,
4. संसाधन की सुलभता द्वारा।
5. भौगोलिक जलवायु ।

पर्यावरण सुधार के मूलभूत आयाम –

1. **विज्ञान शिक्षण द्वारा** – प्रकृति के गूढ़ रहस्यों की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान का परम उद्देश्य रहा है। पर्यावरण, गुणवत्ता सुधार भी विज्ञान का अभिन्न अंग है। पर्यावरण अवयव विज्ञान से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित हैं। लोगों की आवश्यकताओं, रूचियों और क्षमताओं तथा उनके मानसिक विकास एवं सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों, वैज्ञानिकों एवं सामान्यजन हेतु आधुनिक प्रभावशाली पर्यावरण कार्यक्रम तैयार करना होगा। विज्ञान अध्ययन में पर्यावरण का उपभोग बहुत प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है जिसके अंतर्गत छात्रों को अभिप्रेरित करना, उपयुक्त विधि की खोज, पर्याप्त प्रमाणों का संग्रहण एवं उचित निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है।

बाल मनोवैज्ञानिक जिज्ञासा एवं उसके समाधान हेतु उचित सामग्री की तलाश भी पर्यावरण में की जा सकती है। इसके लिये काफी सीमा तक

विद्यार्थी भी सहायता कर सकते हैं, इसी प्रकार शिक्षक भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

2. **सामाजिक विज्ञान शिक्षण द्वारा** – सामाजिक विज्ञान द्वारा नागरिकों को उनके भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण एवं उसमें निहित बलों की जानकारी से अवगत कराया जा सकता है। बच्चों का सामाजिक पर्यावरण उनके घर से आरम्भ होकर जिला प्रदेश तक पहुँचता है। बच्चों को उनके भूत और वर्तमान, भौगोलिक एवं सामाजिक पर्यावरण से अवगत कराके पर्यावरण के प्रति उसके उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्यों की जानकारी देनी चाहिये। विगत शताब्दियों के क्रान्तिकारी परिवर्तनों के कारण समाज की रचना जटिल हो रही है फलस्वरूप वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विकास के साथ मानव अनेको प्रकार से तनाव ग्रस्त है। सामाजिक विज्ञान में मानवीय मानसिक तनाव जैसी अन्य खतरनाक समस्याओं का समावेश करना होगा। नाटकीयकरण, भेटवार्तायें, पर्यटन समूह चर्चा, स्वयं अध्ययन इत्यादि का प्रयोग कर पर्यावरणीय समस्याओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से समझाया जा सकता है।

3. **अध्यापक द्वारा** – इस पर्यावरण आयाम के द्वारा भी पर्यावरणीय गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है जिसके अंतर्गत पाठक क्रिया स्थानीय पर्यावरण, उसके स्त्रोतों, अध्यापकों की विचारधारा, अनुभव सभी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। यही कारण है कि इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार वांछित रहता है।

प्रदूषण को फैलाने क जिम्मेदार कारक –

1. जनसंख्या वृद्धि,
2. शहरीकरण,
3. औद्योगीकरण,
4. यातायात,
5. कीटनाशक दवायें एवं रासायनिक खादों का अनुचित प्रयोग,
6. पशु,
7. युद्ध,
8. वनों का ह्रास।

पर्यावरण सामग्री का अध्यापन में उपयोग निम्नलिखित उपायों द्वारा किया जा सकता है–

1. बच्चों को पर्यटन पर ले जाकर।
2. प्रशिक्षुओं के पूर्व अनुभव का लाभ लेकर।
3. सामग्री का संग्रह करके कक्षा में दिखाकर।
4. चित्रों द्वारा।
5. सामग्री का संग्रह करके शिक्षार्थियों से क्रियायें कराकर।

संदर्भ–ग्रंथ –

1. **अग्रवाल डॉ.राधा पर्यावरण संतुलन के अस्तित्व पर मँडराता संकट, चिंतन–मनन एवं निदान**
2. **मिश्रा, डॉ. सुलेखा, मिश्रा, डॉ. राजेन्द्र ''ग्राम स्वावलंबन व पर्यावरण प्रबंधन के लिए जरूरी'' गोपनीय विभाग(पी.एच.डी) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर (म.प्र.)**
3. **डॉ. सोमवती विनादिया "पर्यावरण प्रबंधन के उभरते सामाजिक मुद्दे एवं पर्यावरण"**
4. **श्रीमति, निधि विश्वकर्मा ''सामाजिक मुद्दे एवं पर्यावरण'' शोध छात्र, रानी दुर्गावती विश्व विद्यालय, जबलपुर**

राष्ट्रीय जैव विविधता

धनेन्द्र कुमार, शोधार्थी, एम.ए., एम.फिल. पी–एच.डी. अध्ययनरत (राजनीति विज्ञान)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर

भारत के संदर्भ में – भारत एक वृहत् विविधताओं वाला राष्ट्र है। विश्व में केवल 12 ऐसे राष्ट्र हैं जो वृहत् जैव विविधता राष्ट्र के रूप में जाने जाते है। भारत भी इन जैव विविधता रखने वाले 12 राष्ट्रों में सम्मिलित है। ऐसा माना जाता है कि विश्व के सर्वाधिक पादप सम्पन्न राष्ट्रों में भारत का 10 वाँ स्थान है, तथा जैव विविधता एवं कृषि विविधता की उत्पत्ति की दृष्टि से भारत का 6 वाँ स्थान है।

भारत का विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2 प्रतिशत भू–भाग है ताकि इस राष्ट्र में विश्व की कुल ज्ञात जैव प्रजातियों का 6 प्रतिशत भाग निवास करता है। इसके अलावा भारत के पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट क्षेत्र जैव विविधता सम्पन्न क्षेत्र या जैव विविधता के तप्त स्थलो की उपस्थिति में उल्लेखनीय है।

वर्तमान में भारत में जेनेटिक भिन्नता रखने वाले 1.25 लाख से अधिक आर्थिक वैज्ञानिक रूप से वर्णित प्रजातियॉ तथा 4.0 लाख से अधिक अवर्णित प्रकृतियाँ है जो देश के कुल 328.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्षेत्रफल पर फैली हुई है।

भारत में जैव प्रजातियों की आर्थिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण है कि इस देश में जलवायु तथा उच्चावच की दृष्टि से पर्याप्त भिन्नताएँ।

जैव विविधता के ह्रास के कारण –

जैव विविधता के ह्रास के निम्नलिखित कारण प्रस्तुत हैं–

4. **प्राकृतिक कारण** – जब जलवायु में होने वाले परिवर्तनों को कोई जीव सहन नहीं कर पाता अर्थात् प्राकृतिक दशाओं के अनुरूप स्वयं को ढ़ाल नहीं पाता तो उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। अतः इस प्रकार की प्रजाजियाँ पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाती हैं। साथ हीं जो प्रजातियाँ इन जलवायु परिवर्तनों के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेती हैं, वे प्रजाजियाँ और अधिक विकसित रूप में अस्तित्व में आती चली जाती हैं।

5. **निवास क्षेत्रों का विनाश** – वर्तमान क्षेत्र में विकास के नवीन आयामों की खोज में जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण वनोन्मूलन है। आर्द्र प्रदेशों तथा अन्य जैविक रूप से सम्पन्न पारिस्थितिकी तंत्रो के विनाश से प्रतिवर्ष सैकड़ों प्रजातियों का पृथ्वी से पूर्णतया सफाया हो जाता है।

प्रजातियों में निवास क्षेत्र के विनाश से जहाँ एक ओर प्रजातियों की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आती है, वहीं दूसरी ओर निवास क्षेत्र छोट–छोटे विलग भागों में विभक्त हो जाता है। वन्य जीवों के अस्तित्व की रक्षा के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थाना वनों का होता है। वनों के विभिन्न उपयोग हेतु अनियंत्रित कटाई से जीवों के निवास क्षेत्र नष्ट होते जा रहे हैं।

6. **जंगली जीवों का अवैध शिकार** – भू–पटल पर जंगली जीव वस्तुओं का मानव द्वारा वृहत् स्तर पर अवैध शिकार करने से इनका तेजी से विनाश हो रहा है। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्धों/नियमों आदि के बावजूद भी जीवों का अवैध शिकार किया जा रहा है। जीवों से प्राप्त बहुमूल्य खाल, दाँत, हड्डियाँ आदि से आर्थिक लाभ पाने के उद्देश्य।

मानव वन्य जीवन संघर्ष

मानव प्राचीन काल से ही वनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं के लिये करता आया है। मनुष्य अपनी सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही वन्य जीवन का

अविवेकपूर्ण ढ़ग से विदोहन करता आया है किन्तु 20वीं शताब्दी में बढ़ते औद्योगीकरण नगरीकरण तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण मानव द्वारा वन्य जीवन के विदोहन की दर में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई है। भू–पटल पर वनों तथा घास के क्षेत्रो के सिकुड़ते क्षेत्रफल से जंगली जीव–जन्तुओं के प्राकृतिक आवासीय क्षेत्रो को नष्ट करने तथा मानव द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से इनका वृहत् स्तर पर शिकार करने से जंगली जीव–जन्तुओं को तेजी बिनाश हो रहा है। फरयुक्त खालों के लिये शेर, हिरण तथा चीता को उनकी बहुमूल्य खालों के लिये तथा हाथियों को उनके कीमती दाँतो के लिये मानव द्वारा वृहत् स्तर पर इन जीवो को मारा जा रहा है, साथ ही अनेक अन्य जंगली जीवों तथा पक्षियों के मास प्राप्ति के लिये शिकारियों द्वारा शिकार किया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि कई प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी है और कई विलुप्ति की कगार पर है।

जैव–विविधता का महत्व

जैव–विविधता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योकि यह मानव संस्कृति के विकास में बहुत सहायक होती है। दूसरी ओर मानव ने अनवंशिक प्रजातीय व परिस्थितिकी स्तरों पर प्राकृतिक विविधता बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव–विविधता की तीन मुख्य बकाए हैं जिन्हे पारिस्थितिकी आर्थिक तथा वैज्ञानिक भूमिका के में जाना जाता है।

जैव–विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका

परितंत्र में अनेक प्रजातियां होती है, जो विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। प्रत्येक जीवन आपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ वस्तुओं का प्रयोग करता है, और साथ ही अन्य जीवों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ पदार्थ लौटाता है।

जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती हैं और पारितंत्र में जल व पोषण तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायता देती है। इसके अतिरिक्त प्रजातिया वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती है। और जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्रजातियों द्वारा किए गए कार्य पारितंत्र को कार्यरत रखने तथा मानव जीवन के विकास के लिए उपयोगी हैं।

पारितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी प्रजातियों के प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होगी। स्पष्ट है कि प्रजातियों की क्षति से पारितंत्र की क्षमता भी कम हो जाती है। अधिक जैव–विविधता वाले पारितंत्र में पर्यावरणीय परिवर्तनों को सहन करने की क्षमता अधिक होती है। अतः अधिक विविधता वाले पारितंत्र की स्थायी रहने की संभावनाएं भी अधिक होती है।

जैव विविधता

जैव विविधता अथवा जीवीय विविधता का अभिप्राय जीवों को विविधता अथवा प्रचुरता से है। किसी प्रदेश की जैव विविधता वहां पर रहने वाले सूक्ष्मजीवों पादपों तथा पशुओं के योग द्वारा आंकी जाती है। विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार ''जैव विविधता विश्व के जीवो तथा उनके जनन का विविधता एवं उनके द्वारा निर्मित संयोजन से है। यह प्राकृतिक जैव सम्पत्ति है जो मानव जीवन तथा उसके कल्याण को प्रभावित करती है''

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार '' सभी पशुओं पादपों एवं सूक्ष्मजीवो तथा पारिस्थितिकी जटिलताओं की विभिन्नता एवं परिवर्तशीलता को जैव विविधता कहते हैं।'' जैव विविधता की संकल्पना को तीन विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है और प्रत्येक स्तर का अपना विशेष महत्व है। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

भारत में जैव विविधता

32.87 लाख वर्ग किमी. से भी अधिक क्षेत्र वाला भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है जिसमें अधिकांश भागों में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अतः यह जैव विविधता की दृष्टि से बड़ा ही समृद्ध देश है। इसके लगभग 6,77,088 वर्ग किमी. श्रेत्र पर वन उगे हुए हैं। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 20.59 प्रतिशत है। इसमें से 38,726 वर्ग किमी. (57.19) सघन वन, 289872

वर्ग किमी. (42.81%) खुले वन, 38475 वर्ग किमी. (8. 761%) छितरे वन हैं। पश्चिमी तटीय भाग में तथा असम में सदाबहार वर्षा वन, पश्चिमी हिमालय में कोणधारी वन महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा राजस्थान में शुष्क मरूस्थलीय वनस्पति पाई जाती है।

भारत को तीन मुख्य भू–आकृतिक खंड़ों में बाटा जाता है। इसके उत्तर में विश्व का उच्चतम हिमालय पर्वत तथा इसके पूर्वी एवं पश्चिमी विस्तार तथा दक्षिण में विश्व का प्राचीनतम प्रायद्वीपीय पठार है। इन दोनो के मध्य में गंगा–सिंध का मैदान है। भारत में प्राचीनतम जीवाश्म (fossil) 450 मिलियम वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। 300 मिलियन वर्ष पूर्व भारत का अधिकांश भाग वनाच्छादित था। इस समय भारत विश्व के 12 महाजैव विविधता केन्द्रों में से एक है।

भारत में जैव विविधता उच्च स्तर की है जहां पर विश्व की लगभग 8 प्रतिशत प्रजातिया पाई जाती हैं। पादप समृमिद्ध की दृष्टि से भारत विश्व का दसवां बड़ा देश है। इसकी परिस्थिति में वन आद्रं भूमियां (Wetlands), घास के मैदान, मरूस्थल, समुद्री भाग, आदि हैं, और प्रत्येक में हजारों प्रजातियां है। अभी तक लगभग 2,00,000 प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है, और बहुत सी अन्य प्रजातियों की पहचान करना अभी बाकी है। भारत में जैव विविधत का संक्षिप्त विवरण।

संदर्भ सूची –

1. श्रीवास्तव डॉ. लोकेश : पर्यावरणीय अध्ययनः म.प्र. हिन्दी ग्रंथ आदमी ओवस 2012–13
2. गर्ग डॉ. एच.एस. गर्ग डॉ. अजली : पर्यावरण अध्ययन : विद्याया भवन 620 खजरी बाजार इंदौर 452002 इंदौर
3. शर्मा डॉ. प्रो. राजीव, सिद्दकी डॉ. अनिश : पर्यावरीण अध्ययन, देवी अहित्या प्रकाशन : 26 सुभाष चौक इंदौर (म.प्र.)
4. खुल्लर डी.आर. भूगोल मेग्राव हिल एजूकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमीटेड (न्यू दिल्ली)
5. इन्टरनेट के द्वारा प्राप्त किया गया है।
6. मासिक पत्रिका कुरूक्षेत्र, 2016
7. मासिक योजना पत्रिका, 2015

Status of Female Literacy in Madhya Pradesh

Dr. Rekha Vishwakarma, Assistant Professor,
Department of Geography. M.L.K. (P.G.) College, Balrampur

Abstract:

Education is the birth right of every human. According to census, a person aged seven years and above who can both read and write in any language is treated as "literate".

Literacy is an important demographic element of process. It is essential for human character social and economic development. It contributes to better health. Productivity, High Income capacity and estimated living increased participation in community life. Education includes new ideas for a better building of the society and their personal life style. Female literacy playsan important role in the social advancement and economic development of half the human resources, but also in improving the quality of live at home and outside. Educated female can provide better guidance to all their children. She can also help in the reduction of infant mortality rate and growth of the population. Literate female have the ability to engage themselves in productive work.

The present work is an attempt to study the trends and pattern of female literacy in Madhya Pradesh The study is based on data from the census of India 2001 and 2011.Madhya Pradesh has 60.01% female literacy rate and varies form highest in Bhopal (76.6 Percent) to the lowest in Alirajpur (31.01 %) district.

Key Terms:-

Literacy rate, Status, Trends of literacy, spacial pattern, Literacy level.

Introduction:-

Indian is severely experiencing the inequalities and disparities, we see sharpinequalities of cast, creed, and tripe and rural, urban divided. Gender cuts across all these layers making female and girls of the disadvantaged groups the most deprived members of our society gender inequality in education is highly existent in male and female in particular.

Literacy rate scientific and cultural organizations (UNESCO) defined literacy as the ability to identify, understand interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials.

It is essential for social reconstruction, improvement in quality of life and preparation of manpower for rapid development, Education inculcates new ideas for betterment of the society in particular nation in general. The high literacy rate in one of the very significantly qualitative indicators of social development associated to the economic development.

Objectives:-

The main objective of the present study is to attempt an analysis of the literacy level in the state. The three fold objectives of the present are as follows:-

(i) To examine the literacy rate of female at national level and state level.
(ii) To know the district wise literacy level of female in M.P.
(iii) To analysis the spatial pattern of literacy rate (district level) 2011.

Data Base And Methodology:-

This research paper is based on secondary source i.e. census of India 2001 and 2011. The data was analyzed by percentage and was graphically represented. Provisional census data (2011) has

been used to compare the literacy of the study area. The choropleth method has been used to present the special pattern of female literacy during the period of study. The data for the following analysis has been obtained for census of India 2001-2011.

Study Region:-

Madhya Pradesh is the second largest state of the country with the area of 30825 Km^2, constituting 9.381 of total geographical area of the country. It lies between latitude of 21^0 17' N to 26^0 52' N latitude and between 78^0 08' E to 82^0 49' E longitude. The physiologically the state can be divided into four regions. Gwalior, Malwa, Satpura and Vindhyan range. The annual temp range from 22.5^0c to 25.0^0c.

Map-01

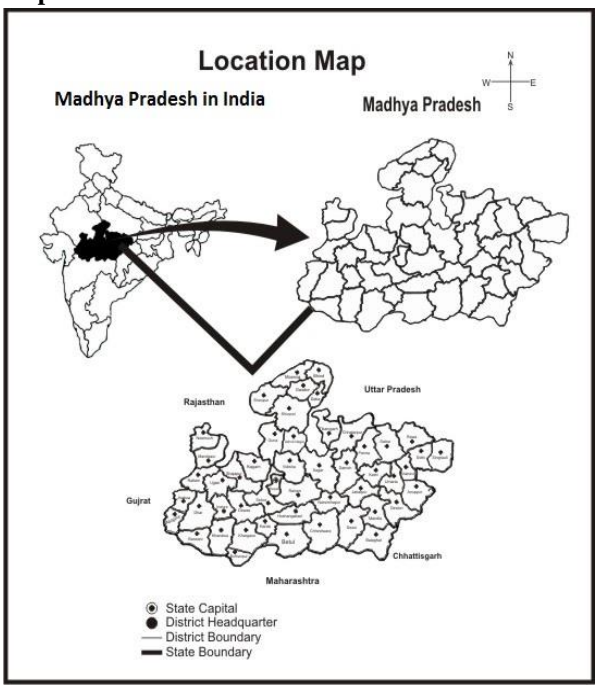

The shares its boundaries with Rajasthan and Uttar Pradesh in the North, part of Rajasthan and with Gujarat in the West on the Southern part of the state Madhya Pradesh lie the state Maharashtra. The entire eastern border of the State is bounded by the state of Chhattisgarh.The total population of the State 72597565 (According to census year 2011) rural population 72.379 and Urban Population 27.631. The population density is 236 people per Sq. Km.

According 2011 census 50 district, 342 Tehsil, 476 City and 54903 Village of the study area.

Result, Discussion and Analysis:-

As per the provisional figures of census 2011 in India 77, 84, 54,120 persons have been counted as literacy rates. Among are literacy rates 33, 42, 50,358 are females literacy rate among.

Although the study area Madhya Pradesh State witnesses increasing trend in literacy. According to census 1981, 1991, 2001 and 2011 in Madhya Pradesh state there were 16.0, 29.4, 50.3 and 60.0 % female literacy respectively.

Table No. 01
Growth of Female Literacy (1981-2011)

Census Year	India		Madhya Pradesh	
	Total	Female	Total	Female
1981	43.6	29.8	38.6	16.0
1991	52.2	36.3	44.7	29.4
2001	64.8	53.7	63.7	50.3
2011	74.0	65.5	70.6	60.0

Source: -Census of India.

The females in Madhya Pradesh as well as India are considered as housewives. There is no opportunity for them to participate in the economic structure. Added to this the factors are general poverty prevalence for early marriage and prejudices against their mobility. All of which have kept the female in Madhya Pradesh for behind their male counterparts in matter of literacy.

Fig. 01

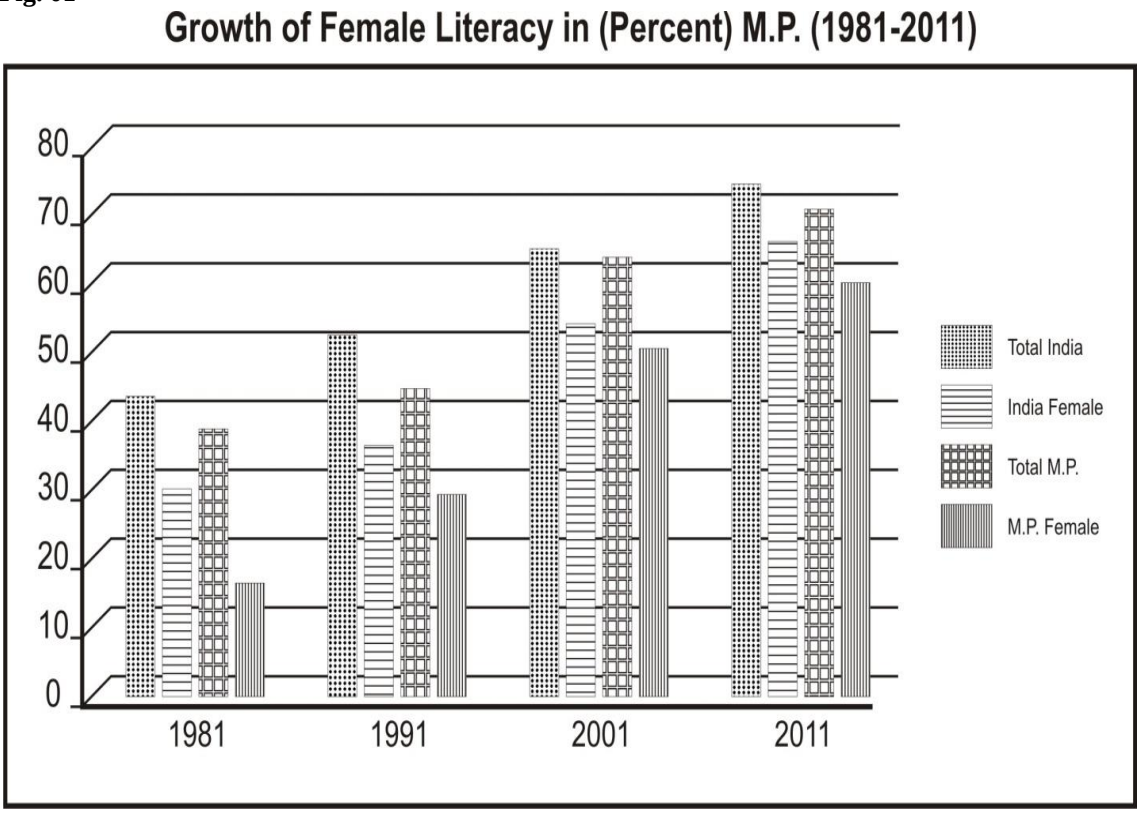

Amidst a host of social economic factors the type of economic degree of urbanization standard of living. Status of women and value system play decisive role in governing the rate of literacy.

Status of Female Literacy rate 2011:-

The study area has continued its inexorable march in (9.9%) improving the female literacy rate by recording a jump of 50.3 % in 2001 to 60.6% in 2011. The study area has 60.0% female literacy rate and it varies from highest in Bhopal (76.6%) to the lowest in Alirajpur (31.1%). The special pattern of very high female literacy rate in five district as Bhopal (76.6%), Jabalpur (75.3%), Indore (74.9%), Balaghat (69.7%) and (68.3%) Gwalior district in the state. The high and moderate female literacy rate area broad region of the state and low and very low female literacy rate in two small regions one lies in Northern part and second lies in South western part of the state.

Table No. 02
Female Literacy 2001-2011

	Total			Rural Literacy			Urban Literacy		
	2001	2011	Change	2001	2011	Change	2001	2011	Change
Sheopur	29.1	44.5	15.1	24.6	41.0	16.4	52.2	62.4	10.2
Morena	46.2	57.6	11.4	41.6	54.3	12.7	62.3	67.7	5.4
Bhind	55.2	64.0	8.8	53.0	61.8	8.8	62.3	69.9	7.6
Gwalior	56.2	68.3	11.9	34.4	52.5	18.1	69.9	77.2	7.3

Datia	56.6	60.2	3.6	53.5	56.9	3.4	68.0	71.1	3.1
Shivpuri	40.7	49.5	8.8	35.7	45.1	9.8	63.7	69.2	5.5
Teekamgarh	41.0	50.7	9.7	37.3	47.2	9.9	57.6	67.0	9.4
Chhatarpur	39.3	54.3	15.0	32.3	48.8	16.5	62.8	72.3	9.5
Panna	48.0	55.6	7.6	45.1	52.9	7.8	66.7	73.5	6.8
Sagar	54.4	67.7	13.3	45.9	61.7	15.8	73.6	81.3	7.7
Damoh	47.3	59.9	12.6	41.4	55.2	13.8	71.5	78.1	6.6
Satna	51.0	63.4	12.4	46.7	59.8	13.1	67.8	76.4	8.6
Rewa	47.6	62.5	14.9	44.2	59.8	15.6	64.9	75.6	10.7
Umariya	44.5	56.1	11.6	41.4	52.8	11.9	60.2	71.4	11.2
Neemuch	49.0	57.3	8.3	41.8	50.2	14.4	67.4	74.2	6.8
Mandsaur	54.7	58.3	3.6	50.9	53.5	2.6	71.1	76.3	5.2
Ratlam	54.3	56.5	2.2	45.9	47.1	1.2	72.5	77.6	5.3
Ujjain	51.9	61.4	9.5	48.8	51.1	2.7	72.3	77.0	4.7
Shajapur	57.4	56.4	-1.0	55.1	52.6	-2.5	67.2	71.8	4.6
Dewas	45.0	58.3	13.3	36.8	51.6	14.8	66.3	74.3	8.6
Dhar	38.6	49.7	11.1	33.6	44.4	10.8	64.0	72.9	8.9
Indor	64.8	74.9	10.1	39.8	57.0	17.2	75.2	81.1	5.9
Khargaon	50.6	53.7	3.1	47.1	49.3	2.2	68.7	76.4	7.7
Badwani	32.0	43.1	11.1	26.0	37.9	11.9	64.7	71.4	6.7
Rajgarh	37.1	49.8	12.7	32.3	45.5	13.2	59.7	69.4	9.7
Vidisha	47.4	61.7	14.3	41.3	50.9	15.6	68.3	76.7	8.4
Bhopal	66.4	76.6	10.2	36.5	58.0	21.5	73.1	80.8	7.7
Sehore	47.4	58.9	11.5	42.6	54.8	12.2	68.2	75.6	6.9
Raisen	61.3	65.1	3.8	53.6	61.8	8.2	68.7	75.9	7.2
Baitul	55.6	61.6	6.0	50.5	56.5	6.0	77.4	82.4	5
Harda	54.1	64.3	10.2	48.1	59.2	11.4	74.9	82.6	7.7
Hoshangabad	57.8	67.0	9.2	48.8	60.0	11.2	76.9	81.8	4.9
Katni	48.2	62.5	14.3	41.3	57.7	16.4	73.0	80.5	7.5
Jabalpur	65.9	75.3	9.4	49.7	63.1	13.4	77.6	83.8	6.2
Narsimhpur	68.2	67.6	-0.6	56.7	64.2	7.5	77.5	82.4	4.9
Dindori	38.2	53.5	15.3	36.6	52.3	15.7	70.8	78.9	8.1
Mandla	45.5	57.2	11.7	41.7	53.6	11.9	77.9	82.3	4.4
Chhindwara	54.6	63.4	8.8	48.3	57.7	9.4	73.4	80.8	7.4
Shivni	53.8	64.1	10.3	50.8	61.3	10.5	79.0	84.6	5.6
Balaghat	57.2	69.7	12.5	54.7	67.8	13.1	74.0	80.8	6.8
Guna	41.2	52.5	11.3	34.0	46.6	12.6	62.4	69.4	7.0
Ashok Nagar	45.2	54.2	9.0	41.3	50.6	9.3	63.6	69.8	6.2
Sahdol	44.2	58.2	14.0	36.8	53.1	16.3	69.4	77.3	7.9
Anooppur	46.1	57.9	11.8	38.9	52.5	13.6	63.8	72.2	8.4

Seedhi	40.3	55.2	14.9	38.4	53.7	15.3	64.0	71.6	7.6
Singrauli	31.5	49.9	18.4	24.8	45.5	20.7	56.7	67.4	10.7
Jhabua	28.6	34.3	5.7	23.3	29.8	6.5	73.9	77.5	3.6
Alirajpur	22.0	31.0	9.0	18.2	27.1	8.9	67.6	74.0	6.4
Khandwa	48.6	56.5	7.9	42.2	50.6	8.4	73.0	79.6	6.6
Burhanpur	49.5	57.3	7.8	38.4	47.4	9.0	66.3	74.9	8.6
Total	**50.3**	**60.2**	**9.9**	**42.8**	**53.2**	**10.4**	**70.5**	**77.4**	**6.9**

Source:- Census of India.(2011)

Show the literacy rate of study unit reveals that so district has the highest literacy rate of female is reported 76.6% in Bhopal district.

Female literacy rate in M.P. ranges from 31.0 % to 76.6% (according to census 2011) shows there are still wide inter and inter regional this parties in development per. A general analysis at the district level present a this approve picture of female in M.P. Female are equal of higher than the state average 60.0%. Now district in M.P. has equal of higher literacy rate of female then the national average 65.5%. Thus scarcity of female though a common feature is however of relatively considerable magnitude in M.P.

Status of Rural Female Literacy 2011:-

Spatial distribution and growth of literacy (district wise) in Madhya Pradesh is so in following table 04. In decade through 2001-2011 the 10.4% below than total rural female literacy rate. The lowest literacy rate is 27.1%. Alirajpur district and Seoni, Bhind, Sagar, Raisen, Jabalpur, Narsinghpur and Balagst district with highest rural female literacy.

District level comparison shows close correspondence of total literacy in Madhya Pradesh. Spatial analysis of district level data represent in table 04. It is intristing that 03 district Alirajpur, Jhabua and Barwani with lowest level of rural female literacy rate below 40%. High level (60.70%) of rural female literacy is accociated with 07 districts. (In seoni, Bhind, Sagar, Raisen, Jabalpur, Narshingpur and Balaghat.) It seems that cast and community in structure of society is also Significant in influencing the level of rural female literacy.

Table No. 03
Level of Development of Total Female Literacy 2001-2011

	2001	2011
Category	**Name of District**	**Name of District**
More then 70 %	-	Indore, Bhopal, Jabalpur
60-70%	Indore, Bhopal, Raisen, Jabalpur, Narsimhapur,	Bhind, Gwalior, Datia, Sagar, Satna, Rewa, Ujjain, Vidisha, Raisen, Betul, Harda, Hoshangabad, Katni, Narsimhapur, Chhindwara, Seoni, Balaghat,
50-60%	Bhind, Gwalior, Sagar, Satna, Mandsaur, Ratlam, Ujjain, Shajapur, Khargaon, baitul, Harda, Hoshangabad, Datia,	Morena, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna, Damoh, Umariya, Neemuch, Mandsaur, Ratlam, Shajapur, Dewas, Khargaon,

	Chhindwara, Seoni, Balaghat,	Sehore, Dindori, Mandla, Guna, Ashoknagar, Shahdol, Anooppur, Sidhi, Khandwa, Burhanpur
40-50%	Morena, Shivpuri, Tikamgarh, Panna, Damoh, Rewa, Umariya, Neemuch, Dewas, Vidisha, Sehore, Katni, Mandla, Guna, Ashoknagar, Shahdol, Anooppur, Sidhi, Khandwa, Burhanpur	Sheopur, Shivpuri, Dhar, Badwani, Rajgarh, Singrauli
30-40%	Chhatarpur, Dhar, Badwani, Rajgarh, Dindori, Singrauli,	Jhabua, Alirajpur
Less then 30%	Sheopur, Jhabua, Alirajpur	-

Source:- Self Calculated

Table No. 04
Status of Development of Urban Female Literacy 2001-2011

	2001	2011
Category	**Name of District**	**Name of District**
More then 80 %	-	Jabalpur, Narsinghpur, Mandla, Seoni, Chindwara, Balaghat, Sagar, Indore, Bhopal, Betul, Harda, Hoshangabad, Katni.
70-80%	Sagar, Damoh, Mandsaur, Ratlam, Ujjain, Indore, Bhopal, Betul, Harda, Hoshangabad, Katni, Jabalpur, Narsinghpur, Dindori, Mandla, Chhindwara, Seoni, Balaghat, Jhabua, Khanwa.	Didhdori, Shahdol, Anooppur, Sidhi, Dhar, Jhabua, Alirajpur, Khandwa, Burhanpur, Gwalior, Datia, Chhatarpur, Panna, Damoh, Satna, Rewa, Umaria, Neemuch, Ratlam, Mandsaur, Ujjain, Shajapur, Dewas, Khargaon, Barwani, Vidisha, Sehore, Raisen.
60-70%	Morena, Bhind, Gwalior, Datia, Shivpuri, Chhatarpur, Panna, Satna, Rewa, Umaria, Neemuch, Shajapur, Dewas, Dhar, Guna, Khargaon, Ashoknagar, Shahdol, Anooppur, Sidhi, Alirajpur, Burhanpur, Badwani, Vidisha, Sehore, Raisen	Guna, Ashoknagar, Singrauli, Sheopur, Morena, Bhind, Shivpuri, Rajgarh, Tikamgarh.
50-60%	Sheopur, Tikamgarh, Rajgarh, Singrauli.	-

Source:- Self Calculated

Table No. 05
Status of Development of Rural Female Literacy 2001-2011

	2001	2011
Category	**Name of District**	**Name of District**
60-70%	-	Seoni, Bhind, Sagar, Raisen, Jabalpur, Narsinghpur, Hoshangabad, Balaghat.
50-60%	Seoni, Balaghat, Narsinghpur, Bhind, Datia, Mandsaur, Shajapur, Raisen, Betul.	Ashoknagar, Neemuch, Ujjain, Dewas, Sidhi, Dhindori, Anooppur, Shahdol, Mandla, Mandsaur, Shajapur, Panna, Gwalior, Morena, Sehor, Damoh, betul, Vidisha, Datia, Bhopal Hardu, Rewa, Satna, Chhindwara, Indore, Katni, Khandwa,.
40-50%	Mandla, Chhindwara, Ashoknagar, Khandwa, Sagar, Jabalpur, Morena, Panna, Damoh, Satna, Rewa, Umaria, Neemuch, Ratlam, Ujjain, Khargaon, Vidisha, Sehor, Harda,Hoshangabad, Katni.	Sheopur, Mandla, Shivpuri, Dhar, Raigarh, Guna, Tikamgarh, Burahampur, Ratlam, Chhattarpur, Khargaon.
30-40%	Dindori, Guna, Shahdol, Anooppur, Sidhi, Bhopal, Raigarh, Indore, Dhar, Dewas, Chhatarpur, Tikamgarh, Shivpuri, Gwalior, Burahampur.	Singrouli, Barwani.
Less then 30%	Alirajpur, Jhabua, Singrauli, Shivpuri, Barwani	Alirajpur, Jhabua.

Source:- Self Calculated

Status of Urban Female Literacy 2011:-

The study area has urban literacy rate which varies from the highest 84.6% in seoni district to the lowest in 62.4% in sheopur district. For the special pattern of urban literacy rate in M.P. has shown by map No of 13 district are very high urban literacy and 28 district have included of high urban literacy rate in the state wise 09 district have included in low and very low urban literacy rate.

The urban female literacy rate of 29 district of study area of above the national average (74.04%) show the following table gives position of district by literacy rate out of 50 district 19 district literacy rate higher than state literacy rate 60.0 %. Wherever 30 districts have literacy rates lover then the state literacy rate.

Table No. 06
Literacy Level (2001-2011)

Top Five district of M.P.				Bottem Five district of M.P.			
2001		2011		2001		2011	
District	%	District	%	District	%	District	%
Narsinghpur	68.2	Bhopal	76.6	Alirajpur	22.0	Alirajpur	31.0
Bhopal	66.4	Jabalpur	75.3	Jhabua	28.6	Jhabua	34.3
Jabalpur	65.9	Indore	74.9	Sheopur	29.1	Barwani	43.1
Indore	64.8	Balaghat	69.7	Singrouli	31.5	Sheopur	44.5
Raisen	61.3	Gwalior	68.3	Barwani	32.0	Shivpuri	49.5

Source:- Census of India.(2011)

Change In Rural Female Literacy (2001-2011):-

The pattern of present changes in rural female literacy at district level study area recorded 10.4 % increase in total literacy of rural female and district level is various between 1.2% and 21.5 % lowest increase of 1.2 % is shared by Ratlam district with over whelming quality Bhopal 21.5 % and Singrouli (20.7%)district registered highest level of growth rate.

Map-2

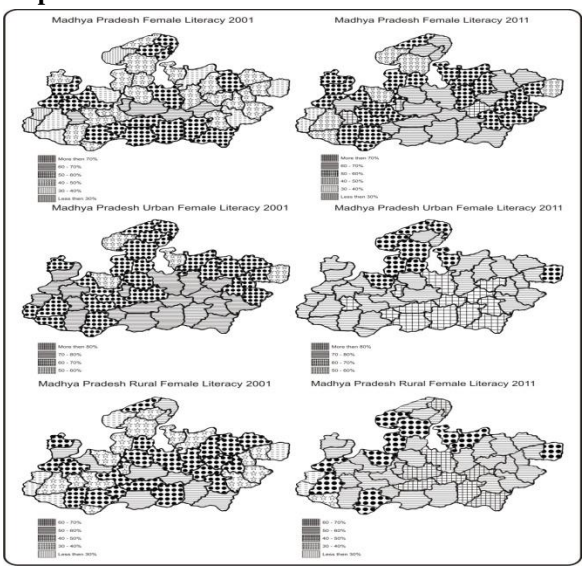

Change In Urban Female Literacy (2001-2011):-

Change in urban female literacy are (3.1 to 10.7%) impressive at district level. Datia (3.1%) district in the observed minimum change in urban female literacy in correspondence to their study area in total literacy 10.7% increase in urban female literacy Singrouli district. Female literacy plays and important role in the development of any area because half of the population of any country is female and without educating them the country progress is not possible.

Change In Female Literacy (2001-2011):-

The district by female literacy rates of 1991, 2001 and 2011 along with decadal change during 2001-2011 districts Narsinghpur which occupied the first position in female literacy in 2001 has slipped down to the 7th position in 2011. Similarly Raisen, Ujjain and Shajapur district have slipped from fifth, six and eight position in 2001 to ninth nintheenth and thirteenth position in 2011. Respectively on the other hand Balaghat district has improved form the 9th position in 2001 to 4th position in 2011, Similarly Gwalior and Sagar district has moved forward from the 11th and 16thposition 2001 to the 5th and 6th position in 2011 respectively.

Concluding Observation:-

It may be concluding that there is an increase in literacy rate in the state since in independence but it is significant in comparison to

other state of Union of the country. There are wide gaps between female urban and rural literacy rates. In rural area parents discriminate the boys give education. Poverty also compels the parents discriminate the girls preferring the boy to give education. Poverty also compels the involve their children to sundry work rather than sending them to schools. Therefore in order to achieve the goal of universalization of education, more stress should be given for female literacy.

References:-

1. ChauhanAlok (2011):Spato temporal Dimension of female literacy in Hanumangarh district (Rajasthan): Indian research Journal of social sciences Vol-21, No 1, P.P. 199, 204.
2. Ghosal G.S. (1964): Literacy in India: A Interpretative study, rural sociology, 29(3): P.P. 261-277.
3. Ghosal G.S. (1979): Spatial per spectate on literacy in India population geography volume -1 No. 1&2, P.P. 41-67.
4. Moitra-Kajal and KiskuSunjit (2015): Literacy pattern of Chhatisgarh state. Journal of Intrigated development and research. Vol-5, No. 1, P.P. 39, 48.
5. Mukharjee A.B. (1968):Speical pattern of literacy in Andhra Pradesh, India in selected papers, Vol-03. Population and settlement Geography 21st IGU, P.P. 181-186.
6. Sangeeta (1989): Progress of literacy in Himachal Pradesh 1961- 1981 an M.Phil dissertation, Dept. of Geography. Punjab University, Chandigarh.
7. Sagar P (1989): Male-Female literacy differential in India 1981, Population Geography Vol-11, No. 1&2, P.P. 21-39.
8. Singh VinayPrakash (2014): and RaiGayatri male female differential in literacy in Varanasi city. Indian Reasearch general of social sciences. Vol – 26, No.2, P.P. 171 – 177.
9. Singh Preeti and Tamta Prem Lal (2011): Rural Population literacy in Hariddwar district. Prospects and petrospect. Indian Reasearch general of social Sciences. Vol-21, No. 1, P.P. 186-190.
10. Siddique Mohammad (1977): The Geography of literacy in Uttar Pradesh, Geographical review of India 39/4 P.P. 388.
11. Sodhi Ram and Dadral B.M. (1995): Progress and pattern of literacy in lahul and spiti, Geographical review of India. Vol-57, No. 3, P.P. 258-273.
12. Vishwakarma Rekha(2014): Progress and Pattern of Literacy in Bahraich district U.P. Progressive research Journal. Vol-4, No.2, P.P. 46-51.
13. Yadav Ranveer Kumar and Pathak Ganesh Kumar (2013): Growth and development level of literacy in Bihar Journal of instigated development and research. Vol-3, No.2, P.P. 19-24.
14. JariyaGhanShyam Prasad & Jain C.K. (2014) Pattern and Differential of Literacy in Madhya Prasad- IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Vol. 09, Issue- 09, Page no. 77-84.
15. Sheikh M.U.D. &Jahan (2013) / Educationia confab. Literacy Rate of Muslim Women in Uttar Pradesh (India). Vol. 02, No. 04, Page no. 52-61.

SATISFACTION AS A BOON TO ADJUSTMENT

Dr. Rashmi Gupta[1]
Asstt. Professor,
Department of Education,
Hawabagh Women's College,
Jabalpur

Mrs. Bhawna Sharma[2]
Asstt. Professor,
Department of Education,
Hawabagh Women's College,
Jabalpur

Dr. Manisha Basal[3]
Asstt. Professor,
Head, Department of Psychology
Hawabagh Women's College,
Jabalpur

INTRODUCTION :

Satisfaction has been set forth as one of the goals of human adjustment as one of the factors to be reckoned within an acceptable concept of efficiency. The essentials of good life comprises in the main, the means of meeting the needs and desires of man that are innate or are at any rate universally present. Satisfaction and dissatisfaction are terms that refer to the way one feels. They are descriptive of the feeling or emotional aspect of experience as distinguished introspectively from its intellectual or rational aspect. It is necessary to avoid setting up a sharp dichotomy between these two kinds of experiences. The feelings are vague and are not localized in a sense organ as are the sensory reactions of seeing and hearing. It is also experienced as a glow of pleasantness or even a warm glow of pleasantness. Dissatisfaction cannot be so readily characterized but it will be recognized as unpleasant. If the preceding modest generalizations are acceptable, adequate justification is at hand for attaching great significance to satisfaction and dissatisfaction in adjustment.

THE NATURE OF SATISFACTION

A glow of satisfaction pervades the day's work and makes events seen to run smoothly, or a cloud of dissatisfaction descends and envelops the worker in a fog of discontent. When one is satisfied, he is satisfied "all over", and when he is dissatisfied, he is dissatisfied "all over". Satisfaction is desirable in itself and that it should be one of the products of work to which every worker is entitled. It has been the expectation, nevertheless, of those concerned with increasing efficiency that decreasing dissatisfaction, and thereby raising the general level of satisfaction, would improve performance. It is a must recognize the need for manifestation by the individual of his nature impulses, his motives and aspirations for self-expression, for ownership, and for recognition in the eyes of his fellows. It is sufficient to recall that the very nature of satisfaction and dissatisfaction is such as to lead to the spread of their influence ones the twenty four hours of the day, no matter how these hours happen to be spent.

SATISFACTION FROM PROPER WORKING CONDITIONS

When employees are given an opportunity to say what makes jobs satisfying or dissatisfying, they rate high the factor of variety, in what they are called upon to do. Also they value the freedom to choose the way in which they shall do any specific thing. It is found too that rest periods introduced at appropriate intervals give satisfaction not so much for the relief of fatigue but for the mere fact of change. Elimination of rest periods or reduction in their length are frequently resented because the sum total of satisfaction is thereby reduced. One

can speak concerning this matter only in rather general terms since individuals differ in respect to what gives them satisfaction as in every other respect. But over and above these differences among individuals there is a sensitivity to the many work variables that contributes to the general undercurrent of feeling, whether it be predominantly satisfying or dissatisfying.

SATISFACTION THROUGH ADJUSTMENT OF CAPACITY

The greatest hope of satisfaction from work lies in putting each person into the type of occupation for which he is best fitted. There must be proper interrelation of the strength of the worker and the strength required of him. The same is true of physical endurance, intellectual capacity and all over other significant traits. Individuals differ in these respects and it is a vital matter to recognize the importance of such differences. The fear has frequently been expressed that, when such adjustments have been made, there will be no one to do the menial tasks. The study of the interests of people with the introduction of machines to take over more and more of the heavy and routine work, there will, doubtless, be enough persons who will get satisfaction from doing the remaining menial tasks. The study of the interests of people of low mentality and of opportunities for employing them in industry has demonstrated that there are many who prefer routine, repetitive and menial activities and who shrink from tasks that are more complex and responsible.

SATISFACTION THROUGH ADJUSTMENT OF PERSONALITY

Every one of the current classifications and descriptions of personality suggests differences among people of a kind which a practical vocational counsellor would need to recognize in advising them. Introverts and extroverts, ascendants and submissive, motor and mental, mechanical and social adjust differently to life situations. Accordingly some persons were inclined toward mental work and others towards manual work, some liked a settled life and others a rowing life, some enjoyed indoor work and others outdoor work, some preferred projects of large scope and others of small scope, some were deliberate and others were impulsive, some tended to concentrate their energy whereas others tended to diffuse there is work may create satisfaction through the opportunity for social intercourse to be one of a group and on terms of good fellowship with its members is a source of great satisfaction. The working environment frequently affords the best opportunity for associating with congenial people.

SATISFACTION FROM SELF-EXPRESSION

Nature does not prescribe just the way in which native urges shall be satisfied. If there is a curiosity drive in human nature it is satisfied in a great variety of ways by different people. For one person it may be appeased by developing a mathematical formula on by searching the heavens for a new star, for another, by prying into a neighbor's private affairs or by solving a cross-word puzzle Education is a potent factor in determining what the means of satisfaction shall be, although limits are set for each individual according to his stature.

It is natural for every human being to be active both in body and mind. Such activity gives satisfaction as long it comforts a person.

THE EVOLUTION OF WANTS

Each man confronts his world with a host of active preferences, being only rarely and incidentally a mere indifferent recipient of external forces. His acts are directed; on the whole, in the interest of these desires and aversions, when he seems to be doing what he does not wish to do, it is usually because of some other want which is controlling him. It would seem that raising the general level of living will not solve the present

difficulty because a satisfaction is a relative and not an absolute quantity. One's bread and cheese is likely to turn sour in the mouth at the sight of another's cake and champagne. There scarcely seems to be the increase in satisfaction of the worker that might have been expected from the elevation of the standard of living during the last fifty to seventy five years.

Two groups were created each of 60 members, in which in the first group it was seen that they are not in any kind of facilities as to keep them satisfied. This was said to be the controlled group. The second group comprised of again 60 member who were kept in the influence of all kinds of facilities. The scores obtained were of the following order.

Group	Numbers of Members	Mean Gain Score	't' Value	Level of Significance
Control Group	60	2.825	8.02	.01
Experimental Group	60	4.35		.05

It is evident from Table- B-3, that the computed 't' value of 8.02 is greater than the table 't' value of 2.65 at .01 level for 78 DF. So the null hypothesis that there will be significant difference between the mean scores of experimental group and control group is rejected. The mean scores of Experimental group has been found significantly greater than the mean score of the control group. So the level of satisfaction in the Experimental group was found to be significantly better than that by the control group.

Reference:

1. Mosso, A.F., "Fatigue (New York, G.P. Putnam's Sons, 1915)
2. Kelley, T.L., Essential Traits of Mental Life (Cambridge, Harvard University Press, 1935)
3. Young, P.T., Motivation of Behaviour (New York, John Wiley and Sons, 1936).

SOCIAL STATUS OF MUSLIM WOMEN IN JABALPUR CITY

Ms. Tamanna Praveen
Asst. Prof., Department of Political Science Hawabagh College, Jabalpur

Women constitute half the resource and half potential in all the societies and empowered women are essential to the democracy.

"Empowerment is an intentional ongoing process centered in the local community, involving mutual respect, critical reflection, caring and group participation, through which people lacking in equal share over those resources.

Table No. 1. Opinion for remarriage of Muslim women

Sr. No.	Opinion for remarriage	Respondents	Percentage
1	Agree	281	75.10
2	Disagree	93	24.90
	Total	**374**	**100**

75.1% women are in favour of remarriage and 24.9% are not favouring it. According to majority of women, Islam allows Muslim women to do remarriage and there is no restriction.

Graph No. 1 – Representation of opinion for remarriage of Muslim women

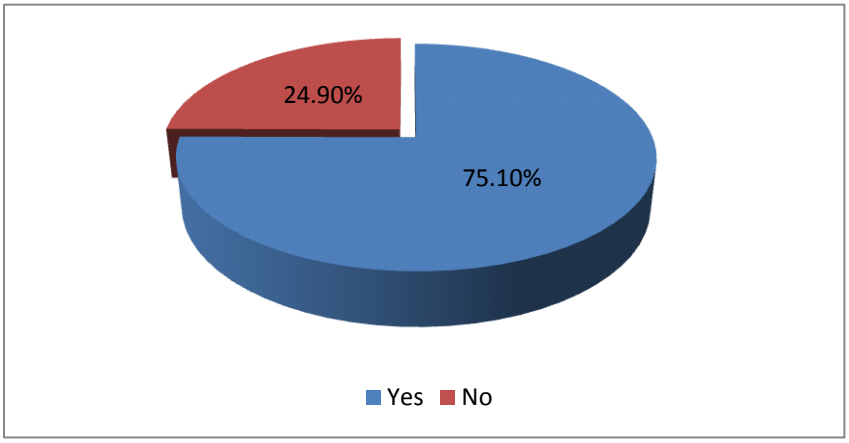

Table No.2. Freedom of movement

Sr. No.	Freedom of Movement to Public Places	Respondents	Percentage
1	Yes	125	33.4
2	No	249	66.6
	Total	**374**	**100**

66.6% women have no freedom to move freely in public places where as 33.4% respondents are able to move and enjoy freely.

Graph No. 2 – Representation of freedom of movement

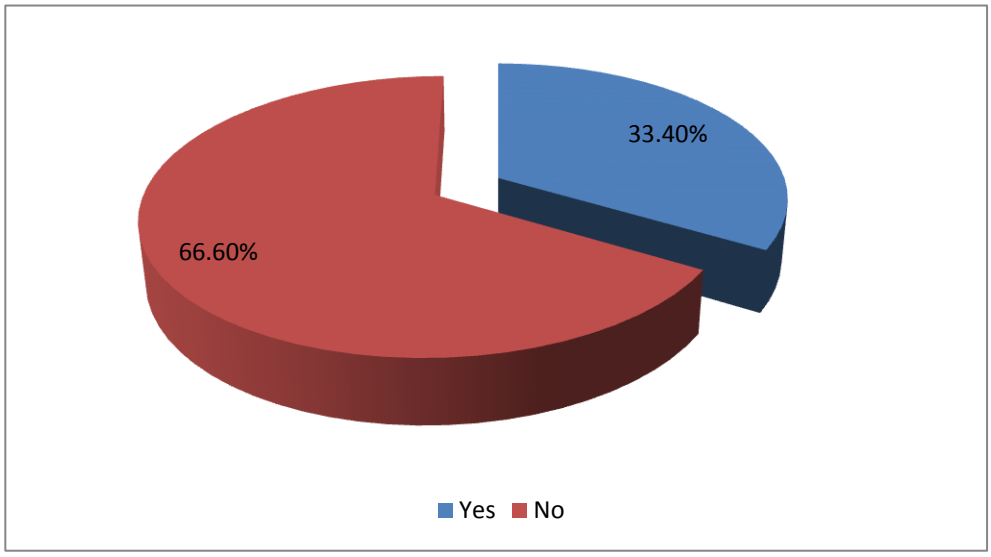

CONCLUSION :- In Jabalpur city 75% Muslim women are in favour of remarriage as they feel that male are the supporters and care taker of the women. They also connect this issue with the Islamic principles, according to Islam there is right to women to remarry, it favours companionship. Whereas 25% Muslim women of this area are not in favour of remarriage because as they feel, except doing remarriage women should develop confidence in themselves and try to live a respectful life. 65% Muslim women of this area have no freedom to move in restaurants, market for shopping, or health centres. Only 35% can move but with someone and the situation is same for both educated and working women, they have no right to move freely. Here also we can say that Muslim women of Jabalpur City are not socially empowered.

REFERENCES :-

1. Mondal, S.R., Rural Muslim Women: Role and Status, Northern Book Centre, New Delhi, 2005.
2. Lemu, Aisha, and Fatima Heeren, Woman in Islam, Crescent Publishing Co., Islamic foundation, Europe, 1977.
3. Naik, Dr. Zakir, Rights of Women in Islam Modern or outdated, Adam Publications and Distributers, New Delhi, p. 8.